चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 09 मई–15 मई 2011 | मूल्य 5 रुपये

माओवादियों की दस्तक

पेज-5

हमारे क़दम अडिग और इरादे नेक हैं

पेज-6

पानी पर सबका हक़ है

पेज-7

साई की महिमा

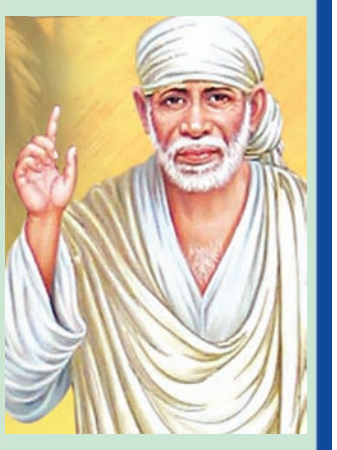

पेज-12

अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं हैं

भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री जेल जा सकता है, नेता गिरफ्तार हो सकते हैं, कभी-कभी तो अधिकारियों को भी कुर्सी छोड़नी पड़ती है. 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कुछ कंपनियों के मालिकों पर केस चला, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनके कर्मचारियों को जेल भेजा गया. अंबानी हों या फिर टाटा, इन बड़े-बड़े उद्योगपतियों में ऐसी क्या ख़ास बात है कि सीबीआई इनके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करने की हिम्मत नहीं कर सकी?

मनीष कुमार

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

आज के ज़माने में अमर सिंह जैसा दोस्त मिलना मुश्किल है. जिनके पास अमर सिंह जैसे दोस्त हों, उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता है. कहां मिलते हैं ऐसे लोग, जो दोस्त के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएं. अमर सिंह ने यही किया, सीना ठोंक कर किया. यह सिर्फ़ अमर सिंह ही कर सकते हैं. जन लोकपाल बिल के नाम पर पूरा देश अन्ना हजारे का साथ दे रहा था. सरकार डरी हुई थी. राजनीतिक दल ख़ामोश थे. नेता मीडिया से दूर भाग रहे थे. ऐसे में धारा के विरुद्ध अमर सिंह की ज़बरदस्त इंट्री होती है. उन्होंने एक ही झटके में पूरे आंदोलन की हवा निकाल दी. अमर सिंह के आरोपों से किसी का भी मतभेद हो सकता है, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद तो देनी ही पड़ेगी. अमर सिंह ने दोस्ती निभाई है. अमर सिंह का मक़सद प्रशांत भूषण और शांति भूषण को लोकपाल बिल तैयार करने वाली कमेटी से बाहर करना नहीं था. उनका एजेंडा यह था कि वह अदालत पर ऐसा दबाव डालें, ताकि 2-जी घोटाले में उनके दोस्त अनिल अंबानी पर कोई कार्रवाई नहीं हो, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो. अमर सिंह की वजह से अनिल अंबानी का नाम सीबीआई की चार्जशीट में नहीं है. अमर सिंह का अपने दोस्त अनिल अंबानी पर यह ऐसा एहसान है, जिसे वह कभी भी चुका नहीं सकते.

मज़ेदार बात यह है कि जब उन्होंने शांति भूषण और प्रशांत भूषण पर हमला किया तो लोगों को लगा कि वह कांग्रेस में शामिल होने के लिए कोई चाल चल रहे हैं. किसी को अमर सिंह की चाल की असलियत की भनक तक नहीं लगी. उनकी निगाहें कहीं और थीं और निशाना कहीं और था. अमर सिंह ने एक आडियो सीडी का हवाला दिया और जन लोकपाल बिल बनाने वाले दो क़ानूनविदों को बेनक़ाब करने की कोशिश की. अमर सिंह का प्रशांत भूषण पर मुख्य आरोप यह था कि शांति भूषण इस टेप में यह कहते हुए पाए गए कि उनके रिश्ते जस्टिस जी एस सिंघवी से अच्छे हैं, अच्छा मैनेज करते हैं. ऐसे लोग भ्रष्टाचार से कैसे लड़ेंगे? इन्हें लोकपाल बिल बनाने वाली कमेटी से बाहर रखना चाहिए. अमर सिंह के बयानों से ऐसा लगा कि वह भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन करने वाले नेताओं को आईना दिखा रहे हैं. अमर सिंह की चाल को मीडिया भी नहीं समझ सकी. सीडी असली है या नकली, बात यहीं पर आकर टिक गई. प्रशांत भूषण दुनिया को समझाने में लग गए कि किस तरह यह सीडी नकली है. उनके वाक्यों को अलग-अलग करके जोड़ा गया है. कांग्रेस पार्टी की भी समझ में नहीं आया कि अमर सिंह क्या करना चाहते हैं. अमर सिंह के बयानों से यह धारणा बन गई कि वह कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं. इसलिए वह कांग्रेस के बचाव में अन्ना हजारे और लोकपाल बिल के लिए आंदोलन कर रहे उनके सहयोगियों पर आरोप लगा रहे हैं. यदि अमर सिंह इतने ही साधारण व्यक्ति होते तो शायद इस बुलंदी पर नहीं पहुंच पाते.

नोट करने वाली बात यह थी कि अमर सिंह अपनी प्रेस कांफ्रेंस में लगातार जस्टिस सिंघवी का नाम ले रहे थे. वह जस्टिस सिंघवी का नाम क्यों लगातार ले रहे थे? अमर सिंह और जस्टिस सिंघवी का रिश्ता क्या है? समझने वाली बात यह है कि जस्टिस सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले के जज हैं. इस मामले में देश की बड़ी-बड़ी टेलीकाम कंपनियां फंसी हुई हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मंत्री ए राजा का इस्तीफ़ा हो चुका है. इस मामले से अनिल अंबानी का नाम भी जुड़ा हुआ है. मामला जस्टिस सिंघवी की अदालत में था, इसलिए अमर सिंह ने यह आडियो टेप जारी करके उन पर दबाव बनाने की कोशिश की. वह एक तीर से दो निशाने लगा रहे थे. इसके अलावा जस्टिस सिंघवी से उनका पुराना हिसाब-किताब भी था.

नौ फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक घटना घटी. वहां अमर सिंह की जमकर खिंचाई हुई. अमर सिंह 2006 के फोन टैपिंग मामले में सोनिया गांधी पर लगाए गए आरोप वापस लेना चाहते थे. सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए अमर सिंह ने कोर्ट में कहा था कि सत्ताधारी दल अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन अब वह इस आरोप को वापस ले रहे हैं. कोर्ट में उनके वकील कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी थे. इनके सामने दो जज थे, जस्टिस जी एस सिंघवी और जस्टिस ए के गांगुली. अमर सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दलील दी कि उन्होंने अपनी निजी जानकारी और समझ पर यह आरोप लगाए थे, पर अब पता चल रहा है कि सब कुछ फ़र्ज़ी है. इस पर जस्टिस सिंघवी ने कहा कि जब आप व्यक्तिगत जानकारी कहते हैं तो इसका मतलब ऐसी जानकारी से होता है, जो आपको व्यक्तिगत तौर पर मालूम हो और यह समय के साथ बदल नहीं सकती. न्यायालय ने कहा कि अगर वह आपकी व्यक्तिगत जानकारी थी तो उसे आप ख़ुद झुठला नहीं सकते. अदालत ने यहां तक कह दिया कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी संदेहास्पद है और आपके हलफ़नामे ने अदालत का समय बर्बाद किया है. जस्टिस सिंघवी ने कहा कि अदालत ने आपके मामले की सुनवाई शुरू की. कई साल बीत चुके हैं और आपके कथनों के आधार पर आपके मामले के लिए कई घंटे समर्पित किए गए. हम केवल उन्हीं पर भरोसा करते हैं. जजों ने अभिषेक मनु सिंघवी को कई बार याचिका का वह हिस्सा पढ़ने को कहा, जिसमें अमर सिंह ने कांग्रेस पार्टी और उसकी अध्यक्ष के ख़िलाफ़ आरोप लगाए थे. इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी कुछ परेशान से दिखे. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अदालत को ऐसे व्यक्ति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई क्यों करनी चाहिए, जो साफ इरादे से नहीं आया है. जस्टिस सिंघवी की अदालत में जिस तरह अमर सिंह को जलील किया गया, शायद वह उसे भूल नहीं पाए. अमर सिंह के सामने जब अवसर आया तो उन्होंने हिसाब बराबर करने और अपने प्रिय दोस्त अनिल अंबानी को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

जब अमर सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस की, तब सीबीआई 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले की दूसरी चार्जशीट तैयार कर रही थी. ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि सीबीआई की दूसरी चार्जशीट में कई बड़े-बड़े नामों का ख़ुलासा होगा. अनिल अंबानी, कनिमोझी और टाटा पर भी गाज गिर सकती है. इन लोगों को भी ए राजा की तरह जेल की हवा खानी पड़ सकती है. सीबीआई ने दो अप्रैल को दाखिल 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले की पहली चार्जशीट में

(शेष पृष्ठ 2 पर)

उस्मान बलवा | संजय चंद्रा | विनोद गोयनका | ए राजा | नीरा राडिया | गौतम दोषी

हाल में आई उनकी किताब-द डार्क साइड ऑफ ब्लैक मनी ठीक उसी समय प्रकाशित हुई है, जब देश में भ्रष्टाचार और काले धन की चर्चा जोरों पर है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

बाबुओं के बाबू

पिछले दिनों एक पुराने मित्र के पी सिंह का दिल्ली में देहांत हो गया, जिससे बहुत से वरिष्ठ बाबुओं को आघात पहुंचा. वैसे तो के पी से पहले उनके बहुत से मित्रों का देहावसान हो चुका है, लेकिन उनकी याद में आयोजित कार्यक्रम में शीर्षस्थ बाबू बड़ी संख्या में मौजूद थे. के पी ख़ुद तो कभी ब्यूरोक्रेट नहीं रहे, लेकिन बाबुओं की एक बड़ी संख्या, जो दिल्ली और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में उच्च पदों पर रही, उन्हें हमेशा याद करेगी. भारत के ब्यूरोक्रेटिक पटल पर जिस अंदाज में के पी ने लॉबिंग करने का काम किया, वह आजकल के लॉबिस्टों के लिए एक सपना है. वैसे तो उन्होंने लंबे समय के लिए बिरला, आईटीसी और श्रीराम जैसी कंपनियों के लिए काम किया, लेकिन कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वह किसी मालिक का हुक्म बजा रहे हों. के पी नीति निर्माण प्रक्रिया को बहुत पहले भांप लेते थे, उसका सूक्ष्म विश्लेषण कर लेते थे और इसीलिए उनके आसपास लोगों का, विचारों का, चर्चाओं का और बड़े-बड़े राजनेताओं का जमावड़ा लगा रहता था. उनके जाने से अनौपचारिक सत्ता नेटवर्क के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा शून्य उत्पन्न हो गया है, जिस पर दिल्ली के बाबुओं का सालों तक भरोसा रहा था.

भारत के ब्यूरोक्रेटिक पटल पर जिस अंदाज में के पी ने लॉबिंग करने का काम किया, वह आजकल के लॉबिस्टों के लिए एक सपना है. वैसे तो उन्होंने लंबे समय के लिए बिरला, आईटीसी और श्रीराम जैसी कंपनियों के लिए काम किया, लेकिन कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वह किसी मालिक का हुक्म बजा रहे हों.

खोल दी पोल

सही समय पर सही वार. यह एक पुरानी कहावत है. बी वी कुमार, जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व चीफ हैं, ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है. हाल में आई उनकी किताब-द डार्क साइड ऑफ ब्लैक मनी ठीक उसी समय प्रकाशित हुई है, जब देश में भ्रष्टाचार और काले धन की चर्चा जोरों पर है. उनकी किताब प्रत्याशित रूप से रुचिकर है, क्योंकि कुमार 1958 बैच के अधिकारी हैं और दशकों तक उनका सामना आर्थिक अपराधों के कई मामलों से होता रहा. इस किताब में सरकार के संदेहास्पद पक्ष से संबंधित सूचनाएं आम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, जबकि मंझे हुए बाबुओं के लिए ये सूचनाएं बासी हैं. फिर भी कुमार ने उन पक्षों को उजागर किया है, जिनकी जानकारी जनता को कम ही होती है. मसलन, कैसे कॉरपोरेट हाउस संसद सदस्यों को पैसा देकर निर्णय प्रक्रिया प्रभावित करते हैं. विकीलीक्स के जूलियन असांजे की तरह कुमार भी भारत के काले धन की संख्या 400 बिलियन डॉलर बताते हैं. कुमार ने जिस नकारात्मक व्यवस्था का चित्रण किया है, वह बरबस ही बाकी बाबुओं को सोचने पर मजबूर करेगा.

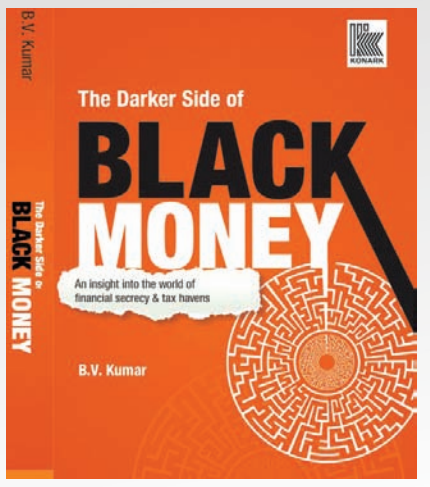

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

टी बोर्ड के लिए तीन नाम

वाणिज्य विभाग के तहत आने वाले कोलकाता टी बोर्ड के चेयरमैन पद के लिए तीन अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध किए गए हैं. इनमें एमजीकेवी भानु, के के मित्तल और महिंदर सिंह शामिल हैं. ये तीनों आईएएस अधिकारी हैं और क्रमश: 1985, 1983 1985 बैच के हैं. यह पद अक्टूबर 2010 के बाद से रिक्त है.

कौन जाएगा श्रीलंका

श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग में निदेशक, डेवलपमेंट को-ऑपरेशन पद के लिए दो नामों पर चर्चा चल रही है. यह मामला विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है. इस पद के लिए 1995 बैच के आईए एंड एएस अधिकारी सुरेश कुमार और 1998 बैच के आईएएस अधिकारी पी मणिवण्णन के नाम पर विचार किया जा रहा है.

सात आईआरटीएस जेएस बनेंगे

वर्ष 1984 बैच के सात आईआरटीएस अधिकारियों के नाम संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष पद के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं. इनमें सोचितो कुमार दास, मुकेश निगम, डी के त्रिपाठी, संजय कुमार मोहंती, विनोद कुमार एवं रघुनाथ माझी शामिल हैं.

शुभ्रा अब डीआईपीपी में

राजस्थान कैडर और 1989 बैच की आईएएस अधिकारी शुभ्रा सिंह का नाम पहले खाद्य एवं जन वितरण विभाग के लिए तय किया जा रहा था, लेकिन अब उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन में संयुक्त सचिव बनाए जाने की बात चल रही है.

प्रसाद डीआईपीपी में जेएस

वर्ष 1984 बैच और कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी डी वी प्रसाद को भारत सरकार में संयुक्त सचिव बनाए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन में संयुक्त सचिव बनाया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो वह रेणु शर्मा की जगह लेंगे.

अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं हैं

पृष्ठ एक का शेष

आरोप लगाया था कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के निजी सचिव आर के चंदोलिया, शाहिद उस्मान बलवा और संजय चंद्रा आदि की साठगांठ के चलते स्वान टेलीकॉम और यूनीटेक ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती गईं. इस चार्जशीट में इनके अलावा डीबी रियालिटी के डायरेक्टर विनोद गोयनका और रिलायंस टेलीकॉम कंपनी के गौतम दोषी, हरि नायर एवं सुरेंद्र पिपरा का भी नाम है. 24 अप्रैल तक सीबीआई को दूसरी चार्जशीट जमा करनी थी. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ देश में जो माहौल बना है और जस्टिस कापड़िया के बर्ताव से यह उम्मीद जगी है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, अब उसे छोड़ा नहीं जाएगा. चाहे वह कितना बड़ा भी नेता हो या फिर उद्योगपति, सबको सज़ा मिलेगी. यही वजह है कि सबकी नज़र जस्टिस सिंघवी, जस्टिस गांगुली और सीबीआई के डायरेक्टर एपीसी सिंह पर थी.

ऐसा क्यों है कि अनिल अंबानी जेल के बाहर हैं, जबकि 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में फंसी छोटी कंपनियों के प्रमुख जेल के अंदर हैं. रतन टाटा के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं हुई. रतन टाटा का नाम नीरा राडिया टेप कांड से विवाद में आया था. अब जबकि इस मामले की कलई खुल गई है तो यही समझा जा सकता है कि 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया. टेलीकॉम कंपनियां, नीरा राडिया और उनके सहयोगी ए राजा को ही टेलीकॉम मिनिस्टर क्यों बनाना चाहते थे. मतलब साफ़ है, इन कंपनियों के मालिकों को यह पहले से ही पता था कि सरकार बनने के बाद इस मंत्रालय में क्या होने वाला है. डीएमके के पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन पहले ही इस महा घोटाले की नींव रख चुके थे. टेलीकॉम कंपनियां यह चाह रही थीं कि कोई ऐसा व्यक्ति टेलीकॉम मिनिस्टर हो, जो उनके रास्ते का रोड़ा न बने. ए राजा को टेलीकॉम मिनिस्टर बनाने के पीछे यही राज़ है. अब सवाल यह उठता है कि क्या यूपीए के दूसरे घटक दल इतने मासूम हैं कि उन्हें इस साजिश की भनक तक नहीं लगी?

अनिल अंबानी से जुड़ा विवाद और भी गहरा है. बताया यह जाता है कि दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलुवालिया का रतन टाटा के प्रति सॉफ्ट कार्नर है, वहीं अंबानी परिवार का सीधा रिश्ता सोनिया गांधी और प्रणव मुखर्जी से है. इस बीच ख़बर यह भी है कि अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी भी अब अपने भाई के बचाव में मैदान में उतर आए हैं. इन सबके बावजूद यह कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता कि अनिल अंबानी बच जाएंगे. इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस कापड़िया का भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जो रवैया है, उससे सारा सरकारी महकमा डरा हुआ है. कोर्ट का इस मामले में कैसा रवैया है, उसका एक उदाहरण यह है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार की आपत्ति को दरकिनार करते हुए 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में वरिष्ठ वकील उदय यू ललित को विशेष सरकारी वकील बनाने का आदेश जारी कर दिया. केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विशेष सरकारी वकील के रूप में ललित की नियुक्ति को लेकर टेक्निकल ग्राउंड पर सवाल उठाते रह गए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया. कोर्ट को लगता है कि देश के सबसे बड़े घोटाले की सुनवाई में ललित अहम भूमिका निभा सकते हैं. यह काम भी जस्टिस जी एस सिंघवी और जस्टिस ए के गांगुली की खंडपीठ द्वारा किया गया. 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में जो कुछ हो रहा है, कोर्ट के आदेश से हो रहा है. सरकार की साख भी दांव पर है. ऐसे में अनिल अंबानी पर कार्रवाई को रोकने का तरीक़ा बस एक ही बचा था और वह यह कि किसी तरह कोर्ट पर दबाव डाला जाए. अमर सिंह ने यही काम किया. शांति भूषण और प्रशांत भूषण की आड़ में उन्होंने जस्टिस सिंघवी पर दबाव बनाने की कोशिश की. अमर सिंह अपनी योजना में कामयाब हो गए. यह संयोग नहीं हो सकता कि सीबीआई की दूसरी चार्जशीट में न तो अनिल अंबानी का नाम आया और न टाटा का.

इसमें कोई शक़ नहीं है कि 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच में सीबीआई और ईडी का रवैया संदेहास्पद है. सीबीआई ने 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया है. सीबीआई के आरोपपत्र में रिलायंस टेलीकॉम के अनिल अंबानी, एस्सार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत रुईया और टाटा का नाम शामिल नहीं है, जबकि इस घोटाले से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं लोगों को हुआ है. शाहिद उस्मान बलवा की स्वान टेलीकॉम और लूप टेलीकॉम वास्तव में रिलायंस कम्युनिकेशंस और एस्सार समूह की मुखौटा (फ्रंट) कंपनियां हैं. आर कॉम 2-जी लाइसेंस पाने की पात्र नहीं थी. उसने स्वान टेलीकॉम का वित्तपोषण किया. अनिल अंबानी की इस कंपनी में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी. इस मामले में सीबीआई ने उन्हें नहीं छुआ, जबकि वास्तव में उनको लाभ मिला था. वहीं टाटा को इसलिए फ़ायदा पहुंचाया गया, क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु के उस एनजीओ को आर्थिक मदद दी, जिसकी निदेशक द्रमुक सांसद कनिमोझी हैं. कनिमोझी का नाम चार्जशीट में आ गया, लेकिन टाटा का नाम आना बाकी है.

चार्जशीट में अंबानी और टाटा का नाम न होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट को बताया गया है कि इस घोटाले से सबसे बड़ा फ़ायदा अनिल अंबानी को पहुंचा है. जिस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है, वह उस समूह की कंपनियों के चेयरमैन हैं. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सीबीआई ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और केवल उनके कर्मचारियों का नाम आरोपपत्र में शामिल किया. मज़ेदार बात है कि यह याचिका एक एनजीओ की तरफ़ से डाली गई है और इसके वकील हैं प्रशांत भूषण और इस मामले की सुनवाई करने वाले जज हैं जस्टिस ए के गांगुली और जस्टिस जी एस सिंघवी. इस बीच आईसीआईसीआई बैंक के एक अधिकारी के बयान से सनसनी फैल गई कि एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी ही 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा के चैक साइन कर सकते हैं. 2006-2007 में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने स्वान टेलीकॉम को 107 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. इसमें 104 करोड़ रुपये एक ही चैक से ट्रांसफर हुए. सीबीआई के मुताबिक़, आईसीआईसीआई के अफसर अमित खोट ने अपने बयान में बताया है कि इतनी बड़ी रकम सिर्फ़ अनिल या फिर टीना अंबानी के हस्ताक्षर से ही ट्रांसफर हो सकती है. इस याचिका पर फ़ैसला होना बाकी है. कोर्ट के फ़ैसले पर ही यह निर्भर करेगा कि अनिल अंबानी और टाटा पर कार्रवाई होगी या नहीं, वे जेल जाएंगे या नहीं. 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 9
दिल्ली, 09 मई-15 मई 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

विशेष संवाददाता
सरोज कुमार सिंह (बिहार)

प्रबंध संपादक (उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)
डॉ. सुनील कौशिक

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-4783999/011-23418962
0120-6450888, 0120-6452888
0120-6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120-4783999
+91 9871194800
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16+4+4+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

देवजी पटेल छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और औद्योगिक प्रदूषण के ख़िलाफ़ अपनी ही सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं.

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़े सवाल

बीते 27 अप्रैल को दिल्ली के वसंत कुंज इलाक़े में एक सभा थी. मौका था दक्षिण भारत के एक स्वामी जी के 81वें जन्मदिन का. मंच पर लालकृष्ण आडवाणी, अशोक सिंहल, प्रवीण तोगड़िया उमा भारती, गोविंदाचार्य और साध्वी ऋतंभरा मौजूद थे. यह दृश्य उस वक़्त की याद दिला रहा था, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले साधु-संत और राजनेता मंच साझा कर रहे थे. इस मंच पर बाबा रामदेव भी मौजूद थे. इन लोगों की मौजूदगी में बाबा रामदेव ने आगामी 4 जून से भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अपने करोड़ों लोगों के साथ देशव्यापी आंदोलन और भूख हड़ताल की घोषणा की. अशोक सिंघल ने भी घोषणा कर दी कि इस आंदोलन में संघ परिवार बाबा रामदेव के साथ है.

बहरहाल, क्या बाबा रामदेव की घोषणा और सिंघल की ओर से उसे समर्थन दिए जाने की घटना और इस वक़्त देश में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ चल रहे आंदोलन को यूं ही छोड़ दिया जाए या इसके निहितार्थ ढूंढे जाएं. क्या इस बात की ज़रूरत नहीं है कि इन आंदोलनों के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष एजेंडे और स्वरूप का विश्लेषण हो. दरअसल, बाबा रामदेव काफी समय से राजनीतिक शुद्धिकरण और काले धन की बात कर रहे हैं. इसके लिए वह देश भ्रमण भी कर रहे हैं और अब आंदोलन की घोषणा भी कर दी है. लेकिन पहला सवाल तो यही उठता है कि जिस मंच से बाबा ने यह घोषणा की, वहां आडवाणी, सिंहल, उमा भारती और प्रवीण तोगड़िया क्या कर रहे थे. अगर इस सवाल को उलट दें तो यहां बाबा रामदेव क्या कर रहे थे?

ख़ैर, इसका जवाब बाबा दें या न दें, लेकिन एक सवाल इस देश की जनता उन तमाम लोगों से पूछना चाहती है जो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं. भ्रष्टाचार जब एक विचार की शक्ल अख्तियार कर ले तो फिर यह गिन पाना मुश्किल हो जाता है कि इसके सिर कितने हैं, चेहरे कितने हैं. ऐसे में जब बाबा रामदेव यह कहते हैं कि काले धन की वापसी से यह देश अमीर हो जाएगा या अन्ना हजारे यह मानते हों कि लोकपाल से भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा तो उस पर विश्वास कर पाना आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. दरअसल, इस वक़्त देश में तीन ऐसी धाराएं एक साथ चल रही हैं, जो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ ख़ुद को योद्धा साबित करने में जुटी हुई हैं. एक तरफ़ बाबा रामदेव हैं. इनके साथ लोग भी हैं और यह भी कहा जा रहा है कि इन्हें आरएसएस का समर्थन है, लेकिन समस्या यह है कि भ्रष्टाचार का अर्थ इनके लिए सिर्फ़ काला धन है. दूसरी ओर अन्ना हजारे और उनकी टीम यह सोचती है कि अगर इस देश में लोकपाल आ जाएगा तो भ्रष्टाचार अपने आप ख़त्म हो जाएगा. दरअसल, इस टीम के पास प्रतिबद्धता तो है, लेकिन लोग नहीं हैं, संगठन नहीं है. 29 अप्रैल से अन्ना का उत्तर प्रदेश के कई शहरों में घूमने का कार्यक्रम था, लेकिन इस पर इतना विवाद हुआ कि मजबूरन अन्ना को अपना दौरा रद्द करना पड़ा. हालांकि यह कहा गया कि डॉक्टर ने उन्हें चलने-फिरने से मना किया है, लेकिन कारण विशुद्ध राजनीतिक है. मायावती नहीं चाहती थीं कि अन्ना वहां जाकर भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं. दरअसल, अन्ना ने अपने आंदोलन को शुरू से ही नेताओं से दूर रखा और यह उसी का नतीजा है. इस वक़्त देश की सभी पार्टियां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना और उनकी टीम के ख़िलाफ़ एक साथ खड़ी हैं. तीसरी तरफ़ कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं, जो अपने विचारों और कुछ दस्तावेजों के सहारे भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं और लड़ भी रहे हैं. इनमें गोविंदाचार्य, एस गुरुमूर्ति, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हैं. इनके पास विचार की ताकत है. इनके साथ संगठन की ताक़त भी है, लेकिन संगठन सामने आकर समर्थन नहीं कर रहा है. सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनके मुद्दे ऐसे हैं, जिनसे जनता ख़ुद को नहीं जोड़ पा रही है. मसलन, स्वामी और मूर्ति के लिए सोनिया गांधी का विरोध करना ही सबसे बड़ा एजेंडा है. एक ऐसा एजेंडा, जिसे भारतीय मतदाता कब का ख़ारिज़ कर चुके हैं.

भ्रष्टाचार के खिलाफ बह रही इन तीनों धाराओं की अपनी-अपनी समस्याएं हैं. विचार के स्तर पर, विजन के स्तर पर और एजेंडे के स्तर पर. इन तीनों के लिए भ्रष्टाचार के मायने अलग-अलग हैं. भ्रष्टाचार को ये लोग सिर्फ दस सिरों वाला रावण मान रहे हैं और इन्होंने अपनी-अपनी लड़ाई के लिए एक सिर चुन लिया है यानी एक एजेंडे का चुनाव कर लिया है. जबकि हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार रूपी यह रावण सहस्त्र सिरों वाला है. इस सहस्त्र सिर धारी रावण के खात्मे के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है.

दरअसल, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बह रही इन तीनों धाराओं की अपनी-अपनी समस्याएं हैं. विचार के स्तर पर, विजन के स्तर पर और एजेंडे के स्तर पर. इन तीनों के लिए भ्रष्टाचार के मायने अलग-अलग हैं. भ्रष्टाचार को ये लोग सिर्फ़ दस सिरों वाला रावण मान रहे हैं और इन्होंने अपनी-अपनी लड़ाई के लिए एक सिर चुन लिया है यानी एक एजेंडे का चुनाव कर लिया है. जबकि हक़ीक़त यह है कि भ्रष्टाचार रूपी यह रावण सहस्त्र सिरों वाला है. इस सहस्त्र सिर धारी रावण के ख़ात्मे के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है, क्योंकि इन सबकी लड़ाई के पीछे कहीं न कहीं व्यक्तिगत प्रसिद्धि पाने की लालसा भी है, जो इनके आंदोलन को कमज़ोर बना देती है. आख़िर ये लोग 2-जी या 26 लाख करोड़ रुपये के कोयला घोटाले पर हल्ला क्यों नहीं बोलते? महंगाई जैसी समस्या पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? रैली क्यों नहीं करते? क्या एक बड़ा सुख पाने के लिए जनता हज़ारों छोटे-छोटे (असल में बड़े) दु:खों का सामना करती रहे? लेकिन कब तक?

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

छत्तीसगढ़

हवाओं में प्रदूषण का ज़हर

संजीत त्रिपाठी

छत्तीसगढ़ ने राज्य बनने के बाद पिछले दस सालों में ख़ूब तरक्क़ी की है. आज छत्तीसगढ़ की कई योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर सराही जा रही हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के पीडीएस सिस्टम को सभी राज्यों में लागू करने की सलाह दी है, लेकिन दूसरी ओर प्रदूषण के मामले में भी छत्तीसगढ़ धीरे-धीरे अव्वल नंबर पर पहुंचता जा रहा है. राजधानी रायपुर सहित कोरबा व रायगढ़ जैसे शहर, जहां सबसे ज़्यादा उद्योग लगे हुए हैं, प्रदूषण के लिहाज़ से ख़तरनाक होते जा रहे हैं. हवा में प्रदूषण के कण के संबंध में शोध करने वाले रविशंकर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का कहना है कि रायपुर दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन और प्रदूषण निवारण मंडल के आंकड़ों में भी अंतर है. ठंड की तुलना में राजधानी का प्रदूषण स्तर इस समय कम है, लेकिन संयत्रों के आसपास रहने वाले लोगों पर इसका ख़ासा प्रभाव पड़ रहा है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि हाल के सालों में प्रदूषण के स्तर का लगातार बढ़ने का कारण स्पंज आयरन संयंत्र बहुत बड़े कारक हैं. आयरन और कोक के मेल्ट होने के बाद संयंत्रों की चिमनियों से कार्बन डाईआक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड का डिपाजिट निकलना शुरू हो जाता है. साथ ही भारी मात्रा में ब्लैक कार्बन निकलने लगता है. प्रदूषण का स्तर हवा की गति पर निर्भर करता है. हवा की गति तेज़ होने पर प्रदूषण फैलाने वाले पार्टिकल हवा के साथ कई किमी दूर चले जाते हैं, दूसरी ओर गति कम होने पर पार्टिकल जमने लगते हैं. यही वजह है कि ठंड में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक व बारिश में सबसे कम रहता है. इस साल गर्मी के दौरान भी पार्टिकल प्रति माइक्रो मीटर का स्तर काफ़ी अधिक बढ़ गया है. रविशंकर विश्वविद्यालय के रसायन के प्रोफेसर डॉ. खगेश्वर पटेल राजधानी के प्रदूषण स्तर पर शोध कर रहे हैं. उनके अनुसार राज्य बनने के बाद स्पंज आयरन इंडस्ट्री की बाढ़ ने राजधानी को देश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में ला दिया है. हाई थर्मल प्रोसेस से चलने वाले इंजन, बर्निंग यूनिट, इंडस्ट्री व स्टील प्लांट से पीएम-10 व पीएम 2.5 माइक्रो मीटर के डस्ट पार्टिकल निकलते हैं. ठंड के दिनों में हवा की गति काफ़ी कम हो जाती है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक़ ठंड में दो किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, इस वजह से धूल के कण हवा में अधिक दूर तक नहीं जा पाते हैं. साथ ही धुंध होने के कारण यह कण उसमें लिपटे रहते हैं. इस वजह से ही पीएम-10 का स्तर 600 से अधिक हो जाता है. यह मानने में कोई हिचक नहीं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के क़ाबिज़ होने के बाद से अर्थात 2003 के बाद से ही यहां औद्यौगिक प्रगति ने तेज़ रफ्तार पकड़ी है. भाजपा शासन के इन 7 वर्षों में यदि उद्योग के क्षेत्र में ज़बर्दस्त प्रगति हुई है और इस्पात बनाने वाली 20 कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में 427.61 अरब रुपए के निवेश के लिए राज्य सरकार के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन औद्योगिक प्रगति के पीछे का हाल यह है कि रायपुर, कोरबा व रायगढ़ देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं. राजधानी से सटे औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित फैरो एलायज के संयंत्रों की चिमनियां इतनी राख एवं धुंआ उगलती हैं कि आसपास खेतों में महीन काली धूल की मोटी परत जम गई है. किसानी चौपट है और किसान परेशान.

देवजी पटेल छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और औद्योगिक प्रदूषण के ख़िलाफ़ अपनी ही सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार को अब बातों से तौबा करनी चाहिए और प्रदेश को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त करने का कोई ठोस उपाय करना चाहिए. पटेल कहते हैं कि वे पिछले पांच वर्षों से अनवरत औद्योगिक प्रदूषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं, परंतु उनकी अपनी भाजपा सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, जिसकी वजह से प्रदेश के उद्योगपति खुलेआम पर्यावरण के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. पटेल इस बात से भी हैरान हैं कि उनके औद्योगिक प्रदूषण विरोधी आंदोलन के जगज़ाहिर होने के बावजूद न तो कभी मुख्यमंत्री और न ही पर्यावरण मंत्री ने उनसे इस विषय में वार्तालाप करने की ज़रूरत महसूस की, जबकि वे अपनी तरफ़ से सरकार को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर लगाम कसने के लिए समय-समय पर सचेत करते रहे हैं.

चिंता की एक बात यह है कि अब छत्तीसगढ़ की राजधानी ध्वनि प्रदूषण से भी त्रस्त होने लगी है. ख़बरें बताती हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रायपुर को देश के उन 35 शहरों में शामिल किया है, जहां अगले वर्ष रियल टाइम व्यापक शोर निगरानी नेटवर्क तैयार किया जाएगा. यह रायपुर में ध्वनि प्रदूषण की उच्च मात्रा को देखते हुए किया गया है.

इधर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए राज्य शासन के वृक्षारोपण जैसे जनजागरण अभियान में प्रदेश के गिने-चुने उद्योग ही दिलचस्पी दिखाते हैं. अधिकारी बताते हैं कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 14 विभिन्न उद्योग प्रबंधनों को वर्ष 2008 मे सड़कों के किनारे दिए गए 814 किलोमीटर वृक्षारोपण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन उद्योगों ने शुरुआत तो बड़े ज़ोरशोर से की, लेकिन उनका उत्साह केवल 123 किलोमीटर क्षेत्र में पौधे लगाने के पश्चात काफ़ूर हो गया. इससे पहले भी इन्हीं उद्योगों को वर्ष 2006 में सड़क के किनारे 800 किलोमीटर वृक्षारोपण का लक्ष्य दिया गया था, परंतु वे 56 किलोमीटर से अधिक पौधे रोपित नहीं कर पाए. यही हाल वर्ष 2007 का रहा, जब राज्य शासन ने फिर भरोसा जताते हुए इन उद्योगों को 391 किलोमीटर वृक्षारोपण का लक्ष्य दिया, लेकिन वे महज़ 110 किलोमीटर की लंबाई तक ही वृक्षारोपण कर सके. इधर औद्योगिक नीति वर्ष 2009-14 के क्रियान्वयन एवं प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं. राज्य सरकार के वर्ष 2011-12 के बजट में उद्योगों को ब्याज़ अनुदान हेतु 46 करोड़, औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान के लिए 4 करोड़ 50 लाख, नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 20 करोड़ तथा औद्योगिक पार्कों के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय मेला प्रांगण के निर्माण हेतु 10 लाख का प्रावधान किया गया है,

लेकिन पर्यावरण सुधारने के लिए बजट में कितनी रक़म का रखी गई है, यह विधानसभा में बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह उल्लेख नहीं कर पाए. हालांकि राज्य के पर्यावरण को लेकर उनकी चिंता और गंभीरता सर्वविदित है. उनकी मंशा पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते. वहीं राज्य के आवास व पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि प्रदूषण के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और समय-समय पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई करती है. वहीं ईएसपी लगने के बाद भी उद्योगों से काला धुआं निकल रहा है, इस पर उद्योगपति सफ़ाई देते हैं कि ईएसपी चालू व बंद होने के 10 मिनट तक काला धुंआ निकलता है, जबकि राजधानी रायपुर से सटे औद्योगिक इलाक़े उरला-सिलतरा के ग्रामीणों की मानें तो अधिकतर उद्योग शाम सात बजे के बाद से ईएसपी बंद कर देते हैं जो कि सुबह तक बंद ही रहता है. ऐसे में कहां से प्रदूषण रुकेगा. इस मुद्दे पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री ख़ुद कभी-कभी आकस्मिक रूप से औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा करते हैं. कुछ महीने पहले ही उन्होंने ऐसे ही आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्रदूषण फैलाने वाले तीन उद्योगों को बंद करने के निर्देश दिए. श्री मूणत के निर्देश पर पर्यावरण संरक्षण मंडल ने सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेसर्स-देवी आयरन एंड पावर प्रा.लि., मेसर्स- इंडियन स्टील एंड पावर प्रा.लि., चरौदा, और मेसर्स अग्रवाल स्पंज प्रा.लि., को तत्काल उत्पादन बंद करने के आदेश दिए थे.

चिंता की एक बात यह भी है कि अब छत्तीसगढ़ की राजधानी ध्वनि प्रदूषण से भी त्रस्त होने लगी है. ख़बरें बताती हैं कि केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रायपुर को देश के उन 35 शहरों में शामिल किया है, जहां अगले वर्ष रियल टाइम व्यापक शोर निगरानी नेटवर्क तैयार किया जाएगा. यह रायपुर में ध्वनि प्रदूषण की उच्च मात्रा को देखते हुए किया है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि हाल के सालों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने का कारण स्पंज आयरन संयंत्र हैं. आयरन और कोक के मेल्ट होने के बाद संयंत्रों की चिमनियों से कार्बनडाई आक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का डिपाजिट निकलना शुरू हो जाता है. साथ ही भारी मात्रा में ब्लैक कार्बन निकलने लगता है.

feedback@chauthiduniya.com

बात नवल यादव पर ही आकर ख़त्म नहीं होती. राजद के कई मज़बूत नेता वेट एंड वाच वाली स्थिति में हैं. नवल ने तो बस उन नेताओं की भावनाओं को एक आवाज़ दी है.

बिहार

राजद के सिपाहियों की कसमसाहट

नवल किशोर यादव

सरोज सिंह

सभी फोटो–संजय कुमार

राम कृपाल यादव

राम बिहारी सिंह

आलोक मेहता

जय प्रकाश यादव

चुनावी महाभारत में बुरी तरह धराशायी होने के बाद एक संगठित पार्टी के तौर पर राजद की दीवारें कमज़ोर होने लगी हैं. नेताओं की हताशा ने कार्यकर्ताओं को टुकर-टुकर ताकने की स्थिति में ला दिया है. सूबे में बिजली-पानी के लिए हाहाकार मचा है, पर मुख्य विपक्षी दल राजद के नेता सड़क पर निकलना तो दूर, बयानों से भी सरकार पर दबाव बनाने से परहेज कर रहे हैं. तर्क यह है कि जो बोलेंगे या करेंगे, वह पंचायत चुनाव के बाद. अभी कुछ करेंगे तो लोग कहेंगे कि हार से खिसिया कर ऐसा कर रहे हैं. राजद का यह नज़रिया उसके कुछ नेताओं और यहां के लोगों को सही नहीं लग रहा है. आग आज लगी है तो छह महीने बाद पानी डालकर क्या होगा, यह तो राजद के लोग ही बता सकते हैं, पर एक सच्चाई यह है कि पार्टी के इस रवैये से कुछ लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है.

राजद के विधान पार्षद नवल यादव कहते हैं कि पार्टी को बिहार के लोगों की समस्याओं के साथ जुड़ना होगा. बाबा रामदेव पर लालू प्रसाद की टिप्पणी से नवल यादव खासे आहत हैं. उनकी राय में लालू प्रसाद ने फूहड़ बात की है. क्या लालू प्रसाद यह नहीं चाहते कि यादव का बेटा इंजीनियर और डॉक्टर बने. आज जब चांद पर बसने की बात हो रही है तो हम जातिपात के बंधन में बंधकर कैसे रह सकते हैं. सभी को आगे बढ़ने का हक़ है, चाहे वह यदुवंशी हो या फिर कोई और. नवल यादव की राय में लालू प्रसाद पार्टी के रोल मॉडल हैं और अगर वही फूहड़ बातें करेंगे तो पार्टी का क्या होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है. नवल कहते हैं कि हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और ईमान एवं ज़ुबान गिरवी रखकर राजनीति नहीं करते. पार्टी, राज्य और देशहित में जो बात सही है, उसे हम हर मंच पर बोलते हैं. नवल कहते हैं कि मैं शुरू से राजद का वफादार सिपाही रहा हूं और चाहता हूं कि पार्टी फिर से मज़बूत होकर उभरे तथा बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाए. किसी नए विकल्प पर उनकी राय है कि भविष्य की राजनीति के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है. दिल्ली में बन रहे पार्टी कार्यालय का नाम राबड़ी भवन रखे जाने से भी नवल यादव आहत हैं. वह कहते हैं कि लोहिया भवन या कर्पूरी भवन के बजाय राबड़ी भवन नाम रखने से पार्टी को कितना लाभ मिलेगा, इसका अंदाज़ लगाया जा सकता है.

बात नवल यादव पर ही आकर ख़त्म नहीं होती. राजद के कई मज़बूत नेता वेट एंड वाच वाली स्थिति में हैं. नवल ने तो बस उन नेताओं की भावनाओं को एक आवाज़ दी है. ऐसे नेताओं की सोच है कि समय रहते लालू प्रसाद को अपनी सोच और काम करने का तरीक़ा बदल लेना चाहिए. उन्हें आशा भी है कि बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए लालू प्रसाद ख़ुद को बदलेंगे. लेकिन पंचायत चुनाव के बाद भी अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ऐसे नेता पार्टी का बंधन तोड़ने से भी बाज नहीं आएंगे. इन नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार का मुक़ाबला पुराने ढर्रे पर चलकर नहीं होगा. जदयू-भाजपा की एकता को परास्त करने के लिए राजद को अपना पुराना जनाधार वापस लाना होगा. जो लोग पार्टी से दूर चले गए, उन्हें वापस लाने का वाजिब कारण बताना होगा. युवाओं एवं महिलाओं के लिए ख़ास कार्यक्रम बनाने होंगे. दलितों एवं अति पिछड़ों को बताना होगा कि उनका हित केवल राजद में है.

अगर पंचायत चुनाव के बाद भी राजद पुराने रास्ते पर चलता रहा तो पार्टी में एक बड़ी टूट भी हो सकती है. ऐसे नेताओं की सोच है कि लालू प्रसाद तो अपनी पारी खेल चुके, अगर अब वह नए नेताओं-चेहरों को आगे नहीं करेंगे तो कई नेताओं का राजनीतिक करियर दांव पर लग जाएगा. अब उन नेताओं के आगे आने का समय आ गया है, जिन्होंने राजद के लिए पसीना बहाया है. युवा एवं साफ छवि वाले नेताओं को नई ज़िम्मेदारी देकर राजद को वास्तविक विकल्प बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी. हालांकि सांसद राम कृपाल यादव नेताओं के बीच किसी भी तरह की बेचैनी से इंकार करते हैं. उनका कहना है कि राजद समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति की आवाज़ है, उसके सभी साथी एकजुट हैं और बिजली-पानी को लेकर जल्द ही राज्यव्यापी आंदोलन शुरू होने वाला है. बिहार और देश के प्रति राजद की जो ज़िम्मेदारी है, उसे हम हर हाल में निभाएंगे. नवल यादव के संबंध में उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी फोरम में अपनी बात रखनी चाहिए थी. वैसे उनका मामला पार्टी अध्यक्ष के पास है. राजद प्रवक्ता राम बिहारी सिंह कहते हैं कि लालू प्रसाद बिहार की राजनीतिक स्थिति से अवगत हैं और उचित समय पर उचित निर्णय लेने में सक्षम हैं.

इस बात में कोई शक नहीं है कि राजद की सबसे बड़ी ताक़त लालू प्रसाद हैं, लेकिन पार्टी में बहुत सारे ऐसे क्षत्रप रहे हैं, जो उनकी ताक़त को कई गुना बढ़ाकर उन्हें सुपर पावर बनाते रहे हैं. इनमें शहाबुद्दीन, फातमी, जगदानंद सिंह, रघुवंश सिंह, सीताराम सिंह, जय प्रकाश यादव, शकुनी चौधरी और आलोक मेहता का नाम लिया जा सकता है. इनके अलावा भी कई नेता हैं, जो राजद की बुनियाद को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर मज़बूत करते रहे हैं. आज के संदर्भ में बात की जाए तो राजद के उक्त सारे नेता सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह हो गए हैं और उन्हें जगाने की ज़िम्मेदारी तो आख़िरकार लालू प्रसाद की है, लेकिन चुनाव के बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा है. नवल यादव जैसे नेताओं का मुखर होना इसी टालमटोल का साइड इफेक्ट है. ऐसे नेताओं की ऊर्जा का पार्टी और राज्य हित में इस्तेमाल करना लालू प्रसाद की ज़िम्मेदारी है. ऐसे नेता इंतज़ार में हैं, लेकिन इंतज़ार का समय अब कम हो रहा है. अगर लालू नहीं बदले तो लगता है कि राजद की तस्वीर ही बदल जाएगी. जो चेहरे आज राजद की शोभा बढ़ा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे किसी दूसरी महफिल में नज़र आएं.

राजद के विधान पार्षद नवल यादव कहते हैं कि पार्टी को बिहार के लोगों की समस्याओं के साथ जुड़ना होगा. बाबा रामदेव पर लालू प्रसाद की टिप्पणी से नवल यादव खासे आहत हैं. उनकी राय में लालू प्रसाद ने फूहड़ बात की है. क्या लालू प्रसाद यह नहीं चाहते कि यादव का बेटा इंजीनियर और डॉक्टर बने.

feedback@chauthiduniya.com

मधु चौहान बहाल

उच्च न्यायालय ने देहरादून ज़िला पंचायत अध्यक्ष पद पर मधु चौहान को बहाल करके प्रदेश सरकार को एक करारा झटका दिया. मालूम हो कि बीती 18 फरवारी को आठ निराधार आरोपों के आधार पर श्रीमती चौहान को बर्खास्त करते हुए राज्य सरकार ने मामले की जांच मंडलायुक्त को सौंप दी थी. मंडलायुक्त ने भी अपनी रिपोर्ट में उन पर लगे तीन आरोपों को सच बताया था. इस पर मधु चौहान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि मधु को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से बर्खास्त किया गया.

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने सरकार के फ़ैसले को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सचिव ने ज़िला पंचायत अधिनियम 1961 में प्रदत्त शक्तियों का सही मायने में इस्तेमाल नहीं किया. विद्वान न्यायाधीश अग्रवाल ने बर्खास्तगी के फ़ैसले को सिरे से ख़ारिज करते हुए मधु चौहान को बहाल किए जाने का आदेश दिया. मालूम हो कि मधु पूर्व विधायक मुन्ना सिंह चौहान की धर्मपत्नी हैं और राज्य में अपनी जनसेवा के लिए विख्यात हैं. उन्होंने अदालती फ़ैसले को सत्य की जीत बताते हुए कहा कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश रची गई थी.

राज कुमार शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस पर गुटबंदी हावी

उत्तराखंड

राज कुमार शर्मा

देश में पांच राज्यों के चुनाव संपन्न होने के साथ ही उत्तराखंड में भी राजनीतिक तपिश तेज हो गई है. राज्य की पांच संसदीय सीटों पर क़ब्ज़े के बाद से ही कांग्रेसी नेताओं की बांछें खिली हुई हैं. आठ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को व्यापक जन समर्थन मिलने की उम्मीद के चलते संगठन में गुटबंदी तेज हो गई है. पार्टी के पांच पांडव के रूप में विख्यात शीर्ष नेता चुनावी समर जीतने की रणनीति बनाने के बजाय एक-दूसरे की टांग खींचने और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे बने रहने में ही अपनी ऊर्जा खपा रहे हैं. मालूम हो कि हरीश रावत, विजय बहुगुणा, इंदिरा हृदयेश, हरक सिंह रावत एवं यशपाल आर्या को राज्य में कांग्रेस के पांच पांडव के रूप में जाना जाता है. सूबे की राजनीति पर पकड़ रखने वालों का मानना है कि अगर उक्त पांचों नेता एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर जाएं तो कोई भी ताक़त राज्य में कांग्रेस को हरा नहीं सकती, लेकिन उसी एकजुटता का सवाल कांग्रेस के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि उक्त पांचों दिग्गज अपनी ढपली-अपना राग वाले रास्ते पर चल रहे हैं. इनमें से हर कोई ख़ुद को मुख्यमंत्री पद का हकदार मान रहा है.

एक ओर पार्टी के पांच पांडव आपसी फूट की वजह से कोई ठोस चुनावी रणनीति बनाते नहीं दिख रहे, वहीं दूसरी ओर जयराम संस्थाओं के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेसी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी इस बार चुनाव में पार्टी के सारथी की भूमिका निभाने का मन बनाए बैठे हैं. जानकारों का कहना है कि पार्टी हाईकमान भी यही चाहता है. ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी की दस जनपथ से निकटता किसी से छुपी नहीं है. ब्रह्मचारी ने ही जयराम संस्थाओं के केंद्रीय प्रांगण में सोनिया गांधी का हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार स्वागत-अभिनंदन करते हुए मंदिरों में उनके प्रवेश का रास्ता प्रशस्त किया था और आरएसएस समेत विभिन्न नेताओं को करारा जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी थी. तभी से ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी को दस जनपथ द्वारा बेहद पसंद किया जाता है. दिल्ली दरबार की पहल पर ही नारायण दत्त तिवारी ने उन्हें प्रदेश के पहले संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति और राज्य संस्कृत अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया था. छात्र जीवन से ही संघ के धुर विरोधी होने के साथ-साथ उनकी समाजसेवा के कारण उन्हें एक निष्ठावान कांग्रेसी के रूप में जाना जाता है.

राज्य में कांग्रेस की वापसी के संकेतों के चलते पार्टी के दिग्गज मुख्यमंत्री बनने की अपनी चाहत छुपा नहीं पा रहे हैं. उधर हाईकमान किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है. बावजूद इसके हर बड़ा नेता यत्र-तत्र-सर्वत्र ख़ुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार साबित करने में जुटा हुआ है. इस काम में हरिद्वार के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री हरीश रावत सबसे आगे चल रहे हैं. उनका मानना है कि हाईकमान ने पिछली बार उनके हक़ पर कुठाराघात करके नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बनवा दिया था, लेकिन इस बार उनका स्वाभाविक हक़ बनता है. मुख्यमंत्री बनने के बाद नारायण दत्त तिवारी को घेरने का काम विपक्ष ने कम, हरीश रावत ने ज़्यादा किया था. दूसरे पांडव टिहरी के सांसद विजय बहुगुणा हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के पुत्र हैं. वह भी सूबे का मुखिया बनने का सपना संजोए बैठे हैं. तीसरे नंबर पर हैं इंदिरा हृदयेश, जो तिवारी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों में शामिल थीं. वह भी हर तरह से ख़ुद को योग्य बताते हुए इस दौड़ में शामिल हैं. चौथे स्थान पर हैं हरक सिंह रावत, जिन्होंने राज्य की भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन में अहम भूमिका निभाकर राहुल गांधी की मंडली के बीच ख़ुद को चर्चित कर लिया है. हरक ख़ुद को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं.

पांचवे पांडव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्या हैं, जिन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी भरोसा जता चुकी हैं. आर्या कांग्रेस के दलित चेहरे हैं. उनके प्रयासों के चलते सूबे में बसपा का हाथी कांग्रेस को नहीं रौंद सका. दलित वोटों के बल पर ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आशा से अधिक सफलता मिली और उसने सभी पांचों सीटें जीत लीं. आर्या इस राज्य की ब्राह्मण-क्षत्रिय राजनीति को संतुलन प्रदान करने वाले नेता सिद्ध हुए हैं. इसीलिए तमाम विरोधों को दरकिनार करके सोनिया ने एक बार पुन: उन पर भरोसा किया है. उनके मन में भी सीएम बनने की चाह हिलोरे ले रही है. आर्या पूर्व मुख्यमंत्री तिवारी की भी पहली पसंद हैं. इसी के साथ सूबे की आधी से अधिक सीटों पर पहाड़ी मानुस और मैदानी मानुस का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है. हरीश रावत भी पहले पहाड़ से चुनकर आते थे, लेकिन इस बार वह मैदानी क्षेत्र हरिद्वार से सांसद चुने गए हैं. उनका मानना है कि वह पहाड़ में जितने लोकप्रिय हैं, उतने ही मैदान में भी हैं. हरीश पहाड़ी-मैदानी जंग में ख़ुद को एक सेतु की भूमिका में मानते हैं. सच तो यह है कि भाजपा द्वारा ऐन मौक़े पर प्रत्याशी बदलने का लाभ कांग्रेस को मिल गया था और हरीश चुनाव जीत गए थे.

कांग्रेस के पांचों पांडव अपनी जनसेवा के लिए विख्यात हैं, लेकिन आपस में एकता न होने के कारण पार्टी की चुनावी तैयारियां परवान नहीं चढ़ पा रही हैं. राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अगर इनमें आपसी समझ स्थापित हो जाए तो कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर सकती है. वहीं भाजपा ने अल्पसंख्यकों एवं दलितों को अपने पाले में खींचने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं. मुख्यमंत्री निशंक ने तो पार्टी की ओर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाने की घोषणा भी कर दी है. कांग्रेस के साथ दलितों के जुड़ाव ने भाजपा हाईकमान के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर दी हैं. भाजपा कांग्रेस के अंदरखाने में फूट डालकर अपना मिशन-2012 सफल बनाना चाहती है. इधर कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को प्रभारी बनाकर उन्हें बेलगाम नेताओं पर काबू पाने का काम सौंप दिया है. चौधरी ने भी देहरादून पहुंच कर पहली बैठक में ही ऐसे नेताओं को संदेश दे दिया है कि वे पार्टी विरोधी गतिविधियों से बाज आएं. समस्या तो यह है कि अभी चौधरी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य में पार्टी के पक्ष में बन रही हवा को बरक़रार कैसे रखा जाए और बड़बोले नेताओं पर अंकुश कैसे लगाया जाए. चौधरी अगर अपनी कोशिशों में कामयाब रहे तो इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय है. लेकिन इसके लिए वरिष्ठ नेताओं को अपनी महत्वाकांक्षा पर काबू पाना होगा, अन्यथा वही होगा कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी.

feedback@chauthiduniya.com

ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी

विजय बहुगुणा

हरीश रावत

यशपाल आर्या

किसान संगठनों की मांग है कि 5000 करोड़ रुपये की आय बीमा योजना लांच की जाए, ताकि किसानों को मूल्य में उतार-चढ़ाव और फ़सल न होने की स्थिति में राहत मिल सके.

उत्तर प्रदेश

माओवादियों की दस्तक

सुरेंद्र अग्निहोत्री

सोनभद्र एवं चंदौसी के बाद अब माओवादी कौशांबी, फतेहपुर, चित्रकूट एवं महोबा आदि जनपदों में भी दस्तक देने लगे हैं. चित्रकूट में जल, जंगल और ज़मीन पर दबंगों के क़ब्ज़े के कारण हालात गंभीर हो गए हैं. सरकार की भूमिका बड़े जमीदारों जैसी हो गई है. सरकार ने सीलन एक्ट को शहरी क्षेत्र में अप्रभावी बनाकर उद्योगपतियों को भूमि लूटने की खुली छूट दे रखी है. बड़े-बड़े उद्योगपति कृषि भूमि को औने-पौने दामों में ख़रीद कर देश की खाद्यान्न सुरक्षा पर चोट पहुंचाने के साथ ही लाखों हाथों को बेरोज़गार करके समाज में अराजकता पैदा कर रहे हैं. बड़े पैमाने पर उपजाऊ भूमि शहरीकरण के नाम पर नीलाम हो चुकी है. दिल्ली से आगरा तक चार टाउनशिप बनाने के नाम पर ज़मीन हड़पने का खेल जिस तरह हो रहा है, वह बहुत ख़तरनाक है. इन क्षेत्रों में नक्सलवाद-माओवाद पनपने की वजहों को समझना बहुत ज़रूरी है. नौकरशाह उद्योगपतियों के नौकर बन गए हैं. यह लूट रोकने के लिए सिर्फ़ भूमि अधिग्रहण क़ानून बदलने से काम नहीं चलेगा.

भारतीय किसान संघ कृषि भूमि और कृषि के प्रति अंतरराष्ट्रीय साजिशों के प्रति जनता को आगाह करने का प्रयास कर रहा है. संघ प्रतिनिधि एम जे ख़ान, देहात मोर्चा के केसरी सिंह गुज्जर एवं राष्ट्रीय किसान संगठन की प्रीति सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की उदासीनता के चलते कृषि क्षेत्र के सामने चुनौती दिनोंदिन बढ़ती जा रही है. केसरी सिंह ने कहा कि डॉ. स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की जा रही है. अगर कृषि भूमि का अधिग्रहण इसी रफ्तार में होता रहा तो लाखों लोग भूख से मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे. अंग्रेजों द्वारा भूमि अधिग्रहण सिर्फ़ सड़क, बांध एवं अन्य सरकारी कामों के लिए होता था, लेकिन भारतीय सरकार अंग्रेजों से भी बदतर साबित हो रही है. वह प्रॉपर्टी डीलर बन गई है. 35 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि ख़त्म कर दी गई. इसे लेकर पिछले तीन माह से आंदोलन चल रहा है. एनसीआर से आगरा तक चार टाउनशिप बनाने का ठेका दिया गया है. इसकी आड़ में किसका भला हो रहा है? इससे किसानों और आम आदमी पर असर पड़ेगा. देश की खाद्यान्न सुरक्षा ख़त्म हो जाएगी. आज एक लाख से अधिक परिवार नोएडा में सड़कों पर आ गए हैं, जो भुखमरी के कारण अपराध करने से भी पीछे नहीं हटते. 40 प्रतिशत युवा कृषि कार्य छोड़ना चाहते हैं. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित साधने के लिए अपने ही लोग देशद्रोही बन गए हैं. वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सीड बिल लाने हेतु लॉबिंग कर रहे हैं, ताकि किसान बीज स्वयं न तैयार कर सकें और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पेटेंट बीजों का उपयोग करें. विदेशी संगठन देश में किसानों के हितों के विपरीत कार्य करने वाले एनजीओ को फंड मुहैया कर रहे हैं. आरटीआई के माध्यम से पता चला कि यूरोपियन यूनियन ने दिल्ली स्थित एनजीओ सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट (सीएसई) को 56 करोड़ रुपये दिए हैं.

किसान संगठनों की मांग है कि 5000 करोड़ रुपये की आय बीमा योजना लांच की जाए, ताकि किसानों को मूल्य में उतार-चढ़ाव और फ़सल न होने की स्थिति में राहत मिल सके. यह मांग उत्पाद का उचित मूल्य मिलने की है, न कि किसी तरह की सब्सिडी, जो किसानों के लिए हानिकारक है. अधिकतम समर्थन मूल्य का विस्तार अन्य फ़सलों तक भी किया जाए, विशेषकर बागवानी की फ़सलों को. किसान प्रतिनिधियों ने 2011-12 के बजट को भी निराशाजनक बताया, क्योंकि इसमें कृषि विकास के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है. उन्होंने कहा कि किसी भी किसान संगठन को बजट से पूर्व या बाद में चर्चा के लिए नहीं बुलाया गया, सिर्फ़ कुछ एमएनसी प्रायोजित किसानों को बुलाया गया. भूमि अधिग्रहण के विरोध के बावजूद सरकार प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम करना नहीं छोड़ रही है. किसानों को अपनी भूमि के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत बाज़ार दर मिलनी चाहिए. यदि भूमि अधिग्रहण बिल किसानों को संतुष्ट करके पारित नहीं किया गया तो टकराव थमने वाला नहीं है. जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई अब आमने-सामने की लड़ाई बनती जा रही है. वनों पर आधारित आदिवासी समुदाय एवं वनटगिया लामबंद होने लगे हैं. उनके वनाधिकारों को मान्यता देने वाला अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी क़ानून-2006 एक जनवरी, 2008 से देश भर में लागू किया जा चुका है. उत्तर प्रदेश में भी सरकार द्वारा इसे लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है. साथ ही लगातार इस विशिष्ट क़ानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को बाधित करने का काम किया जा रहा है. वनाधिकार क़ानून के तहत वन समुदायों को अधिकार सौंपने के बजाय उन्हें जंगल से बेदख़ल किया जा रहा है. वनवासियों द्वारा प्रस्तुत दावों को नियम विरुद्ध तरीक़े से निरस्त किया जा रहा है, सामुदायिक अधिकारों की बात पर एकदम चुप्पी है, लोगों को लघु वनोपज के अधिकार से वंचित किया जा रहा है. जंगल

में अपनी ज़रूरत का सामान लेने गए लोगों को लकड़ी काटने और शिकार का आरोप लगाकर झूठे मुक़दमों में फंसाया जा रहा है. यह वनाधिकार क़ानून का सीधा उल्लंघन है, जिससे देश के विभिन्न वन क्षेत्रों में संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है.

प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2010 में जनपद सोनभद्र में 7000 मुक़दमे वापस लेने की घोषणा की थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर वन विभाग और प्रशासन द्वारा इन सब मामलों में लोक अदालत लगाकर आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत समुदायों को पैसा देकर उनसे अपराध स्वीकार कराया जा रहा है और उनका आपराधिक इतिहास बनाया जा रहा है, जिससे वनाधिकार क़ानून सही ढंग से लागू न हो सके और विभाग एवं प्रशासन की मनमानी चलती रहे. इस जन सुनवाई में ऐसे कई गंभीर मामले जूरी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनमें जनपद सोनभद्र, चंदौली एवं मिर्जापुर में वन विभाग और पुलिस द्वारा आदिवासियों को माओवादी बनाकर उन पर झूठे मुक़दमे दर्ज हुए थे. इन्हीं जनपदों से वनाश्रित समुदाय के विरुद्ध दर्ज क़रीब 10,000 फ़र्ज़ी मामलों की सूची भी जूरी के समक्ष रखी गई. इन मुक़दमों में 80 फ़ीसदी संख्या महिलाओं की है. साथ ही प्रदेश के सात जनपदों के टांगिया गांवों के मामले भी इनमें शामिल हैं. ये गांव आज भी वन विभाग के अधीन हैं, जिन्हें अंग्रेजी शासनकाल में वन लगाने के लिए बंधुआ मज़दूरों की तरह इस्तेमाल किया गया था. ये गांव अभी तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं और इस देश के नागरिक नहीं कहलाते. इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है.

प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा इन गांवों को राजस्व ग्रामों का दर्जा देने का आदेश जारी किए जाने के बाद भी वन विभाग द्वारा अड़ंगा लगाया जा रहा है. जनपद खीरी में जंगलों में रहने वाले कई थारू आदिवासियों पर वन्य जंतुओं का शिकार करने के झूठे मामले दर्ज किए गए और उनमें से कई को जेल भेज दिया गया. वहीं वन विभाग की मिलीभगत से तस्करों द्वारा आएदिन वन्यजीव-जंतुओं का शिकार किया जाता है, लेकिन उस तरफ़ किसी का ध्यान नहीं है. खीरी जनपद की मोहम्मदी तहसील के दिलावर नगर में सरकार द्वारा बसाए गए बाढ़ पीड़ित परिवारों को वन विभाग ने बड़ी बर्बरता के साथ भगा दिया. उनके घरों को आग लगा दी गई, लोगों को पीटा गया और महिलाओं के साथ अभद्रता की गई. यह तब किया गया, जबकि इन परिवारों के पास हाईकोर्ट का आदेश था कि इन्हें उजाड़ा न जाए. इसी तरह पलिया तहसील और खीरी की नेपाल सीमा से जुड़े फिक्सड डिमांड होल्डिंग गांव गौरी फंटा को उजाड़ने के लिए वन विभाग द्वारा पूरा माहौल बनाया जा रहा है, जबकि ये गांव वनाधिकार क़ानून के तहत बसाए जाने चाहिए. मिर्जापुर, चित्रकूट एवं बांदा में भी वनाधिकार क़ानून लागू करने की प्रक्रिया न के बराबर है.

सबसे बड़ी समस्या इन क्षेत्रों में बसे आदिवासी कोल समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा न मिलना है, जिसकी वजह से वनाधिकार क़ानून के अनुरूप उन्हें 75 वर्ष का प्रमाण देने के लिए बाध्य किया जा रहा है. हालांकि प्रदेश सरकार ने 50 साल तक के साक्ष्यों को आधार मानते हुए मालिकाना हक़ देने की बात कही है, लेकिन वन विभाग और ज़िला प्रशासन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और मनमानी पर आमादा है. दिलावर नगर में वन विभाग द्वारा 2007 में घरों व फ़सलों को जलाना, पल्हनापुर टांगियां में वनाधिकार क़ानून की प्रक्रिया को लंबित करना, खीरी के थाना पलिया, ग्राम बसही और चंदन चौकी सीमा क्षेत्र में वन्यजीव-जंतु संरक्षण अधिनियम की आड़ में आदिवासियों का उत्पीड़न, गौरी फंटा गांव को नोटिस, ग्राम ढकिया जनपद पीलीभीत में बेदखली, सहारनपुर-गोरखपुर-महराजगंज-खीरी के टांगियां गांवों को वनाधिकार क़ानून के तहत राजस्व ग्राम का दर्जा न देना, गोंडा जनपद के पांच टांगियां ग्रामों में वनाधिकार क़ानून लागू होने के बाद भी ग्रामीणों के खेतों में गड्ढे खोदना और बंधुआ मज़दूरी प्रथा ज़ारी रखना, चंदौली में गोंड एवं अन्य आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल न करना, मगरदह टोला एवं सत्तद्वारी जनपद सोनभद्र में वन विभाग द्वारा आदिवासियों के घरों-फ़सलों को जलाना, राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच के कार्यकर्ता रामशकल गोंड को माओवादी बताकर जेल भेजना, भैसइया नाला में वन विभाग द्वारा घर-फ़सल जलाना, चित्रकूट में डबल एंट्री, सोनभद्र में वन विभाग और पुलिस द्वारा आदिवासियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुक़दमे लादना आदि मामलों को जूरी के सामने रखने के लिए हज़ारों लोग राजधानी लखनऊ की इस जन सुनवाई में मौजूद थे. ज़ूरी के सदस्य मन्नुलाल मरकाम (रिटायर्ड न्यायाधीश जबलपुर एवं सदस्य, राष्ट्रीय वनाधिकार संयुक्त समीक्षा समिति), रवि किरण जैन (वरिष्ठ अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय), स्मिता गुप्ता (सदस्य, वनाधिकार क़ानून ड्राफ्टिंग कमेटी) एवं मणिमाला (निदेशक, गांधी स्मृति दर्शन, नई दिल्ली) आदि ने जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े इन तमाम मामले सुने और पीड़ितों की बात आगे तक ले जाने का आश्वासन दिया.

दरअसल बात यह है कि बांध, जलाशय एवं सड़क निर्माण और उद्योगों के नाम पर किसानों को भूमिहीन करने का सिलसिला पूरे देश में चल रहा है. आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण नए जमीदारों के रूप में जबरन और छल-प्रपंच से भूमि अधिग्रहीत करके उसे अधिक दामों में बेचने का कार्य कर रहे हैं.

भारतीय किसान संघ कृषि भूमि और कृषि के प्रति अंतरराष्ट्रीय साजिशों के प्रति जनता को आगाह करने का प्रयास कर रहा है. संघ प्रतिनिधि एम जे ख़ान, देहात मोर्चा के केसरी सिंह गुज्जर एवं राष्ट्रीय किसान संगठन की प्रीति सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की उदासीनता के चलते कृषि क्षेत्र के सामने चुनौती दिनोंदिन बढ़ती जा रही है. केसरी सिंह ने कहा कि डॉ. स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की जा रही है.

feedback@chauthiduniya.com

राजा का एक और कारनामा

बहरहाल, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने यह स्टोरी किसी कंपनी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि बीएसएनएल द्वारा फ्रेंचाइजी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करते वक़्त किए गए भेदभाव को सामने लाने के लिए की थी.

चौथी दुनिया को ऑन मोबाइल कंपनी का नोटिस

हमारे क़दम अडिग और इरादे नेक हैं

शशि शेखर

चौथी दुनिया (11 अप्रैल–17 अप्रैल) के अंक में प्रकाशित कवर स्टोरी (शीर्षक–दूरसंचार विभाग में नए घोटाले का पर्दाफाश: राजा का एक और कारनामा) में बीएसएनएल की वैल्यू एडेड सर्विसेज (वीएएस) शाखा में एक घोटाले का खुलासा किया गया था. इस खुलासे के बाद बीएसएनएल वीएएस सर्विसेज देने वाली एक कंपनी ऑन मोबाइल की ओर से एक लॉ फर्म ने चौथी दुनिया के संपादक संतोष भारतीय और संवाददाता शशि शेखर के नाम से एक लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि यह स्टोरी ग़लत है, तथ्य से परे है और इस स्टोरी की वजह से उनके क्लाइंट (ऑन मोबाइल के सीईओ एवं चेयरमैन अरविंद राव) और उनके बिज़नेस को नुक़सान हुआ है. लीगल नोटिस में हमसे इस स्टोरी को चौथी दुनिया की वेबसाइट से हटा लेने, बिना शर्त माफ़ी मांगने और क्षतिपूर्ति के रूप में 10 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है, अन्यथा हमारे ख़िलाफ़ सिविल एवं क्रिमिनल प्रोसिडिंग चलाए जाने की बात कही गई है.

चौथी दुनिया
www.chauthiduniya.com
दूरसंचार विभाग में नए घोटाले का पर्दाफ़ाश
राजा का एक और कारनामा

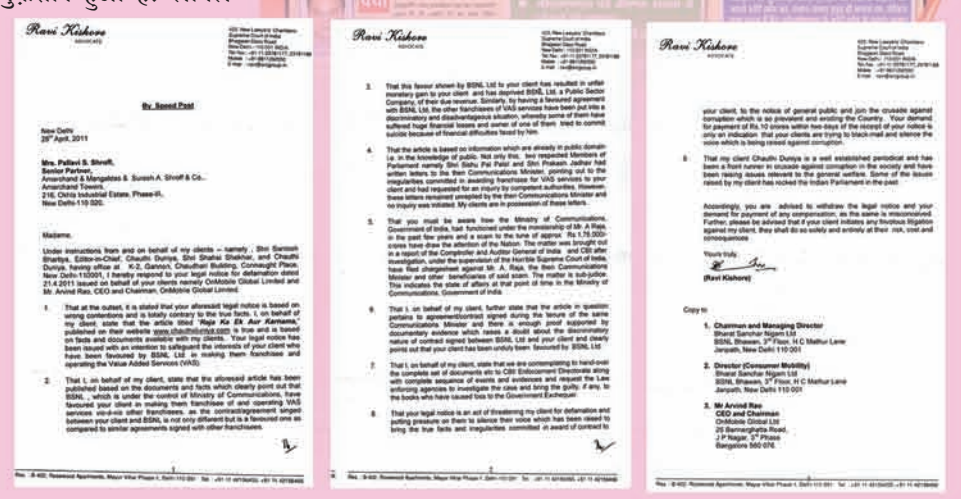
Ravi Kishore

बहरहाल, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने यह स्टोरी किसी कंपनी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि बीएसएनएल द्वारा फ्रेंचाइजी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करते वक़्त किए गए भेदभाव को सामने लाने के लिए की थी. हमारा उद्देश्य किसी कंपनी को बदनाम करने का नहीं था. इस स्टोरी में कहीं भी ऑन मोबाइल कंपनी या इसके सीईओ को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की गई है और न ही इस कंपनी के ख़िलाफ़ कुछ लिखा गया है. नतीजतन, न तो माफ़ी मांगने का सवाल उठता है और न ही स्टोरी को वेबसाइट से हटाए जाने का. चौथी दुनिया हमेशा जन सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता करता रहा है और आगे भी करता रहेगा. फ़िलहाल इस लीगल नोटिस के मद्देनजर हम इस स्टोरी से जुड़े तथ्यों एवं सारे दस्तावेजों से आपको रूबरू करा रहे हैं, ताकि इस आरोप कि स्टोरी तथ्य से परे है, का जवाब दिया जा सके. हमने इस स्टोरी के माध्यम से बीएसएनएल की मनमानी पर सवाल उठाए थे. यह बात प्रमाण सहित बताई थी कि कैसे बीएसएनएल वीएएस शाखा ने एक ही काम (ग्राहकों तक वैल्यू एडेड सर्विसेज पहुंचाने का काम) के लिए अलग–अलग कंपनियों से अलग–अलग करार किया था. यह स्टोरी हमारे पास उपलब्ध दस्तावेजों (जिसमें बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से लिखे गए पत्र, महाराष्ट्र के दो सांसदों द्वारा संचार मंत्री/सचिव को लिखे गए पत्र, बीएसएनएल द्वारा फ्रेंचाइजी कंपनियों के साथ किए गए करार की कॉपी शामिल है) के आधार पर लिखी गई है.

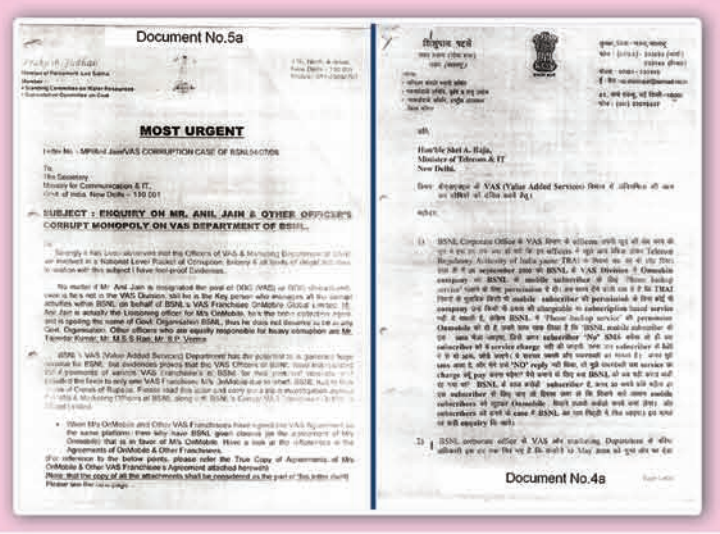
Document No.5a
MOST URGENT
Document No.4a

2004 Agreement

M/s On Mobile	Other Franchisees
The Duration of M/s On Mobile's VAS agreement is of 3 (Three) Years according to the 2nd clause in M/S OnMobile's VAS agreement.	VAS Agreement for other Fran chisees of BSNL is of 1 (one) year.
M/s On Mobile	**Other Franchisees**
The Marketing Clause in the Agreement (PART-1, Clause 13) of OnMobile stated that BSNL and the Franchisee both shall be responsible for the joint marketing, advertising & promotion of the VAS services.	No such support/facility for other franchisees. VAS Franchisee is straightway asked to promotes its Service code all on its own
M/s On Mobile	**Other Franchisees**
In clause 5 'Restriction on 'Transfer of Agreement' states 'However, Franchisee may involve its subsidiary or associate companies to accomplish its obli gations under this agreement, with the written permission of BSNL'	No such support/facility for other franchisees
M/s On Mobile	**Other Franchisees**
PART-1, clause # 7 for 'Delivery of Services'. OnMobile was given a time of 3 (three) months for the commercial launch of their services. 7.1 clause in the PART-1 of Agreement no.200-38/2004-NS	other franchisees have been given 2 months
M/s On Mobile	**Other Franchisees**
clause #1 for 'Financial Condition' it was mentioned that the Payment of the Franchisee will be made within 10 days of the receipt of the verified Bill. 1.4 clause in the PART-2 of Agreement no.200-38/2004-NS	For other franchisee the duration for bill clearance was 30 days.

New VAS Agreement 2008

M/s On Mobile	Other Franchisees
New VAS Agreement, in Feb, 2008. The Duration of Agreement of OnMobile is 2 years'	While the 'The Duration of Agree ment of other is only 1 years'

महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं तथ्य

1. ऑन मोबाइल एवं बीएसएनएल के बीच 8 नवंबर, 2004 को हुए एग्रीमेंट की प्रति (संख्या–200–38/2004 एनएस). इसके मार्केटिंग क्लॉज, बिंदु संख्या 13 में लिखा है कि बीएसएनएल एवं ऑन मोबाइल मिलकर वीएएस सर्विसेज की मार्केटिंग, प्रमोशन, एडवरटाइजिंग का काम करेंगे. जबकि अन्य फ्रेंचाइजी को यह सुविधा नहीं मिली. ज़ाहिर है, ऐसे में इस क़रार और बीएसएनएल की मंशा पर सवाल उठना लाज़िमी है. (एग्रीमेंट की कॉपी चौथी दुनिया के पास है)
2. 5 फरवरी, 2008 को ऑन मोबाइल एवं बीएसएनएल के बीच हुए एग्रीमेंट की प्रति. इसमें 2 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया है. 2008 में ही अन्य फ्रेंचाइजी और बीएसएनएल के बीच हुआ करार सिर्फ़ एक साल के लिए किया गया. सवाल यह है कि बीएसएनएल ने दोहरा मापदंड क्यों अपनाया? (एग्रीमेंट की कॉपी चौथी दुनिया के पास है)
3. 8 जनवरी, 2008 को एक अन्य फ्रेंचाइजी कंपनी के साथ बीएसएनएल का एग्रीमेंट. इस कंपनी के साथ एक साल के लिए एग्रीमेंट किया गया था. (एग्रीमेंट की कॉपी चौथी दुनिया के पास है)
4. पत्र संख्या 200–17/2006 एनएस, दिनांक 22 मई, 2008 को बीएसएनएल डीडीजी (वीएएस) का लिखा पत्र, जिसमें सीबीएसई रिजल्ट सिर्फ ऑन मोबाइल कंपनी के शॉर्ट कोड 12555 के जरिए जारी करने के संबंध में कई टेलिकॉम सर्किलों के सीजीएम को सूचित किया गया. आखिर अन्य फ्रेंचाइजी को यह यह सुविधा क्यों नहीं दी गई? (पत्र की कॉपी चौथी दुनिया के पास है)
5. पत्र संख्या 200–38/2004 एनएस (वोल्यूम–2), दिनांक 6 फरवरी, 2007 को बीएसएनएल के एडीजी (न्यू सर्विसेज) द्वारा बीएसएनएल के सभी सर्किलों के सीजीएम को लिखा गया पत्र. इसमें शॉर्टकोड 12555–––के प्रमोशन/विज्ञापन के लिए कहा गया है. अन्य फ्रेंचाइजी कंपनियों के लिए यह पत्र क्यों नहीं लिखा गया? (पत्र की कॉपी चौथी दुनिया के पास है)
6. महाराष्ट्र (भंडारा) से लोकसभा सांसद शिशुपाल पटले द्वारा तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा को लिखा गया पत्र, जिसमें वीएएस विभाग में अनियमितता की जांच की मांग करते हुए मंत्रालय को सारी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं और जिस पर मध्य प्रदेश के सागर क्षेत्र से सांसद वीरेंद्र कुमार के भी हस्ताक्षर हैं. लेकिन पत्र लिखे जाने के बाद भी न तो जांच हुई और न कोई कार्रवाई हुई. आखिर क्यों? (पत्र की कॉपी चौथी दुनिया के पास है)
7. शिवसेना के लोकसभा सदस्य प्रकाश जाधव द्वारा 4 जुलाई, 2008 को लिखे गए दो पत्र, जिनमें उन्होंने संचार मंत्रालय के सचिव को बीएसएनएल एवं फ्रेंचाइजी कंपनियों के बीच हुए एग्रीमेंट और अन्य अनियमितताओं के बारे में सूचित किया था. मंत्रालय के सचिव ने पत्र मिलने के बाद आखिर कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी, जांच क्यों नहीं हुई? (पत्र की कॉपी चौथी दुनिया के पास है)
8. बीएसएनएल एवं फ्रेंचाइजी कंपनियों के बीच हुए एग्रीमेंट से जुड़े कई पत्र, जिनमें कई स्तर पर बीएसएनएल द्वारा एग्रीमेंट करते वक़्त भेदभाव किए जाने की बात स्पष्ट होती है. (पत्र की कॉपी चौथी दुनिया के पास है)
9. रेलवे टिकट, बीएसएनएल के फोन बिल, अखबारों की कतरन और बिजली के बिल की प्रति, जिसमें बीएसएनएल ने एक ख़ास शॉर्ट कोड का प्रचार किया है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... हम नहीं बदलेंगे – वामदल

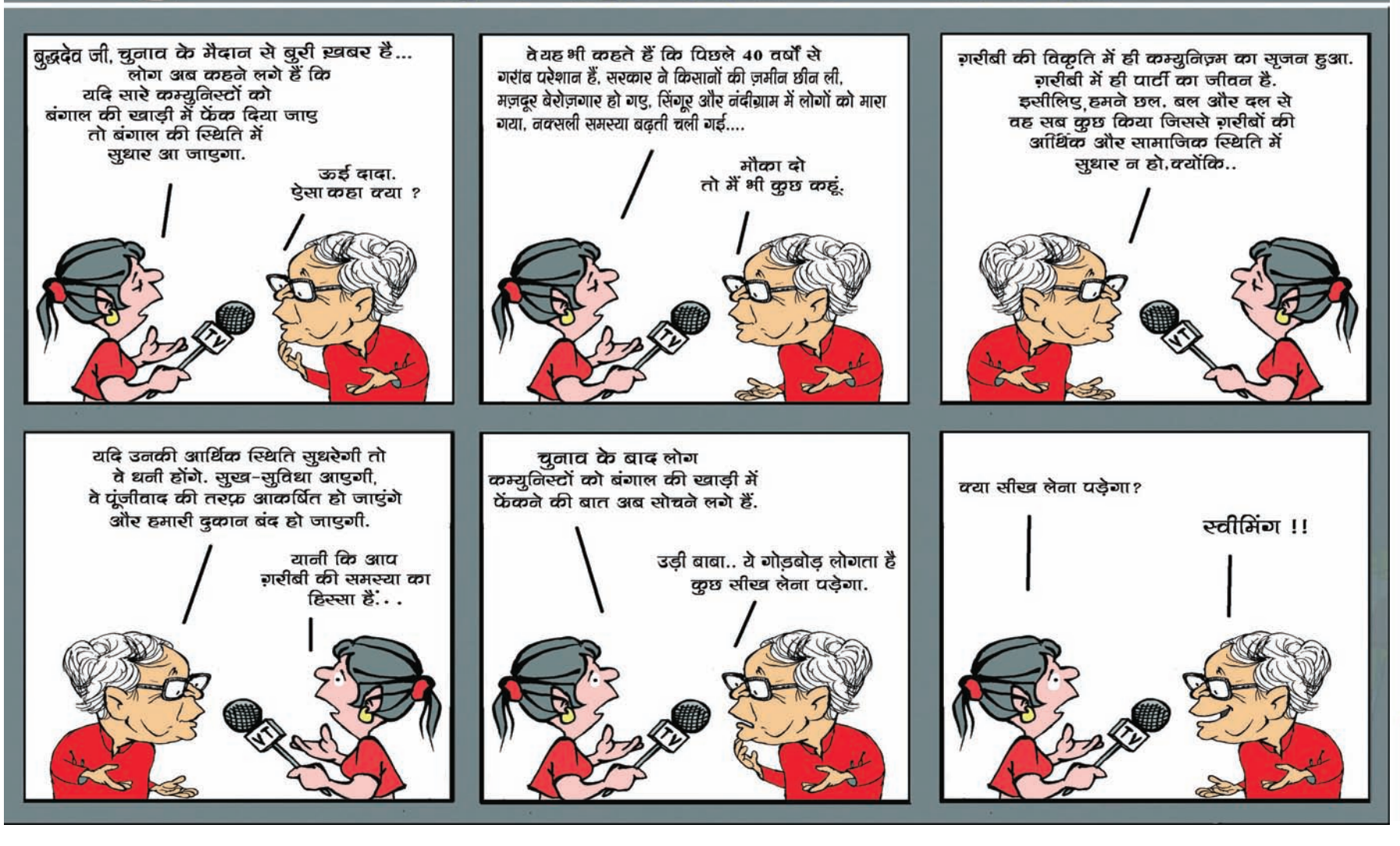

संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक़, अगर इसी तरह जल संपदा का दोहन होता रहा तो 2027 तक दुनिया भर में 270 करोड़ लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा, जबकि 250 करोड़ लोगों को मुश्किल से पानी मुहैया हो सकेगा.

पानी पर सबका हक़ है

भारत में दुनिया के कुल जल संसाधनों का 4 फ़ीसदी जल उपलब्ध है. राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग की रिपोर्ट 1999 के मुताबिक़, भारत के अनुमानित 1123 अरब घन मीटर (बीसीएम) इस्तेमाल लायक़ पानी में से सतही जल की मात्रा लगभग 690 बीसीएम है और भूगर्भीय जल संसाधन 433 बीसीएम है.

फ़िरदौस ख़ान

जल ही जीवन है. वाक़ई पानी के बिना ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि जहां एक तरफ़ करोड़ों लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं, वहीं इतने ही लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करके इसे बर्बाद करने पर आमादा हैं. जब हम पानी पैदा नहीं कर सकते तो फिर हमें इसे बर्बाद करने का क्या हक़ है? भारत सहित दुनिया भर के अनेक देशों के लिए जल संकट एक गंभीर चुनौती बना हुआ है. संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम की 1999 में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 देशों के वैज्ञानिकों ने पेयजल किल्लत को नई सदी की सबसे बड़ी दो गंभीर समस्याओं में से एक क़रार दिया है. उपलब्ध पानी का 70 फ़ीसदी हिस्सा कृषि में इस्तेमाल होता है. विश्व जल परिषद के मुताबिक़, 2020 तक मौजूदा पानी से 17 फ़ीसदी ज़्यादा की ज़रूरत होगी. इस वक़्त दुनिया में हर पांच में से एक व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के मुताबिक़, यूरोप में हर सातवें व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के एक अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया भर के 110 करोड़ लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिलता. इसलिए हर साल 50 लाख लोग जलजनित बीमारियों का शिकार होकर मौत के मुंह में समा जाते हैं. यह तादाद संघर्षों में मारे जाने वाले लोगों से दस गुना ज़्यादा है.

संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक़, अगर इसी तरह जल संपदा का दोहन होता रहा तो 2027 तक दुनिया भर में 270 करोड़ लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा, जबकि 250 करोड़ लोगों को मुश्किल से पानी मुहैया हो सकेगा. पृथ्वी का दो तिहाई हिस्सा पानी से घिरा है, लेकिन इसमें से पीने योग्य पानी बहुत कम यानी सिर्फ़ ढाई फ़ीसदी है. इस पानी का भी दो तिहाई हिस्सा बर्फ़ के रूप में है. दुनिया भर में जितना पानी है, उसका महज़ 0.08 फ़ीसदी हिस्सा ही मानव को उपलब्ध है. अनुमान है कि अगले दो दशकों में पानी की मांग क़रीब 40 फ़ीसदी तक बढ़ जाएगी. जल संकट के लिए बढ़ती आबादी, जल संसाधनों का कुप्रबंधन और जलवायु परिवर्तन ज़िम्मेदार हैं. जनसंख्या में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के कारण पानी की ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है. जितना पानी जुटाया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा आबादी बढ़ जाती है, इसलिए पानी की कमी बनी रहती है. इसके अलावा कृषि की परंपरागत सिंचाई व्यवस्था के कारण भी पानी बर्बाद होता है, जबकि आधुनिक फव्वारा तकनीक के ज़रिए सिंचाई में कम पानी इस्तेमाल होता है. आज़ादी के बाद भारत की कृषि भूमि में काफ़ी बढ़ोत्तरी हुई है. 1951 में जहां सिंचित भूभाग 226 लाख हेक्टेयर था, वहीं 2000 में यह बढ़कर 10 हज़ार करोड़ हेक्टेयर हो गया है. अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के मुताबिक़, आगामी पांच से दस सालों में उत्तर भारत में पानी की ज़बरदस्त किल्लत होने वाली है, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भू-जल स्तर तेज़ी से गिर रहा है. इन प्रदेशों के भू-जल स्तर में पिछले सात सालों में एक फुट प्रति वर्ष की गिरावट दर्ज की गई है. इसकी सबसे बड़ी वजह सिंचाई में भू-जल का इस्तेमाल है. हालांकि भारत में नदियों में अथाह जलराशि है, लेकिन औद्योगिक कचरा और शहरों की गंदगी बहा दिए जाने से इनका पानी दूषित हो गया है.

जल संसाधन मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक़, भारत में दुनिया के कुल जल संसाधनों का 4 फ़ीसदी जल उपलब्ध है. राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग की रिपोर्ट 1999 के मुताबिक़, भारत के अनुमानित 1123 अरब घन मीटर (बीसीएम) इस्तेमाल लायक़ पानी में से सतही जल की मात्रा लगभग 690 बीसीएम है और भूगर्भीय जल संसाधन 433 बीसीएम है. इसमें यह भी कहा गया है कि सभी स्रोतों में उठती मांगों की वजह से 2025 में क़रीब 843 बीसीएम जल की ज़रूरत होगी, जिसमें भूजल का योगदान 35.3 फ़ीसदी अथवा 298 बीसीएम होगा. तीसरी लघु सिंचाई जनगणना के मुताबिक़, 2001 में भारत में एक करोड़ 80 लाख भूजल विकास संरचनाएं थीं. अनुमान है कि यह संख्या अब बढ़कर 2 करोड़ तक पहुंच चुकी होगी. 1951 से 2001 के बीच भूजल सिंचित क्षेत्र में नौ गुना बढ़ोत्तरी हुई है. केंद्रीय भूजल बोर्ड ने राज्यों के साथ मिलकर सक्रिय भूजल संसाधनों का जो आकलन लगाया है, उसके मुताबिक़, देश के भूजल संसाधनों में से क़रीब 50 फ़ीसदी का ही इस्तेमाल हो रहा है. देश के विभिन्न हिस्सों में भूजल की उपलब्धता और उपयोग में भारी भिन्नता है, मसलन भारत के गांगेय क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र के व्यापक कछारों की भूगर्भीय संरचनाओं में प्रचुर भूजल संसाधन उपलब्ध हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानी संरचनाओं में बेहद सीमित मात्रा में कहीं-कहीं ही पानी मिलता है. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु के अधिकांश क्षेत्रों में भूगर्भीय जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया है और जल संसाधनों का ह्रास हो रहा है. उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और असम जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भूजल का स्तर संतोषजनक नहीं है.

केंद्रीय भूजल बोर्ड नौवीं योजना की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में विविध प्रकार की भूजल संरचनाओं के लिए उपयुक्त किफ़ायती रिचार्ज तकनीक को लोकप्रिय बनाने के मक़सद से वर्षा जल संचय और भूजल के कृत्रिम रिचार्ज प्रदर्शन की परियोजनाओं पर काम कर रहा है. ग्यारहवीं योजना के दौरान केंद्र प्रवर्तित योजना

भूजल प्रबंधन एवं नियमन के तहत एक अरब रुपये का प्रावधान किया गया है. जल संसाधन मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश आदि सात राज्यों के उन स्थानों में खुदे हुए सूखे कुओं को रिचार्ज करने काम शुरू किया है, जहां पानी का अत्यधिक दोहन किया जाता रहा है और पानी की गंभीर कमी है. जल संसाधन मंत्रालय ने देश के 5000 प्रदर्शन स्थलों में कृषक सहभागिता कार्य अनुसंधान कार्यक्रम को भी मंज़ूरी दी है, जिस पर 24 करोड़ 46 लाख रुपये ख़र्च किए जाएंगे. यह कार्यक्रम देश के 25 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 375 ज़िलों में लागू किया जा रहा है. इसमें 60 कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय अर्द्ध शुष्क-उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र फ़सल अनुसंधान संस्थान, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान और ग़ैर सरकारी संगठनों की मदद ली जा रही है. इसका मक़सद है कि पानी की हर बूंद के इस्तेमाल से पैदावार में बढ़ोतरी हो. हर कार्यक्रम न्यूनतम एक हेक्टेयर क्षेत्र में इस प्रकार सहभागिता के आधार पर चलाया जाता है कि किसान परिवार को लगे कि यह उसका अपना कार्यक्रम है. इसके तहत कृषि पद्धति, पानी की बचत और उसके भंडारण की व्यवस्था तथा कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया जाता है. भूजल संसाधनों में सुधार के अलावा मंत्रालय ने देश के उन क्षेत्रों में भूजल के उपयोग के नियमन के लिए अनेक क़दम भी उठाए हैं, जहां पानी का अत्यधिक दोहन किया जाता रहा है. देश में भूजल के विकास और नियमन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है. प्राधिकरण ने 43 ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित किया है, जहां पीने के अलावा अन्य किसी कार्य के लिए पानी निकालने की संरचना के निर्माण की इजाज़त नहीं है. पीने एवं घरेलू उपयोग के लिए पानी निकालने की अनुमति देने का अधिकार ज़िला मजिस्ट्रेटों को सौंपा गया है.सरकार ने भूजल विकास और प्रबंधन पर नियंत्रण के दृष्टिकोण से उपयुक्त क़ानून बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विधेयक का एक प्रारूप भेजा है. इसमें राज्यों में संबंधित अधिकारियों द्वारा वर्षा जल संचय कार्यक्रम पर अमल के लिए प्रावधान किया गया है. ग्यारह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इस विधेयक को क़ानून का रूप दे दिया है. 18 अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इसे क़ानून में बदलने की दिशा में क़दम उठाए गए हैं. अब तक 18 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों ने भवनों की छतों पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बना दिया है. जीआईएस तकनीक की मदद से केंद्रीय भूजल बोर्ड ने एक वेब जनित भूजल सूचना प्रणाली (डब्ल्यूईजीडब्ल्यूआईएस) का विकास किया है. इस प्रणाली से नीति निर्माताओं एवं नियोजकों को बड़े अथवा छोटे पैमाने पर योजना तैयार करने के लिए सभी तरह की ज़रूरी जानकारियां मिल रही हैं, जिनमें पानी का स्तर, उसकी गुणवत्ता और क्षेत्र की अन्य सामाजिक-आर्थिक सूचनाएं शामिल हैं.

जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में 2006 में भूजल कृत्रिम रिचार्ज सलाहकार परिषद का गठन किया गया. इस परिषद में केंद्र एवं राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं, उद्योगों, ग़ैर सरकारी संगठनों और किसानों के प्रतिनिधियों केअलावा विषय विशेषज्ञ सदस्यों को शामिल किया गया. परिषद की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं. परिषद की सिफ़ारिशों के आधार पर मंत्रालय ने अनेक क़दम उठाए हैं, जिनमें राष्ट्रीय भूजल कांग्रेस, कृषक सहभागिता कार्य अनुसंधान कार्यक्रम (एफपीएआरपी), भूजल संवर्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना आदि शामिल हैं, ताकि ग़ैर सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, निजी व्यवसायिक क्षेत्रों एवं व्यक्तियों को वर्षा जल संचय, कृत्रिम रिचार्जिंग, पानी के उपभोग में किफ़ायत और पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. परिषद की सिफ़ारिशों के मुताबिक़, 2007 और 2010 में राष्ट्रीय भूजल कांग्रेस का आयोजन किया गया. भारत के उथले जलग्राही क्षेत्रों में भूजल की गुणवत्ता के बारे में केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार रिपोर्ट पिछले साल 8 अप्रैल को परिषद की तीसरी बैठक में पेश की गई. मंत्रालय द्वारा स्थापित भूमि जल संवर्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पुरस्कार अब तक दो बार यानी 2007 और 2010 में दिए जा चुके हैं.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने पेयजल संकट पर चिंता जताते हुए कहा है कि जहां पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, वहां प्रदूषण है. उन्होंने कहा कि पानी को बर्बाद करने का सिलसिला जारी है. चाहकर भी इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है. इसकी एक वजह यह भी है कि अभी भी बहुत से लोगों को बिना मेहनत के आसानी से ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिल रहा है. क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पानी बर्बाद करने वालों को किसी भी तरह की कोई सज़ा दी जाए. जो लोग पानी बर्बाद करते हैं, उन्हें ऐसी जगह भेज दिया जाना चाहिए, जहां पानी बहुत ही मुश्किल से मिलता हो, तभी वे पानी के महत्व को समझ पाएंगे. जिन लोगों के घरों या नज़दीक के किसी स्थान में पानी का नल उपलब्ध नहीं है, ऐसे शहरी बाशिंदों की तादाद पिछले एक दशक के दौरान क़रीब 11 करोड़ चालीस लाख तक पहुंच गई है, जबकि पानी की कमी के कारण साफ़-सफ़ाई की सुविधाओं से वंचित लोगों की संख्या 13 करोड़ 40 लाख है. पानी संबंधी चुनौतियां काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं. अनेक देशों में महिलाओं को पनघट से पानी लाना पड़ता है. इसके अलावा समाज के अत्यधिक ग़रीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को अमीर लोगों के मुक़ाबले 20 से 100 फ़ीसदी ज़्यादा क़ीमत पर पानी ख़रीदना पड़ता है. रियो डि जेनेरियोन में 2012 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास सम्मेलन में पानी का मसला उठाया जाएगा. बहरहाल, हमें यह समझना होगा कि पानी पर सबका हक़ है. अगर हम किफ़ायत से पानी का इस्तेमाल करें तो उस बचे पानी से किसी और का गला तर हो सकता है.

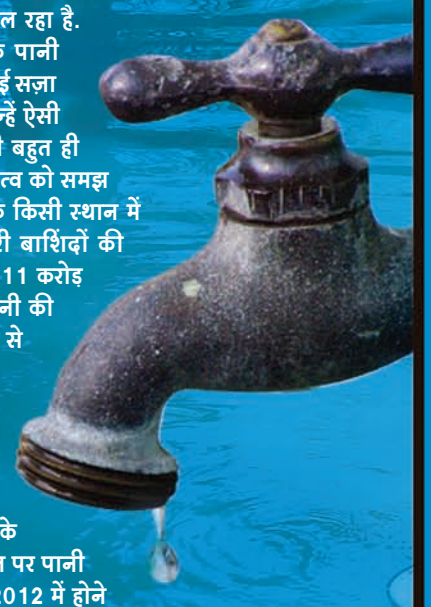

firdaus@chauthiduniya.com

सरकार ने भूजल विकास और प्रबंधन पर नियंत्रण के दृष्टिकोण से उपयुक्त क़ानून बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विधेयक का एक प्रारूप भेजा है. इसमें राज्यों में संबंधित अधिकारियों द्वारा वर्षा जल संचय कार्यक्रम पर अमल केलिए प्रावधान किया गया है. ग्यारह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इस विधेयक को क़ानून का रूप दे दिया है.

कई परिवारों से तो देश की बड़ी-बड़ी हस्तियां स्वयं मिलने आईं, परंतु उनकी मानसिक और माली हालत में कोई परिवर्तन नहीं आया.

बाबा के अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में अति विशिष्ट लोग पुट्टपर्थी पहुंचे. कोई नहीं जानता कि उनकी यात्राएं व्यक्तिगत थीं या आधिकारिक.

बदलाव के दौर में कांग्रेस ख़ुद को बदले

मेघनाद देसाई

महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता तो सही, लेकिन इसके लिए उन्होंने कई विवादित दांवों और गंदी चालों का इस्तेमाल भी किया. ऐसा करने के पीछे उनके पास पर्याप्त तर्क थे. चूंकि कौरवों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया था और जुआ जैसे खेल में बेईमानी से हराया था. शायद तभी युधिष्ठर ने अश्वथामा के बारे में गुरु द्रोण से झूठ बोला था. अर्जुन ने कर्ण को तब मारा, जब वह अपने रथ के फंसे पहिए को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था. भीम ने दुर्योधन का वध उसकी जंघा पर प्रहार करके किया था, जो युद्ध नियम के विरुद्ध था. और, यह सब कुछ हुआ कृष्ण के निर्देश पर.

हालांकि यह तब की बात थी, लेकिन क्या आज हमें फिर एक वैसे ही युद्ध की ज़रूरत है? 9 अप्रैल को जब अन्ना हजारे ने अपना अनशन ख़त्म किया, तब लोकतांत्रिक भारत द्वारा ज्वाइंट कमेटी गठन के ऐतिहासिक निर्णय पर हर किसी को गर्व हो रहा था. ज्वाइंट कमेटी एक नई सोच थी, जिसने सिविल सोसायटी को आवाज़ दी, लेकिन दु:ख की बात है कि इसके बाद दोनों पक्षों (ज्वाइंट कमेटी में सरकार और सिविल सोसायटी के सदस्यों) ने जो कुछ भी किया, वह निराशाजनक रहा. बेवजह 15 अगस्त की समय सीमा तय कर दी गई. अब हम देख रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस ने हमला किया और हजारे टीम के सदस्यों की छवि धूमिल कर रही है. हजारे टीम के सदस्यों को लेकर 9 अप्रैल से पहले भी सवाल उठ रहे थे. संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि यह वास्तव में एक जनांदोलन है या महज़ मीडिया की वजह से एकत्र एक भीड़. लेकिन जैसे ही 9 अप्रैल बीता, कांग्रेस के उकसावे पर कुछ लोगों ने भूषण पिता-पुत्र और अन्य सदस्यों पर आरोप लगाने शुरू कर दिए.

बहरहाल, एक भारतीय के रूप में जब बात नैतिकता की आती है तो हम महाभारत की ओर देखते हैं. संदेश स्पष्ट है. यदि आप जीतने के लिए धोखा देने की ज़रूरत समझते हैं तो ऐसा करें, यही धर्म है. लेकिन यह 21वीं शताब्दी है. हमने अन्य स्रोतों से भी नैतिकता के पाठ सीखे हैं, जैसे बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, इस्लाम एवं पारसी धर्म इत्यादि. मान लीजिए कि भूषण पिता-पुत्र के ख़िलाफ़ अभियान चलाने वाले

लोग अपने मक़सद में सफल हो जाते हैं और उन्हें कमेटी से बाहर निकलवा देते हैं तो क्या यह स्थिति सरकार के लिए अच्छी होगी? क्या ऐसा नहीं लगेगा कि सरकार शासन से जुड़े कुछ कठिन सवालों से बचने की कोशिश कर रही है. मान लीजिए, ईमानदार और अच्छा होने के कांग्रेस के पैमाने पर (ये पैमाने सिर्फ़ दूसरों के लिए लागू होते हैं, ख़ुद कांग्रेस के लिए नहीं) सिविल सोसायटी के सिर्फ़ तीन लोग ही खरे उतरते हैं तो क्या इसके बाद जो लोकपाल बिल निकल कर सामने आएगा, उससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी अथवा यह स्थिति 42 सालों में एक प्रभावी बिल पास न करा सकने की कड़ी में एक क़दम और आगे बढ़ने जैसा होगा.

और ऐसा क्यों है कि सिर्फ़ कांग्रेस ही यूपीए की ओर से मोर्चा संभाल रही है. क्या कोई ऐसी बात है, जिससे वह इस पूरी प्रक्रिया से भयभीत है. कांग्रेस अपनी सुरक्षा में इन ग़ैर सरकारी लोगों के प्रति इतनी आक्रामक क्यों है? क्या यह उचित नहीं होगा कि अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी लाई जाए, ताकि नए भारत के साथ मिलकर नया इतिहास रचा जाए. पंडित नेहरू भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग के ख़िलाफ़ थे, फिर भी उन्होंने इस मामले पर सहमति दिखाते हुए इसे सुलझाया. अब ऐसी कौन सी आफत आ गई है? लोकपाल बिल को लेकर कुछ नया, कुछ अद्‌भुत कर सकने की काफी गुंजाइश है. यह कोई रामबाण नहीं है और भी बहुत सारे बिल पास करने होंगे, लेकिन यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत है. युवाओं की एक पूरी पीढ़ी (ट्विटर जेनरेशन) एक साथ आगे आकर लोकपाल के लिए धरना-प्रदर्शन कर रही है. उसकी आशाओं को दबाने या कुचलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि कांग्रेस को आगे बढ़कर इस बदलाव के दौर में ख़ुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए. साथ ही यह सोचना चाहिए कि इस बदलाव से कैसे फ़ायदा उठाया जाए. सब जानते हैं कि मैं धार्मिक नहीं हूं. मैं किसी विवादित मुद्दे पर बार-बार लोगों को यह याद करने की नसीहत नहीं देना चाहता कि ईसा मसीह ने क्या कहा था. उन्होंने कहा था कि तुम सब में से जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, वही पहला पत्थर फेंक सकता है. ज़ाहिर है, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया.

feedback@chauthiduniya.com

विदर्भ के किसान परिवारों का मनोविज्ञान

डॉ. प्रकाश बेहरे

विदर्भ के आत्महत्याग्रस्त परिवारों में परस्पर संबंध और रचनात्मक व्यवहार के स्तर पर काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है. परिवार के सदस्यों के बीच पुराने मधुर संबंधों के तार उनके अवसादों की भेंट चढ़ चुके हैं. जीवित बचे सदस्य परिवार की आर्थिक और सामाजिक हैसियत में कोई वृद्धि नहीं कर पाते हैं, बल्कि सामाजिक ग्लानि और कुंठा से ग्रस्त जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं. सामाजिक कार्य-व्यापार से दूर अकेलापन इन शेष पीड़ित सदस्यों की दिनचर्या में शामिल हो चुका है. अवसाद का यही स्तर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता पाने वाले परिवारों में भी है. हालत इतनी बदतर है कि लगभग 33 प्रतिशत पीड़ित सदस्यों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति स्वयं पनपती गई. इस सर्वेक्षण के एक माह पूर्व ही कई पीड़ित विधवाओं के मन में आत्महत्या का भाव जगा था, जो वे बमुश्किल संभाल पाईं. 74 प्रतिशत पीड़ितों में भूख की कमी पाई गई, जबकि 65 प्रतिशत अनिद्रा के शिकार हैं और 68 प्रतिशत में अधिक थकान एवं जीवन से अरुचि पाई गई.

मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट के प्रो. के नागराज द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 1997 से 2006 के बीच भारत में 2 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली थी. मतलब यह कि तब प्रति वर्ष लगभग 16 हज़ार किसानों ने आत्महत्या की थी, यानी भारत की हर सातवीं आत्महत्या किसान आत्महत्या थी. इससे भी अधिक चौंकाने वाला सत्य सामने था कि भारत सहित श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड एवं आस्ट्रेलिया जैसे देशों में आत्महत्या करने वाले लोगों में सबसे अधिक संख्या किसानों की रही. देश में सबसे अधिक आत्महत्याएं विदर्भ के किसानों के बीच दर्ज की गई हैं. विदर्भ जन आंदोलन समिति के अनुसार, विदर्भ की कृषि में अधिकतम हिस्सा इसके 34 लाख कपास किसानों का है, जिनमें से 95 प्रतिशत क़र्ज़ में डूबे हैं. क़र्ज़ का यही बोझ आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है.

मेरी रुचि आत्महत्या करने वाले किसानों के आंकड़ों से अधिक उनके परिवारों पर होने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों में थी, ताकि नीति नियंताओं के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणाओं से हटकर किसान परिवारों के लिए समग्र मदद की योजनाओं के मापदंड तय हो सकें. वर्धा के 11 तालुकाओं के आत्महत्याग्रस्त किसानों के जीवित निकटतम परिवारीजनों के बीच मैंने अपने साथियों के साथ अध्ययन किया, जिसमें आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं, बच्चों और माता-पिता को शामिल किया गया. हमने बीस सूत्रीय पैमानों में 52 सवालों के साथ उनके मनोविज्ञान को जानने की कोशिश की. अधिकांश मामलों में मरने वाले पुरुष थे और भुक्तभोगी थीं महिलाएं. चूंकि आत्महत्या करने वाले किसान अधिकांशत: विवाहित थे, इसलिए अध्ययन में 50 प्रतिशत उनकी पत्नियां शामिल थीं, 17 प्रतिशत माता-पिता और शेष अन्य आश्रित. मृतकों के नज़दीकी रिश्तेदारों में अधिकांशत: 30 से 50 वर्ष की महिलाएं (63.1 प्रतिशत) हैं, जो मानसिक अवसाद से गुज़र रही हैं और इन्हें इससे उबरने में सालों लग सकते हैं. पीड़ित परिवारों में 60 प्रतिशत लोगों का मानसिक अवसाद अधिकतम और चिंताजनक है.

मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट के प्रो. के नागराज द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 1997 से 2006 के बीच भारत में 2 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली थी. मतलब यह कि तब प्रति वर्ष लगभग 16 हज़ार किसानों ने आत्महत्या की थी, यानी भारत की हर सातवीं आत्महत्या किसान आत्महत्या थी.

कई परिवारों से तो देश की बड़ी-बड़ी हस्तियां स्वयं मिलने आईं, परंतु उनकी मानसिक और माली हालत में कोई परिवर्तन नहीं आया. ऐसा इसलिए होता आया है कि सरकारी नीतियां आंकड़ों के जाल में फंस गईं. सरकार किसानों के लिए सस्ती ब्याज दरों पर क़र्ज़ मुहैया कराकर, उनके क़र्ज़ माफ कर या फिर उनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करके समस्या का समाधान ढूंढती रही. उन योजनाओं का हश्र भी छिपा नहीं है और उनके कार्यान्वयन में कमी या घोटालों के लिए जांच के प्रयास और प्रतिफल भी छिपे नहीं हैं. हाल में महाराष्ट्र सरकार ने बड़े पैमाने पर अपने अफसरों को बर्खास्त कर दिया. सरकारी नीति नियंताओं के लिए इस अध्ययन में स्पष्ट संकेत हैं कि जीवित बचे किसान परिवारों की समस्याओं का समाधान आर्थिक सहायता से नहीं हो सकता. अध्ययन में शामिल पीड़ित परिवारों में वैसे परिवार, जिन्हें सरकार से आर्थिक सहायता हासिल हुई और जिन्हें नहीं हुई, के मानसिक अवसाद में कोई फ़र्क़ नहीं था. यह भी हो सकता है कि पीड़ित परिवार में जीवित बचे सदस्य कहीं आत्महत्या न करने लगें. इसलिए ज़रूरी है कि सरकार जीवित बचे लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक सलाह की भी व्यवस्था करे.

(लेखक कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज, वर्धा के प्राध्यापक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

अनाज की सुरक्षा ज़रूरी

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गोदाम भर जाने के बाद अनाज को खुले में छोड़ दिया जाता है. कहीं-कहीं अनाज को प्लास्टिक से ढक कर रखा जाता है. चूहों द्वारा बोरे कुतरने के कारण काफ़ी अनाज बिखर जाता है. कीट-पतंगों द्वारा 5 प्रतिशत, चूहों द्वारा 7 प्रतिशत एवं अन्य कारणों से 4 प्रतिशत अनाज प्रति वर्ष भारतीय खाद्य निगम और सेंट्रल वेअर हाउसिंग कारपोरेशन में ख़राब हो जाता है. इस तरह क़रीब 5000 करोड़ रुपये का अनाज बर्बाद हो जाता है. अनाज का एक दाना बचाना, उतना पैदा करने के बराबर है. अगर अनाज को ख़राब होने से बचाया जाए तो विदेशों से खाद्यान्न मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.

-इंदू दिनकर गर्ग, *नागपुर, महाराष्ट्र.*

सर्वोच्च शक्तियां

क्रिकेट का विश्वकप जीतने के बाद धोनी ने तिरुपति, रैना ने साईं बाबा एवं सचिन ने गणपति जी के दर्शन किए और उनका आभार माना. इसी प्रकार हरभजन सिंह ने इस जीत को गुरु नानकदेव जी एवं युवराज ने अपने पारिवारिक गुरु जी की कृपा माना और उनके दर्शन कर पूजा-अर्चना की. देशवासियों ने भी नाना प्रकार के टोने-टोटके किए और व्रत रखे. किसी धर्म या गुरु में आस्था रखना हर व्यक्ति का निजी मामला है. वह अपनी इच्छानुसार धर्म अपना सकता है, गुरु की शरण में जा सकता है, मगर मेरे ज़ेहन में कुछ प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, जैसे कि हरभजन ने जीत को गुरु नानकदेव जी की कृपा बताया, लेकिन क्या गुरु जी अपनी कृपा सिर्फ़ हरभजन या धोनी या भारतीय टीम तक ही सीमित रखेंगे? संगकारा या श्रीलंकाई टीम या वहां की जनता ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि गुरु जी ने अपनी कृपा का अमृत उन पर नहीं बरसाया? क्या यूसुफ़ पठान-मुनाफ़ पटेल के अल्लाह और शाहिद अफ़रीदी एंड कंपनी के अल्लाह अलग-अलग हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर हम इन सर्वोच्च शक्तियों को समदर्शी क्यों समझते आ रहे हैं?

-ओम वर्मा, देवास, *मध्य प्रदेश.*

सर्वश्रेष्ठ पत्र

घपला दर घपला

अब एक और घपला 26 लाख करोड़ रुपये का पढ़ा. ऐसा लगता है, जैसे यूपीए सरकार का एकमात्र लक्ष्य देश को लूटना और इतना लूटना है कि फिर कुछ बचे ही नहीं. सड़कों के निर्माण और अन्य तमाम विकास योजनाओं के लिए धन की कमी का बहाना बनाने वाले हमारे शासक वर्ग को क्या हो गया है. पहले तो मनमोहन सिंह ने घोटालों की ज़िम्मेदारी दूसरे लोगों पर डालकर अपना पल्लू झाड़ लिया था, लेकिन इसके बाद वह देश की जनता को क्या समझाएंगे, यह देखने वाली बात होगी. उस काले धन का शोर तो ख़ूब मचा, जो विदेशी बैंकों में जमा है, लेकिन देश के अंदर जो काला धन मौजूद है, वह बाहर कैसे आएगा?

-सैयद शादाब अनवर, *शेरघाटी, गया, बिहार.*

जन लोकपाल

बाबा रामदेव ने अन्ना का दिया साथ,
अन्ना ने बाबा रामदेव को दिया त्याग,
अन्ना जी, यह संत के तिरस्कार का फल है,
बाबा रामदेव बिना जन लोकपाल असफल है.

-जयभारत, *ईमेल से.*

राह की अड़चन

भ्रष्ट नेताओं ने अपने पापों और काले कारनामों को छुपाने के लिए लोकपाल बिल के रास्ते में बहुत सी अड़चनें उत्पन्न कर दी हैं. लोकपाल बिल इन शातिर नेताओं की चाल में गुम होता नज़र आ रहा है.

-सुभाष चंद्र, *ईमेल से.*

देश के दुश्मन

64 वर्षों में पहली जन लोकपाल बिल को लेकर कुछ अच्छा होने जा रहा है, लेकिन उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे भ्रष्टाचारी एवं उनके साथी उद्योगपति नहीं चाहते कि देश में कुछ भी अच्छा हो. पाप का घड़ा भर चुका है और अब ऐसे लोगों का सर्वनाश निश्चित है.

-जय कुमार झा, *ईमेल से.*

राजकमल प्रकाशन समूह
राजकमल प्रकाशन
लोकभारती प्रकाशन
1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002 फोन 011-23274463, 23288769, फैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com

राजकमल प्रकाशन समूह
की ओर से
लेखन विधा को सम्मान

'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जानेवाली 700 रुपये की किताबें

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें
हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपये की पुस्तकें दी जाएंगी
हेल्पलाइन : 09311196029

पाठक पूरे नाम, पते व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इस पते पर भेजें : संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

देश पार्टी लाइन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है

संतोष भारतीय

देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में थोड़ी सी चिंता ज़्यादा बढ़ गई है. लोकतंत्र को चलाने की ज़िम्मेदारी अगर सीधे तौर पर देखें तो हमारे सांसदों की होती है. वे लोगों के वोट से चुन कर जाते हैं और उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वे देश से जुड़े हुए मसलों पर आपस में विवाद न करें. बहस करें और बहस करके जो देश के हित में हो, वह फ़ैसला करें. लोकतंत्र भी बचे और बेरोज़गारी, महंगाई एवं ग़रीबी से देश लड़ता भी दिखाई दे. पर संसद की समितियों में इधर जो होने लगा है, वह परेशानी के संकेत देता है. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या लोक लेखा समिति एक ऐसी समिति है, जो सरकार द्वारा सारे देश में किए गए कामकाजों, ख़ास तौर से जिनका रिश्ता आर्थिक ख़र्चों से होता है, पर नज़र रखती है. जो रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे वह सीएजी की रिपोर्ट हो या कोई और रिपोर्ट, उन सबका वह विश्लेषण करती है और देश को बताती है कि इसमें यह सच्चाई है. लोक लेखा समिति की रिपोर्ट अगर संसद स्वीकार कर लेती है तो फिर उस पर संसद की मुहर लग जाती है. संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति लोक लेखा समिति मानी जाती है, पर पिछले दिनों जो हुआ, उसने इस तरह के संकेत दिए कि अब लोक लेखा समिति महत्वपूर्ण समिति नहीं रही. उसके सदस्य महत्वपूर्ण नहीं रहे. सदस्यों ने ख़ुद अपनी और समिति की गरिमा समाप्त करने की कोशिश की. जब किसी समिति में सदस्य होते हैं तो वे पार्टी के सदस्य नहीं रह जाते. चाहे समिति का अध्यक्ष हो या विभिन्न दलों के सदस्य, जब वे लोक लेखा समिति में पहुंचते हैं, तब उन पर ज़िम्मेदारी होती है कि वे आने वाले विषय के गुण-दोष पर विचार करें. पर यहां क्या हुआ? यहां हुआ यह कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जब बनी, उसके मुख्य अंश समाचारपत्रों में लीक हो गए. अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी पर आरोप लगा कि उन्होंने पार्टी लाइन पर इसे बनाया और बाकी सदस्यों से बात नहीं की. कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के सदस्य एक हो गए और उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को हमें पास ही नहीं होने देना है.

ए राजा जेल में हैं. 2-जी स्पेक्ट्रम का मसला था. पहले बहस हुई कि इसके लिए क्या हो? पूरा एक सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और तब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी. उसने 2-जी स्पेक्ट्रम की पैरेलल जांच की. हम यह समझ नहीं पाते हैं कि देश के सांसद क्या कभी अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचेंगे? भाजपा के सदस्य हों, कांग्रेस के हों या दूसरी पार्टियों के, ये सारे के सारे पार्टी लाइन में बंटे हुए हैं. ये अपनी पार्टी का हित सोचते हैं. पार्टी को स्कोर कैसे मिले, पार्टी का हित कैसे सधे, इस पर उनका दिमाग़ बहुत चलता है. पर इस मुल्क के सामने कोई सच्चाई आए, उसके बारे में ये सोचते ही नहीं हैं, बल्कि सोचना चाहते ही नहीं. संसद में लोकसभा की बैठक होती है, राज्यसभा की बैठक होती है, आप जो चाहें करें. भाजपा कांग्रेस को गाली दे, कांग्रेस भाजपा को गाली दे. पर इतनी समझ इन सांसदों में नहीं पैदा होती कि जब वे किसी समिति में बैठते हैं, तब वे अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश हित के बारे में सोचें. लोकतंत्र की यह ख़ूबी अब हमारे बीच से धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है.

लोकसभा का एक उदाहरण है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष आर आर मोरारका थे. आर आर मोरारका ने अपनी रिपोर्ट में कुछ कमेंट किया और तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने लॉबी में (सदन के अंदर नहीं) और दोनों कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे, मोरारका जी से कहा कि आप ऐसी रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं? मोरारका जी ने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष ही नहीं है, समिति के सदस्य हैं, जिन्होंने यह रिपोर्ट बनाई है. उस समय भी लोक लेखा समिति की संरचना ऐसी ही होती थी, जैसी अभी है. तब तक किसी सदस्य ने, शायद आचार्य कृपलानी ने इसे सुन लिया और उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि श्री गुलजारी लाल नंदा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष आर आर मोरारका को धमका रहे थे. सदन में हंगामा हो गया. सारे नेताओं ने इस घटना की निंदा की. गुलजारी लाल नंदा ने सदन से माफ़ी मांगी. हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा मतलब यह नहीं था, जो आचार्य जी निकाल रहे हैं. पर उन्हें लोकसभा में खेद प्रकट करना पड़ा. लोक लेखा समिति की लाइन पार्टी नहीं थी, देश की लाइन थी. आज क्या हो गया है? क्या तीस सालों में हमारा संसदीय लोकतंत्र टूट के कगार पर पहुंच गया है? हम इतने ज़्यादा पार्टी लाइन से जुड़ गए हैं कि देश के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते?

ए राजा जेल में हैं. 2-जी स्पेक्ट्रम का मसला था. पहले बहस हुई कि इसके लिए क्या हो? पूरा एक सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और तब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी. उसने 2-जी स्पेक्ट्रम की पैरेलल जांच की. हम यह समझ नहीं पाते हैं कि देश के सांसद क्या कभी अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचेंगे? भाजपा के सदस्य हों, कांग्रेस के हों या दूसरी पार्टियों के, ये सारे के सारे पार्टी लाइन में बंटे हुए हैं. ये अपनी पार्टी का हित सोचते हैं. पार्टी को स्कोर कैसे मिले, पार्टी का हित कैसे सधे, इस पर उनका दिमाग़ बहुत चलता है.

ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं, क्योंकि देश के सामने सचमुच विश्वास का संकट खड़ा हो गया है. इन सांसदों को नहीं पता है कि सांसद चाहे किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो या किसी और पार्टी का, लोगों की नज़र में आज सांसदों की कोई इज़्ज़त नहीं है. वे हर सांसद को बिका हुआ मानते हैं, वे हर सांसद को दलाल मान रहे हैं. ईमानदार लोग हैं, पर उनकी सुनता कौन है? ईमानदार सांसदों को तो संसद में बोलने का मौक़ा ही नहीं मिलता. ऐसे-ऐसे उदाहरण हैं कि सांसदों का पूरा का पूरा कार्यकाल बीत जाता है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता उन्हें संसद में बोलने की इजाज़त ही नहीं देते. ईमानदार सांसदों को संसद के एक कोने में अछूत की तरह, अस्पृश्य की तरह बैठा दिया जाता है. बोलता कौन है! जो दाग़ी होता है. बोलता कौन है! जो अपराधी होता है. शोर कौन करता है! जिसके पास कोई ज्ञान नहीं होता, देश की समस्याओं की जानकारी नहीं होती. यही मुल्क की चिंता का विषय है.

दूसरा मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है. जब हम बात करते हैं संसद के सदस्यों से कि आपके यहां ऐसे-ऐसे लोग आते हैं, आप लोग इस तरीक़े की हरकत करते हैं और देश बुरा मानता है. वे कहते हैं कि देश को बुरा मानने की क्या ज़रूरत है? यही लोग तो चुनते हैं ऐसे लोगों को! जिन सांसदों से हमारे लोग या हम बात करते हैं, उनसे एक ही बात सामने आती है कि देश के लोगों को क्यों परेशानी है? आप चुनते हैं ऐसे ही लोगों को! हम यहां आकर जो करते हैं, उससे आपको कोई परेशानी या शर्म नहीं होनी चाहिए. एक सांसद ने बहुत साफ़ कहा कि हम अपने चुनाव पर 10 से 15 करोड़ रुपये ख़र्च करते हैं. 10 से 15 करोड़ रुपये का मतलब! दरअसल, अब कोशिश की जाती है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र के हर घर को नकद पैसा जाए. पार्टियां अपने-अपने समर्थकों की लिस्ट बनाती हैं और उनके यहां वोटरों के हिसाब से पैसा दिया जाता है. चुनाव आयोग सख़्त हो गया है. अब गाड़ियों का काफिला नहीं निकलता, अब दीवार पर लिख नहीं सकते, पोस्टर एक सीमा से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, होर्डिंग नहीं लगा सकते, लोगों को बेवकूफ बनाने के और साधन नहीं जुटा सकते. उम्मीदवारों ने सीधा रास्ता निकाल लिया कि वोटर के पास सीधे पैसे भेजो. जब उस सांसद ने यह कहा तो दिमाग हिल गया. उसने कहा कि हर घर में हम पैसा भेजते हैं, लिफाफे भेजते हैं और जब इतना ख़र्च करके यहां आते हैं दिल्ली में तथा हमें अगला चुनाव भी लड़ना होता है. तो आप क्या समझते हैं कि हम सिर्फ़ संसद की तनख्वाह पर अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं? जो ख़र्च किया है, उसकी वसूली कहां से होगी, भरपाई कहां से होगी? अगला चुनाव हम किस तरह लड़ेंगे? उसकी भी तैयारी हमें करनी पड़ती है. इसलिए जो भी संसद में हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जिसके भी हक़ में हो रहा है या जिसके भी ख़िलाफ़ हो रहा है, उससे जनता को क्या मतलब?

हमें भी यह लगता है कि अगर इस देश की जनता नहीं चेती तो हमारी संसद, इस महान भारत देश की संसद लोकतंत्र के अवसान का गीत गाएगी, लोकतंत्र के अवसान का शिलालेख लिखेगी. इस संसद को अगर जगाना है, इस संसद पर कंट्रोल करना है और इस संसद को दिशा देनी है तो जनता का हस्तक्षेप अनिवार्य है. देश की जनता यानी देश के मतदाता अगर नहीं चेते तो संसद में आज जो हो रहा है, जिसका सबसे अद्यतन उदाहरण लोक लेखा समिति है, वैसा आप मानकर चलें कि भारत की संसद में अब अक्सर होगा, क्योंकि इन सांसदों के लिए देश नहीं, उनकी पार्टी प्रमुख है. पार्टी में भी पार्टी हित नहीं, जिस नेता ने उन्हें टिकट दिलाया है, उसका हित प्रमुख है. इस अंतर्विरोध को अगर देश की जनता समझ ले, तभी कुछ हो सकता है और अगर वह नहीं समझेगी तो हमें भी अपने देश से लोकतंत्र को विदा होते देखने के लिए तैयार रहना चाहिए.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

सत्य साईं बाबा

आस्था के ज्वार में डोलती तार्किकता की नाव

राम पुनियानी

सत्य साईं बाबा के अवसान ने उनके लाखों अनुयायियों के जीवन में भावनात्मक भूचाल ला दिया है. पुट्टपर्थी में क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित एजेंसियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. बाबा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अति महत्वपूर्ण लोगों के लिए समुचित प्रबंध करना कम चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं था. सत्य साईं बाबा के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए देश भर में और विदेशों में भी भजन सभाएं हुईं. राजनीति, व्यवसाय, फिल्म एवं खेल की दुनिया की नामचीन हस्तियां शोक व्यक्त करने पुट्टपर्थी पहुंचीं. बाबा के विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हो, इस यक्ष प्रश्न का उत्तर खोजना आसान नहीं है. यह साम्राज्य भी साईं बाबा ने शून्य से पैदा किया था, ठीक वैसे ही, जैसे वह भभूत और सोने की जंजीर आदि हवा से पैदा कर दिया करते थे.

सत्य साईं के अनुयायियों, भक्तों और प्रशंसकों की संख्या बहुत बड़ी है. उनसे रईस बाबा शायद ही कोई दूसरा होगा. उनके साम्राज्य की ठीक-ठीक क़ीमत आंकना बहुत कठिन है. बाबाओं द्वारा नियंत्रित संपत्ति का बड़ा हिस्सा हमेशा छुपा रहता है. संसार को त्याग चुके इन संन्यासियों की संपत्ति का सोशल आडिट करने के लिए लोकपाल जैसी कोई संस्था गठित करने का प्रस्ताव रखने की किसी में हिम्मत नहीं है. इन बाबाओं का जीवन बताता है कि यदि आपको संसार त्यागने का सही तरीक़ा मालूम हो तो धन-संपदा आपके पीछे दौड़ती है. इस धन का कुछ हिस्सा समाज सेवा के कार्यों में ख़र्च किया जाता है, जिसका जमकर प्रचार होता है और यह बाबाओं के जीवन का सबसे ज़्यादा सार्वजनिक पहलू है. इसके विपरीत उनके जीवन के अन्य पहलू रहस्य के गहरे आवरण में लिपटे रहते हैं.

सत्य साईं कई विवादों के केंद्र में रहे हैं. उन्हें ठीक से समझना एक मुश्किल कार्य है. हवा से भभूत और सोने की जंजीर पैदा करने की कला में वह सिद्धहस्त थे. पहले वह एचएमटी की घड़ियां भी हवा में हाथ लहरा कर पैदा करते थे, परंतु यह एहसास होने के बाद कि घड़ियों में उनकी निर्माण तिथि अंकित रहती है, उन्होंने यह काम बंद कर दिया. कई तार्किकतावादियों ने उन्हें चुनौती दी थी. सत्य साईं के चमत्कारों को कई बार सड़कों पर दोहराया गया, यात्राएं निकाली गईं, जिनका संदेश यह था कि साईं बाबा के चमत्कार केवल हाथ की सफाई हैं और उनका आध्यात्म या ईश्वर से कोई लेना-देना नहीं है. इन चमत्कारों को दैवीय बताए जाने को जाने-माने जादूगर पी सी सरकार ने भी चुनौती दी थी. सत्य साईं बाबा को यह चुनौती दी गई थी कि वह हवा से एक बड़ा सा कद्दू पैदा करके दिखाएं. बाबा ने यह चुनौती स्वीकार नहीं की. शायद हवा से कद्दू पैदा करना उन्हें आता नहीं था, परंतु इस सबसे उनके अनुयायियों को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा, बल्कि उनकी संख्या बढ़ती चली गई. उनके शिष्य समाज के सभी वर्ग में थे. अच्छी-ख़ासी संख्या में विदेशी भी उनकी ओर आकर्षित हुए.

सत्य साईं कई विवादों के केंद्र में रहे हैं. उन्हें ठीक से समझना एक मुश्किल कार्य है. हवा से भभूत और सोने की जंजीर पैदा करने की कला में वह सिद्धहस्त थे. पहले वह एचएमटी की घड़ियां भी हवा में हाथ लहरा कर पैदा करते थे, परंतु यह एहसास होने के बाद कि घड़ियों में उनकी निर्माण तिथि अंकित रहती है, उन्होंने यह काम बंद कर दिया.

सत्य साईं बाबा ने यह घोषणा की थी कि वह शिरडी के साईं बाबा के अवतार हैं. शिरडी के साईं बाबा की ज़िंदगी अत्यंत सादगीपूर्ण थी. वह पेड़ के नीचे रहते थे. सत्य साईं बाबा के कारण शिरडी के साईं बाबा भी ऐश्वर्य से घिर गए हैं. उनकी मूर्ति अब सोने के सिंहासन पर विराजमान है. शिरडी के साईं बाबा के स्व-घोषित अवतार होने के अतिरिक्त सत्य साईं बाबा ने स्वयं को भगवान का दर्जा भी दिया था. उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि वह 96 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्यागेंगे. दुर्भाग्यवश उनकी नश्वर देह को केवल 85 वर्ष तक ही सुरक्षित रखा जा सका. उन्होंने अपनी दैवीय शक्ति से न जाने कितनों की जान बचाई होगी, परंतु उनकी जान बचाने के लिए उन्हें लंबे समय तक वेंटीलेटर पर रखना पड़ा. इसके बावजूद उन्हें उनकी भविष्यवाणी के अनुरूप 96 साल तक जीवित नहीं रखा जा सका.

सत्य साईं बाबा के चमत्कार चाहे असली रहे हों या नकली, परंतु विभिन्न विवादों के बावजूद उनके भक्तों की संख्या जिस तरह बढ़ती गई, वह सचमुच चमत्कारिक था. उन पर बच्चों का यौन शोषण करने का आरोप लगा. कुछ बालिगों ने भी उन पर यौन शोषण संबंधी आरोप लगाए. टाम ब्रुक ने अपनी पुस्तक अवतार ऑफ द नाइट: हिडन साइड ऑफ साईं बाबा (रात का अवतार: साईं बाबा के जीवन का छुपा हुआ पक्ष) में इस सिलसिले में स्वयं के अनुभव का वर्णन किया है. कुंडलिनी जाग्रत करने के नाम पर युवा भक्तों के यौन शोषण की बातें भी सामने आती रही हैं. सत्य साईं बाबा के निवास स्थान पर एक कत्ल भी हुआ था, जिसके बाबा चश्मदीद थे, परंतु इसकी जांच ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी. आध्यात्मिक दुनिया में दुनियावी क़ानूनों की क्या बिसात! भगवान के उच्चपदस्थ भक्तों ने हमेशा उनके हितों की रक्षा की. चाहे उनके चमत्कारों की पोल खोलने वाले अभियान हों या उनके घर में कत्ल, सारे के सारे मामले नज़रअंदाज़ कर दिए गए और धीरे-धीरे जनता इन्हें भूल गई. सत्य साईं बाबा पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, जिन्होंने स्वयं को भगवान घोषित किया हो. इसके पहले रजनीश भी ऐसा कर चुके हैं. उन्होंने ईश्वरत्व पाने की यात्रा रजनीश के तौर पर शुरू की थी. बाद में वह आचार्य रजनीश और फिर भगवान रजनीश कहलाने लगे. अंतत: उन्होंने ओशो का दर्जा हासिल कर लिया.

बाबा के अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में अति विशिष्ट लोग पुट्टपर्थी पहुंचे. कोई नहीं जानता कि उनकी यात्राएं व्यक्तिगत थीं या आधिकारिक. न ही हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में इस तरह के विभेदों के लिए कोई जगह बची है. संविधान हमें अपने-अपने धर्मों का पालन करने की इजाज़त देता है, परंतु केवल व्यक्तिगत स्तर पर, राजनीतिक या आधिकारिक स्तर पर नहीं. अत: इस प्रकार की यात्राएं सरकारी ख़र्च पर करने को कतई उचित नहीं कहा जा सकता. हमारा संविधान तार्किक सोच को बढ़ावा देने की बात भी करता है, परंतु इस दिशा में राज्य की ओर से शायद ही कुछ किया जाता हो. सत्य साईं के मामले में अब्राहम कोवर एवं प्रेमानंद जैसे तार्किकतावादियों की बातें नक्कारखाने में तूती की आवाज़ साबित होती रही हैं. उन्हें अनसुना किया जाता रहा है और उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं. भगवान होने के दावों पर प्रश्नचिन्ह लगाने वाली कई फिल्में भी हैं, जिनमें से प्रमुख हैं गुरु बस्टर्स और सीक्रेट स्वामी.

धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को भी इन बाबाओं से मदद मिलती है. हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, जब आस्था का ज्वार तर्कवाद की नाव को डुबोने की भरपूर कोशिश कर रहा है और इस नाव का राज्य रूपी मल्लाह अकर्मण्य साबित हो रहा है. आस्था की आंधी इतनी तेज और शक्तिशाली है कि बाबाओं के मामले में प्रश्न उठाना अपराध सरीखा हो गया है. यही कारण है कि स्वयं को भगवान बताने वाला व्यक्ति, जिसके चमत्कारों को सड़क छाप जादूगर भी आसानी से दोहरा सकते हैं, अकूत संपदा का मालिक बन जाता है. इस संपदा के एक हिस्से को समाज सेवा का आकर्षक शो पीस बनाकर दुनिया के सामने रख देने मात्र से उसके कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है. यह भी साफ है कि इस युग में अंधश्रद्धा का विरोध करना धारा के विरुद्ध तैरने जैसा है. हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि आधुनिक जीवन की आपाधापी और असुरक्षा के भाव के चलते लोगों को किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है. 1970 के दशक में ऐसे लोग एलएसडी का सहारा लेते थे, अब वे बाबाओं की शरण में जा रहे हैं. अपने पुनर्जन्म के बारे में साईं बाबा की भविष्यवाणी भी दिलचस्प है. उनका कहना था कि 2022 में कर्नाटक के मांड्या ज़िले में उनका पुनर्जन्म होगा. यह देखना दिलचस्प होगा कि भगवान कैसे फिर से धरती पर आते हैं और उनके अनुयायी उन्हें कैसे पहचानते हैं. तब तक हम केवल आशा ही कर सकते हैं कि हर तरफ कुकुरमुत्तों की तरह उग आए बाबाओं के बारे में हमारा समाज तार्किक ढंग से सोचना शुरू करेगा.

(लेखक आईआईटी मुंबई के पूर्व प्राध्यापक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

केरकोरी के मौलवी करीम अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें आप पढ़ा-लिखा कह सकते हैं. उनके अलावा शायद ही कोई साक्षर है.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

एक आवेदन से बन जाएगा काम

रिश्वत देना जहां एक ओर आम आदमी की मजबूरी बन चुका है, वहीं कुछ लोगों के लिए यह अपना काम जल्दी और ग़लत तरीक़े से निकलवाने का ज़रिया भी बन गया है, लेकिन इन दोनों स्थितियों में एक फ़र्क़ है. एक ओर 2-जी स्पेक्ट्रम के लिए रिश्वत दी जाती है तो दूसरी ओर एक आम और बेबस आदमी को राशनकार्ड बनवाने, सरकारी पेंशन, दवा एवं इंदिरा आवास पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है. वैसे रिश्वत किसी भी काम के लिए या किसी भी रूप में देना न सिर्फ़ ग़ैर क़ानूनी है, बल्कि अनैतिक भी है. बावजूद इसके व्यवस्था में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इस बीमारी से निजात पाना मुश्किल नज़र आता है. आप चाहे शहर में रहते हों या गांव में, सरकारी बाबुओं द्वारा फाइल दबाने और फाइल आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग से आप सभी का सामना ज़रूर हुआ होगा. गांवों में वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुज़ुर्गों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है. शहरों में भी लोगों को आयु, जन्म-मृत्यु एवं आवास प्रमाण पत्र बनवाने या इनकम टैक्स रिफंड लेने के लिए नाकों चने चबाने पड़ते हैं, साथ ही काम कराने के लिए रिश्वत भी देनी पड़ती है. अब सवाल यह है कि जो आदमी रिश्वत देने की स्थिति में नहीं है तो क्या उसका काम नहीं होगा? ऐसा नहीं है, काम ज़रूर होगा, वह भी बिना रिश्वत दिए. ज़रूरत है सिर्फ़ अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की और वह अधिकार है, सूचना का अधिकार.

यह अधिकार एक क़ानून है. महज़ एक आवेदन देकर आप रिश्वतखोर अधिकारियों की नींद हराम कर सकते हैं. जैसे ही आप अपने रुके हुए काम से संबंधित एक आरटीआई आवेदन डालते हैं, भ्रष्ट और रिश्वतखोर अधिकारियों एवं और बाबुओं की समझ में आ जाता है कि जिसे वे परेशान कर रहे हैं, वह आम आदमी तो है, लेकिन अपने अधिकारों और नियमों के प्रति जागरूक है. सरकारी विभागों में भी आम तौर पर उन्हीं लोगों को ज़्यादा परेशान किया जाता है, जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है. सूचना अधिकार क़ानून में इतनी ताक़त है कि छोटे-मोटे काम तो आवेदन देने के साथ ही हो जाते हैं. इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, बजाय घूस देकर काम कराने के. चौथी दुनिया आपके हर क़दम पर आपका साथ देने को तैयार है. कोई समस्या हो, कोई सुझाव चाहिए या आप अपने अनुभव हमसे बांटना चाहते हों तो हमें पत्र लिखें या ईमेल करें. हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(किसी भी सरकारी विभाग में रुके हुए काम यथा राशनकार्ड, पासपोर्ट, वृद्धावस्था पेंशन, आयु-जन्म-मृत्यु-आवास प्रमाणपत्र बनवाने, इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी होने, रिश्वत मांगने या बिना वजह परेशान करने की स्थिति में आप निम्न प्रश्नों के आधार पर अपना आवेदन तैयार कर सकते हैं)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
मैंने आपके विभाग में दिनांक.....को.....के लिए आवेदन किया था. (आवेदन की प्रति संलग्न है), लेकिन मेरे आवेदन पर अब तक कोई संतोषजनक क़दम नहीं उठाया गया है.
कृपया इस संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:-
1. मेरे आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कार्रवाई अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं. मेरा आवेदन किन-किन अधिकारियों के पास गया और किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा तथा इस दौरान उन अधिकारियों ने उस पर क्या कार्रवाई की? पूरा विवरण उपलब्ध कराएं.
2. विभाग के नियम के अनुसार मेरे आवेदन पर अधिकतम कितने दिनों में कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए थी? क्या मेरे मामले में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया है?
3. कृपया उन अधिकारियों के नाम एवं पद बताएं, जिन्हें मेरे आवेदन पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.
4. अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी और यह कार्रवाई कब तक की जाएगी?
5. अब मेरा काम कब तक पूरा होगा?
(अतिरिक्त प्रश्न, यदि आवश्यक हो)
6. कृपया मुझे सभी आवेदनों/रिटर्न/याचिका/शिकायत की सूची उपलब्ध कराएं, जिन्हें मेरे आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत जमा होने के बाद जमा किया गया. सूची में निम्नलिखित सूचनाएं होनी चाहिए:-
क. आवेदक/करदाता/याचिकाकर्ता/पीड़ित का नाम
ख. रसीद संख्या
ग. आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत की तारीख़
घ. कार्रवाई की तारीख़
7. कृपया रिकॉर्ड के उस हिस्से की छायाप्रति दें, जो उपरोक्त आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत की रसीद का ब्योरा रखते हों.
8. मेरे आवेदन के बाद यदि किसी आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत का नंबर आने से पहले निस्तारण किया गया हो तो उसका कारण बताएं.
9. इस आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत के नंबर आने से पहले निस्तारण के मामले में, यदि कोई हो तो, पूछताछ कब तक की जाएगी?

मैं आवेदन शुल्क.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय
नाम.....
पता.....

तीस साल से मुर्दे को ज़िंदा रखा

बहुत अजीब घटना है. एक व्यक्ति, जिसकी मृत्यु तीस साल पहले हो गई थी, उसे लोग जिंदा समझे हुए थे. सोगेन काटो नामक यह शख़्स टोक्यो के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन जब अधिकारी काटो को उनके 111वें जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे तो उन्हें उनके बिस्तर पर एक कंकाल मिला. जापानी अधिकारियों को आशंका है कि काटो की मौत 30 साल पहले हो गई थी. अधिकारियों को उस समय संदेह हुआ, जब वे काटो को सम्मानित करने अदाची वार्ड स्थित उनके घर पहुंचे, लेकिन उनकी पोती ने कहा कि काटो किसी से मिलना नहीं चाहते. पुलिस अब परिवारवालों के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है. अदाची वार्ड के अधिकारी टोमोको ल्वामत्सू ने बताया कि इलाक़े के कल्याण अधिकारियों ने इस साल की शुरुआत में ही काटो से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन जब वे काटो से मिलने पहुंचे तो उनके परिवारीजनों ने उन्हें भगा दिया. इसके बाद अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस से जांच करने की मांग की.

जब पुलिस जबरन काटो के घर में घुसी तो उसे वहां कंकाल में तब्दील हो चुका एक शव मिला, जो बिस्तर पर पड़ा था. माना जा रहा है कि यह काटो का शव है. काटो के कंकाल पर सिर्फ़ अंडरवियर और पायजामा था और वह कंबल से ढका था. रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि काटो ने 30 साल से भी ज़्यादा समय से ख़ुद को इस कमरे में बंद कर लिया था और लिविंग बुद्धा बन गए थे. लेकिन पता यह चला है कि काटो के परिवारीजनों ने छह साल पहले उनकी पत्नी की मौत के बाद विधुर को मिलने वाली पेंशन के तहत 95 लाख येन (एक लाख नौ हज़ार डॉलर) की राशि काटो के बैंक खातों से निकाली. इस राशि का कुछ हिस्सा तो हाल-फ़िलहाल में बैंक से निकाला गया. पेंशन अधिकारी भी काफ़ी समय से काटो से कोई संपर्क नहीं कर पाए थे. टोक्यो के एक कल्याण अधिकारी ने कहा कि परिवारीजनों को इस बारे में निश्चित तौर पर पता होगा कि काटो इतने वर्षों से मृत हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे व्यवहार किया कि जैसे वे कुछ जानते ही न हों.

एक मां के कितने बच्चे

हम दो-हमारे दो का सरकारी नारा देश के दूरदराज़ के इलाक़ों में मुश्किल से ही पहुंच पाता है. शायद तभी राजस्थान के सरहदी ज़िले बाड़मेर के एक गांव में 49 वर्षीय जन्नत 23वीं बार मां बनने जा रही हैं. जन्नत और उनके शौहर 50 वर्षीय अब्दुल बहुत उत्सुकता से घर में आने वाले नए मेहमान का इंतज़ार कर रहे हैं. ज़िला मुख्यालय से कोई सौ किलोमीटर दूर जन्नत का केरकोरी गांव आपको ऐसे जहान से रूबरू कराता है, जहां न सड़क है, न बुनियादी सुविधाओं का कोई वजूद. जन्नत के आंगन में उनके अट्ठारह बच्चे खेलते मिलते हैं. इनमें चौदह लड़कियां हैं, जो जन्नत के मुताबिक़ जुड़वां हैं.

उनके दो बच्चे गांव के मदरसे में तालीम लेते हैं. केरकोरी के मौलवी करीम अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें आप पढ़ा-लिखा कह सकते हैं. उनके अलावा शायद ही कोई साक्षर है. मौलवी करीम जन्नत के फिर से मां बनने और बच्चा पैदा होने को ख़ुदा की नियामत मानते हैं. इस गांव में किसी के पास फ़ोन नहीं है. केरकोरी अपनी ही बनाई दुनिया में ज़िंदगी के सारे सुख महसूस कर लेता है. न कोई शिकवा, न शिकायत. जन्नत और उनके पति अब्दुल दोनों स्वस्थ हैं. जन्नत बाइस बार मां बनीं, लेकिन उनके अट्ठारह बच्चे ही ज़िंदा रहे. बाड़मेर चार साल पहले भी सुर्ख़ियों में आया था, जब किसान विरमाराम 88 साल की उम्र में पिता बने थे. जन्नत सिंधी मुसलमान बिरादरी की हैं, जो सरहद पार बड़ी तादाद में आबाद हैं. स्थानीय निवासी एवं शिक्षक खुदा बख्श कहते हैं, हमारी बिरादरी में तालीम बहुत कम है. प्राय बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता. उनका बचपन मवेशी चराने और खेत में काम करने में ही गुजरता है. यहां इतनी सुविधाएं भी नहीं हैं कि लोग नए ज़माने के मुताबिक़ ख़ुद को प्रगति की राह पर ले चलें. जब 2001 में जनगणना हुई थी तो राजस्थान ने जनसंख्या में भारी बढ़ोत्तरी दर्ज कराई थी. यहां एक हज़ार पुरुषों के मुकाबले 922 महिलाएं हैं, लेकिन बाड़मेर में एक हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र 892 है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
कारोबार में आंशिक लाभ हो सकता है. यदि आप नौकरीपेशा हैं और आर्थिक संकोच से गुजर रहे हैं तो किसी नई योजना में आपका शामिल होना एक अच्छी शुरुआत माना जाएगा. कुछ लोगों को जोख़िम लेने से ही फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अवांछित कार्य से बचना ज़रूरी होगा.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
पारिवारिक माहौल बेहतर रहेगा. ज़मीन-जायदाद, शेयर प्रतिभूतियों और बॉन्ड आदि में धन लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है. कारोबार की स्थितियां अगर ढीली भी चल रही हैं तो आप चिंता न करें.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
पेचीदा और लंबे खिंचने वाले मामले में जोखिम लेना ठीक नहीं रहेगा. कार्यक्षेत्र और कारोबार में तनाव बढ़ने से आपकी भागदौड़ भी बढ़ रही है. हो सकता है, कुछ ऐसी ही परेशानियों और जोखिम भरे कामों से सामना हो, लेकिन सप्ताहांत तक मानसिक शांति और संतोष मिल जाएगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
आप अपने परिवारीजनों को समझाने या अपनी बात कहने में असमर्थ रह सकते हैं. यदि नौकरी या सरकारी कार्यक्षेत्र से जुड़े हैं तो सब तरफ़ नज़र दौड़ाने की ज़रूरत होगी. कोई भी कमज़ोर कड़ी मुसीबत का पैगाम ला सकती है. जितना हो सके, सहज और सावधान रहकर अपना काम व्यवस्थित करें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
जब भी मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं तो आपके नज़दीकी, शुभचिंतक और परिवारीजन एक सहारा बनकर आगे आते हैं. इस सप्ताह भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां आएंगी, जब आपको जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
पिछली घटनाओं के चलते मन कुछ अशांत रहेगा. जो काम आपने पहले से ही निर्धारित कर रखे हैं, उनमें रुकावट आ सकती है. दोस्तों और सहकर्मियों से मतभेद पैदा होंगे. ख़र्च की मात्रा बढ़ने से बेचैनी हो सकती है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
जमा पूंजी को किसी अच्छे फंड या स्रोत में निवेश करना फ़ायदेमंद साबित होगा. यदि कोई खुदरा या थोक व्यापार करने की बात सोच रहे हैं तो भी समय का अच्छी तरह विश्लेषण कर लें. हो सकता है, जो धन आप अपनी उन्नति के लिए लगा रहे हैं, उसका लाभ तत्काल न मिल पाए.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
ख़ुद को सरकारी या ग़ैर सरकारी कामकाज पूरा करने में लगा दें. यदि विद्यार्थी हैं तो कुछ इधर-उधर के और रूमानी विचार विचलित कर सकते हैं. यदि कहीं पर आकर्षण महसूस कर रहे हों तो उसके पक्ष और विपक्ष पर अच्छी तरह विचार कर लें.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
आपको अपने शिक्षण-प्रशिक्षण पर अधिक जोर देना चाहिए. यदि आप किसी गंभीर विषय के जानकार हैं तो उसमें खुद को केंद्रित करना बेहतर होगा. आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी रचनात्मक कार्य थोड़े समय बाद लाभ देने में समर्थ हो जाएगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
सप्ताह व्यवसायिक और आर्थिक दृष्टि से उत्तम रहेगा. अच्छे समय और सौभाग्य के चलते आपको प्रत्येक कार्य में सहज ही सफलता मिल जाएगी. परिवार के कुछ जटिल उत्तरदायित्व भी पूर्ण करने में आप सक्षम होंगे.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
आपको अपना काम पूरा करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपका आत्मविश्वास ही इतना सबल और सक्षम बनेगा कि आप एक झटके में सफलता के द्वार पर खड़े होंगे. कारोबार में अच्छा लाभ होगा और किसी सुनियोजित कार्य में प्रगति होने से संतोष भी मिलेगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
यदि आप अपना काम छोड़कर किसी की मदद के लिए आगे आएंगे तो सप्ताह व्यर्थ की भागदौड़ और तनाव में व्यतीत होगा. आपको बार-बार अपने इरादे बदलने में दिक्कत आएगी. दूसरों की मदद करें, लेकिन अगर क्षमता कम है तो पीछे हट जाने में भी देर न करें.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

अमेरिका ने पाकिस्तान से उसी वक़्त स्पष्ट कह दिया था कि वह चरमपंथियों और आतंकियों का जड़ से खात्मा करने में उसकी मदद करे.

अमेरिकी पहाड़ के नीचे पाकिस्तानी ऊंट

राजीव रंजन तिवारी

सतही कूटनीति के सहारे ख़ुद को दबंग समझने वाले पाकिस्तान को अब उसकी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि कथित रूप से दुनिया के वास्तविक दबंग माने जाने वाले अमेरिका की नज़रें उस पर टेढ़ी हो गई हैं. इसका प्रमाण यह है कि अमेरिका न सिर्फ़ धीरे–धीरे पाकिस्तान को दी जाने वाली अपनी मदद घटाने लगा है, बल्कि अफ़ग़ानिस्तान से सटे कबायली इलाक़ों के बहाने उसने पाकिस्तान में ड्रोन हमले भी तेज कर दिए हैं. अमेरिकी चाल को समझते हुए पूर्व क्रिकेटर एवं राजनीतिज्ञ इमरान ख़ान सरीखे कुछ लोग अमेरिका के विरुद्ध आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि इससे कोई फ़र्क़ पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आज पाकिस्तान की सरजमीं पर शुरू हुआ अमेरिकी खेल कोई साधारण बात नहीं, बल्कि उसकी ख़ास रणनीति का हिस्सा जैसा प्रतीत हो रहा है. इससे लगता है कि पाकिस्तान लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका को समझा पाने में सफल नहीं हो पाएगा.

ग़ौरतलब है कि तालिबान का नकाब ओढ़े आतंकियों पर अमेरिका को गुस्सा तब आया, जब 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका में आतंकी हमले हुए. तमाम जांच–पड़ताल के बाद यह स्पष्ट हुआ कि इस मामले में तालिबानी आतंकी संगठन अलकायदा का हाथ है. अलकायदा के तमाम बड़े नेता 11 सितंबर, 2001 को पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूद थे और एक सुरक्षित मकान में बैठकर न्यूयार्क एवं वाशिंगटन का ताजा हाल टीवी पर देख रहे थे. फिर अलक़ायदा के सभी बड़े नेता अफ़ग़ानिस्तान चले गए. अमेरिका ने तालिबान को तबाह करने की ठान ली और इस कार्य में पाकिस्तानी सेना की मदद ली जाने लगी. नतीजतन, पाकिस्तानी सैनिकों की गोली से अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के वे चरमपंथी मारे जाने लगे, जिनसे पाक शासकों को मोहब्बत थी.

अमेरिका ने पाकिस्तान से उसी वक़्त स्पष्ट कह दिया था कि वह चरमपंथियों और आतंकियों का जड़ से खात्मा करने में उसकी मदद करे. इसके बदले अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को प्रति वर्ष 8 अरब डॉलर की सहायता भी दी जाने लगी. अब जब नए सिरे से अमेरिका द्वारा दी जाने वाली मदद और पाकिस्तानी कार्रवाइयों की समीक्षा हुई तो स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान के कबाइली इलाक़े मोहमंद में अब भी चरमपंथी जड़ जमाए बैठे हैं. यानी जिस उद्देश्य से उसने पाकिस्तान की मदद शुरू की थी, वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है. परिणामस्वरूप उसने अब पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद फ़िलहाल रोक दी है. हालांकि आधिकारिक रूप से आर्थिक मदद रोकने का कारण कुछ और बताया जा रहा है.

इसके अलावा अमेरिका और पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसियों के बीच उभरे मतभेद अब सेना तक जा पहुंचे हैं. पाकिस्तानी सेना के साथ रिश्ते बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी एडमिरल माइक मलन ने कई बार पाकिस्तान का दौरा करके वहां के सैन्य प्रमुख जनरल अशफ़ाक़ कयानी के साथ संबंध बनाने में असामान्य रूप से बहुत अधिक वक़्त लगाया. अफ़ग़ानिस्तान में वर्ष 2001 में तालिबान सरकार को हटाने के बाद उभरे मतभेदों के बावजूद अमेरिकी सेना से रिश्ते मधुर बनाने में जनरल कयानी ने भी पर्याप्त समय और ऊर्जा लगाई. बावजूद इसके पाकिस्तानी सेना शुरू से ही काबुल में अफ़ग़ान नॉर्दन एलायंस के क़ाबिज़ होने का विरोध करती रही है. अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की विद्रोही गतिविधियां दोनों देशों के लिए सिरदर्द बनी हैं. दोनों के बीच मतभेद तब और उभरे, जब अफ़ग़ान तालिबान के शीर्ष कमांडरों को पाकिस्तान ने पनाह दी और उनका समर्थन किया. तालिबान ने ही वर्ष 2003 के बाद अफ़ग़ानिस्तान में विद्रोह शुरू किया. नतीजतन, अमेरिकी–नाटो सेना को डेढ़ लाख सैनिक तैनात करने पड़े और बाक़ायदा युद्ध शुरू हो गया. यह युद्ध पाकिस्तान में तालिबान के संगठित होने का कारण बना, जिसे पहले तो पाकिस्तान ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब वह एक बड़ी समस्या बन गया है. अब पाकिस्तान इस बात से डरने लगा है कि अमेरिका ने उसकी जो सूचनाएं एकत्र की हैं, उनका उपयोग करके वह एक दिन उसकी परमाणु हथियार प्रणाली को भेद लेगा.

व्हाइट हाऊस ने अपनी रिपोर्ट में आतंकवाद के ख़िलाफ़ चले युद्ध को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि पाकिस्तान के अशांत इलाक़ों में एक लाख सैंतालिस हज़ार सैनिक तैनात होने के बावजूद पाकिस्तान के पास चरमपंथ को ख़त्म करने के लिए कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है. हालांकि पाकिस्तान ने अमेरिका के इन आरोपों का खंडन किया था, लेकिन दोनों देशों केबीच तनाव क़ायम है.

इमरान खान

दूसरी ओर अमेरिका को डर है कि कुछ ख़ास संगठनों पर नकेल कसने से पाकिस्तान का इंकार अमेरिका और यूरोप में चरमपंथी हमलों की वजह बन सकता है, जिसके चलते पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई की मांग भी बढ़ सकती है. इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि पश्चिम और भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों में पाकिस्तानी तालिबान का हाथ रहा है या फिर लश्कर–ए–तैयबा का. तमाम प्रयासों के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को यह समझाने में विफल रहा है कि कुछ चरमपंथी संगठनों से दोस्ती करना और कुछ से निपटना ऐसी नीति है, जो देश और वैश्विक सुरक्षा के लिए आवश्यक है. रणनीतिक रूप से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो दूरियां आई हैं, उनसे पार पाना अब संभव नहीं दिखता. ड्रोन हमलों को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है. इसमें चालक रहित विमान यानी ड्रोन के प्रयोग और सीआईए की तैनाती का मसला है और पाकिस्तान की ओर से जलालुद्दीन हक़्क़ानी और लश्कर–ए–तैयबा को दिए जाने वाले समर्थन का मसला भी.

उल्लेखनीय है कि हाल में अमेरिकी सैन्य अधिकारी मलन ने कहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों में तनाव का सबसे बड़ा कारण ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई है, क्योंकि वह चरमपंथी गुट हक़्क़ानी नेटवर्क के संपर्क में है, जो अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद अंतरराष्ट्रीय सेना पर हमले करता है. इससे पहले व्हाइट हाऊस ने अपनी रिपोर्ट में आतंकवाद के ख़िलाफ़ चले युद्ध को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि पाकिस्तान के अशांत इलाक़ों में एक लाख सैंतालिस हज़ार सैनिक तैनात होने के बावजूद पाकिस्तान के पास चरमपंथ को ख़त्म करने के लिए कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है. हालांकि पाकिस्तान ने अमेरिका के इन आरोपों का खंडन किया था, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव क़ायम है. मौजूदा स्थिति यह है कि अमेरिकी ड्रोन पाकिस्तान के कबाइली इलाक़े मोहमंद में लगातार हमले कर रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं. इसे लेकर पाकिस्तान सरकार में खासी बेचैनी है.

दिलचस्प यह है कि पाकिस्तानी शासकों के विरुद्ध सैनिकों में भी आक्रोश है, क्योंकि उनके सामने ही अमेरिकी ड्रोन पाकिस्तानी इलाक़ों को तबाह कर रहे हैं और शासन द्वारा कोई क़दम उठाने के बजाय अमेरिकापरस्ती दिखाई जा रही है. सैनिक चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिकी ड्रोन के विरुद्ध अपने एफ–16 लड़ाकू विमान उतार दे, जो ड्रोन को मार गिराने में सक्षम हैं. बहरहाल, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जिसमें नुक़सान सिर्फ़ पाकिस्तान का होगा, अमेरिका का नहीं. रामचरित मानस में भी कहा गया है, समरथ को नहीं दोष गोसाईं...

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
स्पेशल रिपोर्ट
नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

मुस्लिम शासकों के पतन और बर्तानिया हुकूमत की शुरुआत का यह समय सभ्यता के विचलन की वजह बन सकता था, लेकिन साई सांस्कृतिक दूत बनकर सामने आए.

जाकी रही भावना जैसी

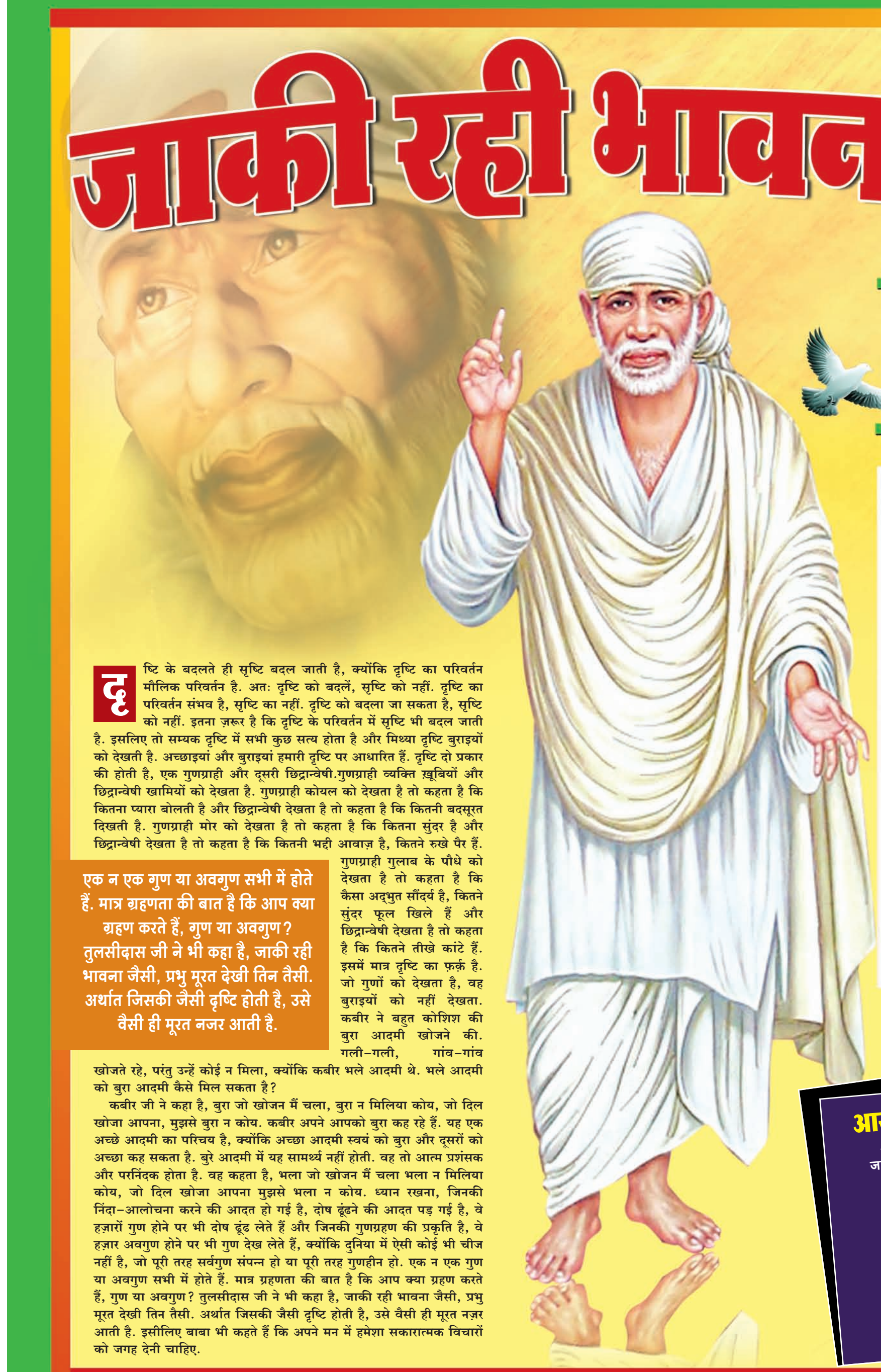

मां होने के कारण नारी का स्थान भगवान से भी ऊंचा है.

प्रेमचंद

विचारों को दबाया नहीं जा सकता. एक दिन विचार कंदरा फोड़ कर संसार पर छा जाते हैं.

स्व. तारा चंद्र मेहरोत्रा

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, क्योंकि दृष्टि का परिवर्तन मौलिक परिवर्तन है. अतः दृष्टि को बदलें, सृष्टि को नहीं. दृष्टि का परिवर्तन संभव है, सृष्टि का नहीं. दृष्टि को बदला जा सकता है, सृष्टि को नहीं. इतना ज़रूर है कि दृष्टि के परिवर्तन में सृष्टि भी बदल जाती है. इसलिए तो सम्यक दृष्टि में सभी कुछ सत्य होता है और मिथ्या दृष्टि बुराइयों को देखती है. अच्छाइयां और बुराइयां हमारी दृष्टि पर आधारित हैं. दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक गुणग्राही और दूसरी छिद्रान्वेषी.गुणग्राही व्यक्ति ख़ूबियों और छिद्रान्वेषी खामियों को देखता है. गुणग्राही कोयल को देखता है तो कहता है कि कितना प्यारा बोलती है और छिद्रान्वेषी देखता है तो कहता है कि कितनी बदसूरत दिखती है. गुणग्राही मोर को देखता है तो कहता है कि कितना सुंदर है और छिद्रान्वेषी देखता है तो कहता है कि कितनी भद्दी आवाज़ है, कितने रुखे पैर हैं. गुणग्राही गुलाब के पौधे को देखता है तो कहता है कि कैसा अद्भुत सौंदर्य है, कितने सुंदर फूल खिले हैं और छिद्रान्वेषी देखता है तो कहता है कि कितने तीखे कांटे हैं. इसमें मात्र दृष्टि का फ़र्क़ है. जो गुणों को देखता है, वह बुराइयों को नहीं देखता. कबीर ने बहुत कोशिश की बुरा आदमी खोजने की. गली–गली, गांव–गांव खोजते रहे, परंतु उन्हें कोई न मिला, क्योंकि कबीर भले आदमी थे. भले आदमी को बुरा आदमी कैसे मिल सकता है?

एक न एक गुण या अवगुण सभी में होते हैं. मात्र ग्रहणता की बात है कि आप क्या ग्रहण करते हैं, गुण या अवगुण? तुलसीदास जी ने भी कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. अर्थात जिसकी जैसी दृष्टि होती है, उसे वैसी ही मूरत नजर आती है.

कबीर जी ने कहा है, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय. कबीर अपने आपको बुरा कह रहे हैं. यह एक अच्छे आदमी का परिचय है, क्योंकि अच्छा आदमी स्वयं को बुरा और दूसरों को अच्छा कह सकता है. बुरे आदमी में यह सामर्थ्य नहीं होती. वह तो आत्म प्रशंसक और परनिंदक होता है. वह कहता है, भला जो खोजन मैं चला भला न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे भला न कोय. ध्यान रखना, जिनकी निंदा–आलोचना करने की आदत हो गई है, दोष ढूंढने की आदत पड़ गई है, वे हज़ारों गुण होने पर भी दोष ढूंढ लेते हैं और जिनकी गुणग्रहण की प्रकृति है, वे हज़ार अवगुण होने पर भी गुण देख लेते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, जो पूरी तरह सर्वगुण संपन्न हो या पूरी तरह गुणहीन हो. एक न एक गुण या अवगुण सभी में होते हैं. मात्र ग्रहणता की बात है कि आप क्या ग्रहण करते हैं, गुण या अवगुण? तुलसीदास जी ने भी कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. अर्थात जिसकी जैसी दृष्टि होती है, उसे वैसी ही मूरत नज़र आती है. इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचारों को जगह देनी चाहिए.

आरती श्री शिरडी के साईबाबा की

आरती श्री साई गुरूवर की, परमानंद सदा सुखवर की
जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख, शोक, संकट, भयहारी
शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया
कितने भक्त चरण पर आए, वे सुख शांति चिरतंन पाए
भाव धरे मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही वैसा
गुरू की लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को
साई नाम सदा जा गावे, सो फल जग में शाश्वत पावे
गुरूबारसर करि पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा
राम, कृष्ण, हनुमान रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में
विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन से इच्छित फल पाते
जय बोलो साई बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरू की
साईदास आरती को गावे, घर में बसि सुख मंगल पावे.

बाबा का सहृदय प्रेम

प्राणी मात्र की पीड़ा हरने वाले साई हरदम कहते हैं कि मैं मानवता की सेवा के लिए ही पैदा हुआ हूं. मेरा उद्देश्य शिरडी को ऐसा स्थल बनाना है, जहां न कोई ग़रीब होगा और न अमीर. कोई खाई, कैसी भी दीवार बाबा की कृपा पाने में बाधा नहीं बनती. बाबा कहते हैं, मैं शिरडी में रहता हूं, लेकिन हर श्रद्धालु के दिल में मुझे ढूंढ सकते हो. एक के और सबके. जो श्रद्धा रखता है, वह मुझे अपने पास पाता है. साई ने कोई भारी-भरकम बात नहीं कही. वह वही बोले, जो हर संत ने कहा. बाबा कहते हैं कि सबको प्यार करो, क्योंकि मैं सब में हूं. अगर तुम पशुओं और सभी मनुष्यों को प्रेम करोगे तो मुझे पाने में कभी असफल नहीं होगे. यहां मैं का मतलब साई की स्थूल उपस्थिति से नहीं है. साई तो प्रभु के ही अवतार थे और गुरु भी, जो अंधकार से मुक्ति प्रदान करता है. ईश्वर के प्रति भक्ति और साई गुरु के चरणों में श्रद्धा से ही बनता है इष्ट से सामीप्य का संयोग. दैन्यता का नाश करने वाले साई ने साफ कहा, एक बार शिरडी की धरती छू लो, हर कष्ट छूट जाएगा. बाबा केचमत्कारों की चर्चा बहुत होती है,

अगर तुम पशुओं और सभी मनुष्यों को प्रेम करोगे तो मुझे पाने में कभी असफल नहीं होगे. यहां मैं का मतलब साई की स्थूल उपस्थिति से नहीं है. साई तो प्रभु के ही अवतार थे और गुरु भी, जो अंधकार से मुक्ति प्रदान करता है.

लेकिन स्वयं साई नश्वर संसार और देह को महत्व नहीं देते थे. भक्तों को उन्होंने सांत्वना दी थी कि जब पार्थिव देह न होगी, तब भी तुम मुझे अपने पास पाओगे. अहंकार से मुक्ति और संपूर्ण समर्पण के बिना साई नहीं मिलते. कृपापुंज बाबा कहते हैं, पहले मेरे पास आओ, ख़ुद को समर्पित करो, फिर देखो. वैसे भी जब तक मैं का व्यर्थ भाव नष्ट नहीं होता, प्रभु की कृपा कहां प्राप्त होती है. साई ने भी चेतावनी दी थी, एक बार मेरी ओर देखो, निश्चित रूप से मैं तुम्हारी तरफ़ देखूंगा. वर्ष 1854 में बाबा शिरडी आए और 1918 में उन्होंने देह त्याग दी. चंद दशकों में वह सांस्कृतिक-धार्मिक मूल्यों को नई पहचान दे गए. मुस्लिम शासकों के पतन और बर्तानिया हुकूमत की शुरुआत का यह समय सभ्यता के विचलन की वजह बन सकता था, लेकिन साई सांस्कृतिक दूत बनकर सामने आए. उन्होंने जन-जन की पीड़ा हरी और उन्हें जगाया, प्रेरित किया युद्ध के लिए. युद्ध किसी शासन से नहीं, कुरीतियों से, अंधकार से और हर तरह की गुलामी से भी! यह सब कुछ मानव मात्र में असीमित साहस का संचार करने के उपक्रम की तरह था. हिंदू, पारसी, मुस्लिम, ईसाई और सिख, हर धर्म और पंथ के लोगों ने साई को अपना आदर्श माना और उनकी राह पर चले.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सम्मेलन के आख़िरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने पहुंच कर जो समां बाधा, उससे देश-विदेश से आए भोजपुरी प्रतिनिधि काफी गदगद दिखे.

अनंत विजय

चमकीली दुनिया, काला सच

उपन्यास में आत्मकथ्य की परंपरा हिंदी में बहुत पुरानी है. अपनी रचना में मैं को प्रतिस्थापित करने से एक तो रचना की विश्वसनीयता बढ़ जाती है और दूसरे कल्पना के भंवरजाल से मुक्त होकर कृति एक नया आयाम प्रस्तुत करती है. हिंदी उपन्यास में अपनी कहानी का प्रयोग सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, जब उन्होंने एक कहानी–कुछ आपबीती कुछ जगबीती की रचना की थी. हम कह सकते हैं कि यहीं से हिंदी में पाठकों से सीधे–सीधे मुख़ातिब होने की परंपरा की शुरुआत हुई. बाद में भी कई लेखकों ने इस परंपरा को अपनाया और हिंदी में कई शानदार कृतियां सामने आईं, जिनमें शिवपूजन सहाय की देहाती दुनिया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की शेखर एक जीवनी के दो खंड, आगे चलकर अमृतलाल नागर का उपन्यास अमृत और विष से लेकर राजेंद्र यादव की मुड़–मुड़ के देखता हूं और मैत्रेयी पुष्पा की कस्तूरी कुंडल बसै तक की काफी चर्चा हुई. कई उपन्यासों में कहानी मैं के बहाने कही गई तो कई में मैं को छुपाकर दास्तानगोई की गई. इस तरह का प्रयोग करने वाले लेखक अपनी रचना में आत्मवृत्त का उपयोग तो करते हैं, लेकिन साथ ही उपन्यास को आत्मकथा न मानने का आग्रह भी होता है. इस वजह से कई बार भ्रांतियां भी फैलती हैं.

हाल के दिनों में कई उपन्यास आए, जिनमें मैं को केंद्र में रखकर सीधे पाठकों से संवाद क़ायम किया गया है. पिछले दिनों वरिष्ठ कथाकार और नया ज्ञानोदय के संपादक रवींद्र कालिया का 17 रानडे रोड और अब वरिष्ठ कथाकार असगर वजाहत का उपन्यास पहर दोपहर प्रकाशित हुआ है. असग़र वजाहत के उपन्यास में सीधे–सीधे मैं को प्रतिस्थापित किया गया है. असगर वजाहत ने अपने इस उपन्यास में मायानगरी मुंबई की चमक–दमक की दुनिया को विषय बनाया है. रवींद्र कालिया और असगर वजाहत के उपन्यास लगभग एक जैसे ही हैं. ज़ाहिर तौर पर दोनों उपन्यासों में बॉलीवुड है, वहां की स्थितियां हैं, वहां का समाज है, इसलिए कई घटनाएं समान भी हैं. दोनों ही उपन्यासों का लंबा हिस्सा एक फ्लैट के अंदर गुजरता है. दोनों ही कथाकारों के पास भाषा की समृद्धि है, जो उनके उपन्यास में परिलक्षित भी होती है.

असगर वजाहत के इस नए उपन्यास पहर दोपहर का बड़ा हिस्सा पात्रों के बीच होने वाले संवाद से बनता है. इस संवाद के केंद्र में लेखक ख़ुद अपने नाम असग़र से ही मौजूद रहता है और पूरा का पूरा उपन्यास उनके दोस्त जालिब के मुंबई स्थित फ्लैट से ही संचालित होता है. जालिब को असगर काफी पुराने दिनों से जानते हैं. जालिब हैदराबाद के निज़ाम के प्रमुख मंत्री हश्मतयारजंग के बिगड़ैल बेटे थे, जो पहले ऐशोआराम की ज़िंदगी बसर कर रहे थे. असगर कहते हैं कि जब जालिब आठवीं क्लास में थे, तब ही उनके पास आस्टिन गाड़ी और रखैल दोनों थीं, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद अय्याशी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और जब खाने के लाले पड़े तो जालिब ने मुंबई का रुख़ कर लिया. यह इस उपन्यास के शुरू होने की कहानी से पहले की कहानी है. असल में उपन्यास शुरू होता है लेखक के मुंबई पहुंचने से. लेखक इस मंसूबे के साथ मुंबई आता है कि वह फिल्मों के लिए लेखन करेगा. मुंबई पहुंच कर असगर अपने दोस्त जालिब के घर पर पहुंचते हैं, जो कि कुछ फिल्में लिखकर फिल्मी दुनिया में स्थापित हो चुका होता है. वहां उनकी मुलाक़ात उसके दोस्तों सुल्ताना, मिर्जा साहब, मानस, हैदर साहब, पिया, रतनसेन एवं उसकी पत्नी नीना आदि से होती है. इसके अलावा जालिब का एक बेहद दिलचस्प चेला जसिया भी है, जो एक रोल की चाहत में जालिब की सेवा में लगा है, इस उम्मीद में कि जालिब से कोई फिल्म प्रोड्यूसर कहानी लिखवाएगा और जालिब साहब अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उसे फिल्म में कोई छोटा–मोटा रोल दिला देंगे.

उपन्यास का कथानक एकदम से अपेक्षित लाइन पर चलता है. कैसे पुराने जमाने की हीरोइन काम न मिलने से डिप्रेशन में चली जाती है और किस तरह फिल्म बनाने की चाहत में मुंबई पहुंचे धनपशुओं का वहां शोषण होता है. किस तरह महिलाओं और लड़कियों की चाहत में मुंबई में परिवार उजड़ते हैं, किस तरह घर पर पत्नी और बच्चों के रहते फिल्म से जुड़े लोग अपनी महिला मित्रों के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाकर सुकून पाते हैं. यह सब कुछ इस उपन्यास में है. असगर वजाहत के इस उपन्यास में ऐसा कुछ भी नया नहीं है, जो पाठकों को चौंकाता हो. असगर ने अपने इस उपन्यास में सेक्स का तड़का भी लगाया है. एक तो जालिब और शकुन के बीच के अंतरंग प्रसंग और दूसरा शराब के नशे में मानस का मीना के घर पहुंचना और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का वर्णन. असगर ने सेक्स का तड़का लगाया तो है, लेकिन ज़ायका ख़राब नहीं किया है. मानस और उसकी प्रेमिका मीना के अंतरंग क्षणों का वर्णन करते हुए असग़र लिखते हैं, शायद उन्हें लग रहा था कि वे नितांत एकांत में समुद्र के किनारे रेत पर लेटे हैं, आसमान में बहुत दूर उड़ते हुए परिंदों को छोड़कर उन्हें देखने वाला कोई नहीं है. इस नैसर्गिक एकांत में मानस और मीना एक दूसरे के इतने पास आ चुके हैं कि उससे अधिक पास होना संभव नहीं था. इस प्रसंग का अंत देखिए, दादा ने कांपते हाथों से एक चादर उठाकर उन दोनों पर डाल दी और फिर अपनी कविताएं सुनाने लगे. उनकी पीठ के ठीक पीछे महाकाव्य रचा जा रहा था.

पहर दोपहर में फिल्मी दुनिया के लटकों–झटकों के अलावा भी कई ऐसे प्रसंग हैं, जो वहां होने वाली घटनाओं और एक्सप्लाइटेशन को सामने लाते हैं, चमकीली दुनिया के काले सच को उघाड़ते हैं. जैसे जालिब के घर पर जब शकुन और मनोहर क़ब्ज़ा करने की सोचते हैं तो किस तरह अंडरवर्ल्ड का सहारा लिया जाता है, जो कि बाद में ख़ुद जालिब के गले की हड्डी बन जाता है. अंडरवर्ल्ड का गुंडा न केवल शकुन पर क़ब्ज़ा कर लेता है, बल्कि उसकी नज़र जालिब के फ्लैट पर भी लग जाती है. बात इतनी बढ़ जाती है कि जालिब को लगता है कि अब तो उसका प्लैट उसके हाथ से गया. लेकिन उसी वक़्त उसके काम आता है एक परिचित, जो कि किसी पुलिस वाले को जानता है और उसकी मदद के बाद ही जालिब का फ्लैट उस गुंडे से आज़ाद हो पाता है. इसके अलावा प्रोड्यूसर से पैसे वसूलने के लिए किस तरह अंडरवर्ल्ड की मदद ली जाती है, इसका संकेत भी इस उपन्यास में मिलता है. जब जालिब और रतनसेन के बीच मनमुटाव से बढ़कर बात तू–तू मैं–मैं तक पहुंच जाती है तो फिर वह रतनसेन से पैसे निकलवाने के लिए डॉन को तलाशता है.

कुल मिलाकर अगर हम असगर के इस उपन्यास पर समग्रता से विचार करें तो कह सकते हैं कि संवाद के केंद्र में मैं को रखकर जिस तरह वास्तविक घटनाओं को नाटकीयता के साथ प्रस्तुत किया गया है, उससे उपन्यास की पठनीयता तो बनती है, लेकिन अगर हम विषयवस्तु के तौर पर देखें तो नया कुछ हासिल नहीं होता. ब्लर्ब पर आंशिक तौर पर सही ही लिखा गया है, पहर दोपहर में नाटकीयता के कारण एक ऐसी पठनीयता है, जो बहुत दुर्लभ है. आंशिक इस वजह से कि यह पठनीयता हिंदी में दुर्लभ नहीं है.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

देवभूमि में भोजपुरी की गूंज

उत्तराखंड के मैदानी भाग से लेकर पहाड़ तक भोजपुरी समाज की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है. इसके बावजूद सूबे के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वादा करके भी दसवें राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन में नहीं आए. इससे भोजपुरी समाज में उनकी जमकर किरकिरी हुई. आयोजक निशंक पर भोजपुरियों की उपेक्षा का आरोप लगाकर ख़ूब बिफरे. सम्मेलन में राजधानी देहरादून से लेकर नैनीताल तक, धर्म नगरी हरिद्वार से लेकर पावन बद्री–केदार तक भोजपुरिया लोगों की मौजूदगी और राज्य के विकास में उनके योगदान की जमकर चर्चा हुई.

फोटो– *तिवारी बंधु*

सम्मेलन के आख़िरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने पहुंच कर जो समां बाधा, उससे देश–विदेश से आए भोजपुरी प्रतिनिधि काफी गदगद दिखे. तिवारी तीन बार अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. उन्होंने भोजपुरी भाषा की मधुरता और स्वतंत्रता आंदोलन में भोजपुरी समाज के योगदान की सराहना करके उपस्थित जनसमूह का आदर प्राप्त किया. इस अवसर पर तिवारी भी भोजपुरी समाज के मध्य पूरे रौब में दिखे. उन्होंने मंच से भोजपुरी गीत, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के ख़िलाफ़ स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बजाया था, सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया. उनके द्वारा गाए भोजपुरी गीत, राजा तोरी राजशहिया मिटाई देबई....ने ख़ूब वाहवाही बटोरी. तिवारी ने भोजपुरी भाषा की ख़ूबियों की सराहना करते हुए कहा कि इस भाषा की मिठास सभी को आकर्षित करती है. भोजपुरी को एक ओजस्वी भाषा बताते हुए उन्होंने इसके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया. मॉरीशस से आए डॉ. सबिता बुद्धू ने भोजपुरी साहित्य और भोजपुरी समाज की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए वहां भोजपुरी समाज की उपलब्धियों का बखान किया. संस्था के अंतरराष्ट्रीय महासचिव अरुणेश त्रिपाठी ने विश्व में भोजपुरी संस्कृति के प्रचार–प्रसार के बारे में प्रकाश डाला. इस अवसर पर भोजपुरी में प्रकाशित स्मारिका सखी का विमोचन किया गया. डॉ. अशोक त्रिपाठी ने भोजपुरी पर आयोजित वार्ता का सफल संयोजन किया.

सम्मेलन के पहले दिन लोक गायिका मालिनी अवस्थी द्वारा गाए भोजपुरी गीत, पिया को लिए जाए रे...रतिया बैरन, सुंदर सभूमि भैया भारत की...पर श्रोता थिरकते रहे. मिर्जापुर से आईं अंतरराष्ट्रीय कजरी गायिका उर्मिला श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत कजरी गीत, मां की आराधना सुनकर श्रोता भावविभोर हो गए. भोजपुरी गीत, हमें मेंहदी लियाई द मोतीझील से जाई के साइकिल से ना...पर उन्होंने ख़ूब तालियां बटोरीं. उर्मिला ने कजरी का संबंध प्रकृति और हरियाली से जोड़ते हुए कहा कि मां विंध्यवासिनी की आराधना के साथ ही कजरी हरियाली गीत भी है. इस धरती पर जब तक हरियाली रहेगी, तब तक कजरी भी रहेगी. इसी रात त्रिवेणी घाट पर पूर्वांचल नृत्य नाटिका मेघदूत एवं भिखारी ठाकुर भोजपुरिया लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही. सम्मेलन में चर्चित गायक हीरालाल यादव द्वारा गाए बिरहा और परमहंस चौरसिया द्वारा गाए निर्गुन ने खासी सराहना हासिल की. अंत में सभी कलाकारों को स्मृति चिन्ह एवं सम्मानपत्र दिए गए. पूर्व केंद्रीय मंत्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, अशोक सिंह, अजीत दूबे, सतीश त्रिपाठी, राजा वशिष्ठ, आचार्य पंकज, सुरेश त्रिपाठी, दीप शर्मा एवं आरती गौड़ समेत बड़ी संख्या में भोजपुरी समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हम किसी से कम नहीं का आभास कराते हुए सम्मेलन को सफल बनाया. उद्घाटन सांसद कलराज मिश्र, समाज के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश चंद्र त्रिपाठी एवं मनोहरकांत ध्यानी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित करके किया. यह पहला अवसर है कि अल्प सूचना पर ही भोजपुरी समाज के दिग्गजों ने अपने संसाधनों से ऋषिकेश पहुंच कर सम्मेलन में हिस्सा लिया.

राजकुमार शर्मा/पूजन अग्रवाल
feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

इस किताब में नारी के सवाल और अनाड़ी यानी लेखक के रोचक जवाब हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक ठहाके लगाने पर मजबूर हो जाएंगे.

पुस्तक का नाम : डाल पर खिली तितली
लेखक : अशोक चक्रधर
मूल्य : 95 रुपये
प्रकाशक : डायमंड पाकेट बुक्स

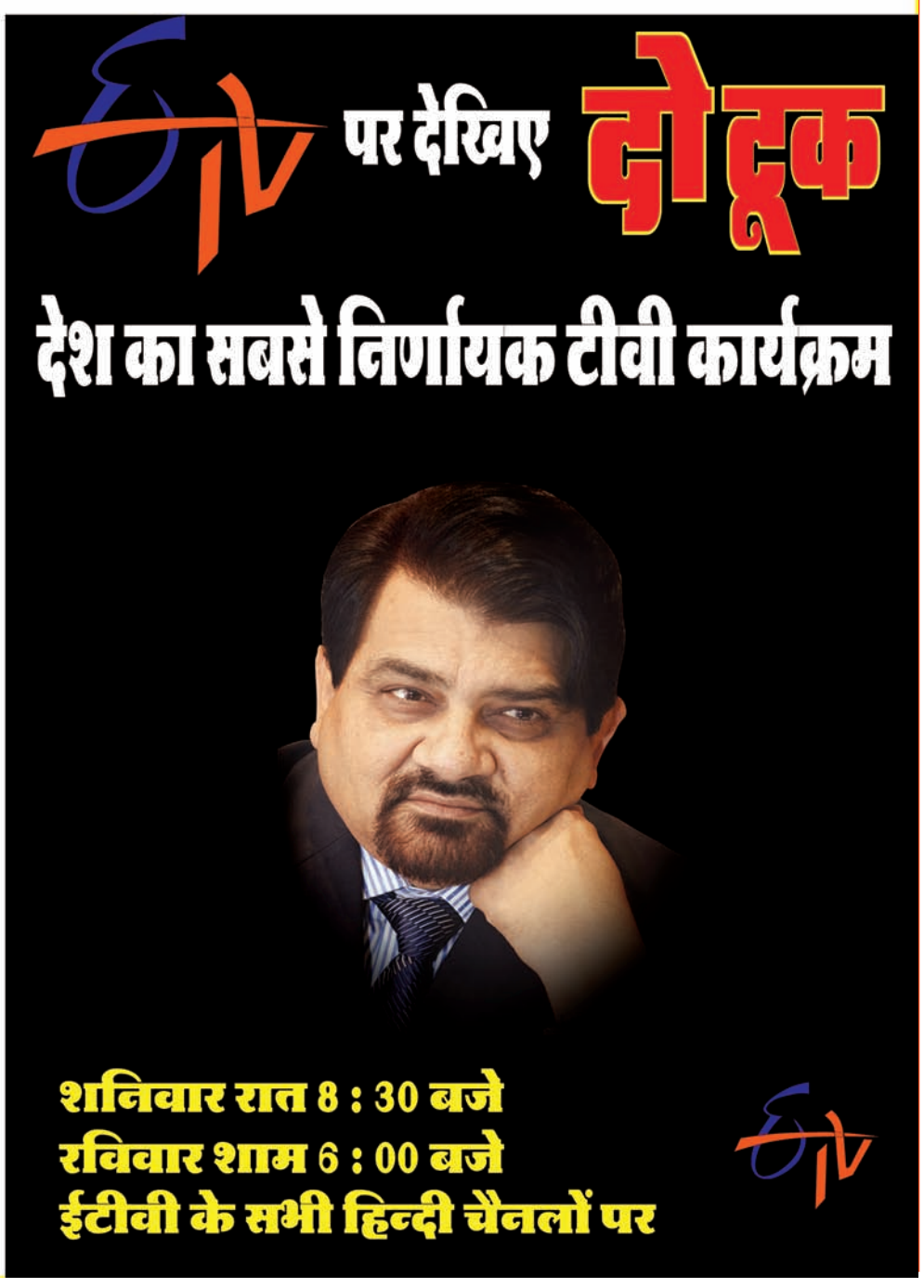

ग्रान कैब्रियो-4.7 दुनिया की सबसे ख़ूबसूरत कारों में से एक है. इसका रूफ मैकेनिज्म महज़ 20 सेकेंड में पूरी तरह फोल्ड हो जाता है. यह कार 285 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड देती है.

दिल्ली, 09 मई-15 मई 2011 चौथी दुनिया

सैमसंग की स्मार्ट तकनीक

भारतीय बाज़ार में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को लेकर अपनी स्थिति को मज़बूत बनाए रखने में सैमसंग ने 60 नए इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बाज़ार में उतारे हैं जिनमें मोबाइल, टेबलेट कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप रेफ्रिजिरेटर आदि शामिल हैं. कंपनी ने इस स्ट्रैटजी के तहत टेलीविज़न के 35 नए मॉडल, थ्री डी की रेंज को एक्सपैंड करने और गैजेट्स की श्रेणी में धूम मचा रही लेटेस्ट गैलेक्सी टैब और मोबाइल फोन लांच करने को लेकर उत्साहित है. इसके अलावा 60 इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की रेंज में नए रेंज के कैमरे, वाशिंग मशीन और रेफ्रिजेटर को भी शामिल किया गया है. कंपनी द्वारा किए गए इस ऐलान के मौक़े पर सैमसंग साउथ वेस्ट एशिया ऑपरेशंस के प्रेज़ीडेंट और सीईओ जंग सू चीन ने कहा कि भारत में व्यापार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ग्राहकों में युवाओं का प्रतिशत ज़्यादा होने की वजह से इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद के बड़े बाज़ार और उपभोक्ता हैं. कंपनी अपने पार्टनर एवं चैनल रिश्तों के प्रति प्रतिबद्धता क़ायम रखते हुए और साथ ही अपनी काबिलियत के अनुसार भारतीय बाज़ार में सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कंपनी बन सकती है. उन्होंने कहा कि कंपनी स्मार्ट तकनीक के निर्माण में निरंतर गतिशील है.

फोटो-सुनील मल्होत्रा

सैमसंग की स्मार्ट तकनीक पेश करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री सराह जेन और कंपनी के अधिकारी.

भारत आई सुपर बाइक

चंडीगढ़ एवं लुधियाना समेत देश भर में कुल 15 डीलरशिप खोलेगी. 2012 तक देहरादून में भी डीलरशिप का विचार है.

पुणे स्थित गरवारे मोटर्स ने कोरियाई कंपनी एसएंडटी मोटर्स के साथ मिलकर ह्योसंग सुपर बाइक्स भारत में लांच की है. कंपनी ने जीटीआर-650 आर (स्पोर्ट्स बाइक) की क़ीमत 4.75 लाख और एसटी-7 (क्रूजर बाइक) की क़ीमत 5.69 लाख रुपये निर्धारित की है. इन बाइकों की डिलीवरी

मध्य जून से शुरू हो जाएगी. जीटीआर में 650 सीसी का इंजन है, जबकि एसटी-7 में 700 सीसी का. लांच के मौक़े पर गरवारे मोटर्स की मैनेजिंग डायरेक्टर दीया गरवारे ने कहा कि कंपनी ने फ़िलहाल पुणे, मुंबई, दिल्ली-एन-सीआर, बंगलुरू एवं गोवा में अपनी डीलरशिप खोली है. कंपनी इस साल के अंत तक चंडीगढ़ एवं लुधियाना समेत देश भर में कुल 15 डीलरशिप खोलेगी. उन्होंने बताया कि 2012 तक देहरादून में भी डीलरशिप का विचार है. कंपनी को 2011 में लगभग 2,000 बाइक्स बिकने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि 650 और 700 सीसी की श्रेणी में अभी तक कोई बाइक देश में मौजूद नहीं है.

ख़ूबियों से लैस मोबाइल

बाज़ार में इन दिनों अजब-ग़ज़ब मोबाइल फोन लांच हो रहे हैं. जेन कंपनी ने भी एक मोबाइल फोन लांच किया है. इसमें सभी बातें दूसरे मोबाइल फोनों की तरह हैं, लेकिन इसकी कुछ ख़ूबियां इसे अन्य मोबाइलों से अलग करती हैं और वे हैं इसकी हैंड राइटिंग रिकगनेशन. मतलब कि यह मोबाइल आपकी हैंड राइटिंग पहचान सकता है. इस तरह की ख़ूबी वाले मोबाइल बहुत कम देखने को मिलते हैं. ख़ास बात यह है कि टच स्क्रीन होने के बावजूद इसकी क़ीमत सिर्फ़ 5000 रुपये है. इस फोन में 3.2 मेगा पिक्सल का कैमरा लगा है और एमपी थ्री और एमपी फोर को सपोर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी शामिल है. इसके अलावा फोन में मिनी ओपेरा और फेसबुक भी शामिल हैं.

आपके लिए ख़ास लाइटर

ये लाइटर रंग-बिरंगे हैं, जिन पर राशि चिन्ह के साथ उनके अनुमानित मतलब भी लिखे हैं. इसे चाहे आप अपने यूनिक स्टाइल में शामिल करें या प्रियजनों को बतौर तोहफ़ा दें.

जॉडियक साइन यानी राशि चिन्ह किसी भी शख़्स के व्यक्तित्व को दर्शाता है और कितना बढ़िया हो कि आप अपने साथ जॉडियक साइन वाला चिक एक्सेसरी लेकर चलें. जिप्पो नामक कंपनी ने जॉडियक साइन वाले लाइटर बनाए हैं. जिप्पो लाइटर एक्सेसरीज, कैंडल लाइटर, घड़ियां, परफ्यूम और पुरुष प्रसाधन की वस्तुएं बनाती है तथा इसका कारोबार 160 देशों में फैला हुआ है. जिप्पो की इस नई रेंज के लाइटरों में जो चिन्ह बने हैं, वे विभिन्न राशियों को दर्शाते हैं. ये लाइटर रंग-बिरंगे हैं, जिन पर राशि चिन्ह के साथ उनके अनुमानित मतलब भी लिखे हैं. इसे चाहे आप अपने यूनिक स्टाइल में शामिल करें या प्रियजनों को बतौर तोहफ़ा दें. जिप्पो के ये क्लासिक लाइटर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जिप्पोइंडिया डॉट कॉम पर इंटरनेट शॉपिंग के ज़रिए ख़रीदे जा सकते हैं या फिर देश के विभिन्न शहरों में खुले रिटेल स्टोरों से. इस ख़ास लाइटर की क़ीमत 2125 रुपये है. साथ ही जिप्पो की लाइफटाइम गारंटी भी दी गई है.

आ गया तूफ़ान

यह कार 285 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड देती है. जबकि क्वात्रापोर्ते स्पोर्ट्स जीटीएस-4.7 का 4.7 लीटर वी-8 इंजन 7,000 आरपीएम पर 440 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा करता है. इस कार का स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट सिस्टम इसे ज़्यादा मज़बूत बनाता है.

लक्जरी एवं स्पोर्ट्स कार निर्माता इतालवी कंपनी मसाराती ने भारत में अपनी कारें लांच करने का ऐलान कर दिया है. कंपनी भारत में अपनी पूरी कार रेंज लांच करेगी, जिनकी क़ीमत 1.20-1.43 करोड़ रुपये के बीच होगी. कंपनी भारत में अपने फ्लैगशिप मॉडल क्वात्रापोर्ते के अलावा ग्रान त्यूरिसमो और ग्रान कैब्रियो लांच कर रही है. उसने भारत में कारें आयात करने केलिए श्रेयांस ग्रुप को आधिकारिक साझीदार बनाया है. मसाराती के मैनेजिंग डायरेक्टर (एशिया-पैसेफिक) सिमॉन निकोलई ने कहा कि कंपनी मुंबई में अपना पहला शोरूम जल्द ही खोलेगी और उसके बाद 2012 में दिल्ली में दस्तक देगी. कंपनी 2015 तक देश के सात स्थानों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी. कंपनी को अगले तीन सालों के दौरान 100 कारें बिकने की उम्मीद है. निकोलई ने बताया कि कंपनी ने 2010 में दुनिया भर में 5,675 कारें बेचीं. कंपनी के प्रमुख बाज़ारों में अमेरिका, यूके, चीन, इटली, जर्मनी, जापान और फ्रांस शामिल हैं. ग्रान कैब्रियो-4.7 दुनिया की सबसे ख़ूबसूरत कारों में से एक है. इसका रूफ मैकेनिज्म महज़ 20 सेकेंड में पूरी तरह फोल्ड हो जाता है. यह कार 285 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड देती है. जबकि क्वात्रापोर्ते स्पोर्ट्स जीटीएस-4.7 का 4.7 लीटर वी-8 इंजन 7,000 आरपीएम पर 440 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा करता है. इस कार का स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट सिस्टम इसे ज़्यादा मज़बूत बनाता है. ग्रान त्यूरिसमो-4.2 कार 4.2 लीटर वी-8 इंजन से लैस है, जो 7,100 आरपीएम पर 405 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा करता है. यह कार 5.2 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है. इसकी टॉप स्पीड 285 किलोमीटर प्रति घंटा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

हम यह नहीं कह रहे हैं कि खिलाड़ी पैसा न कमाएं. पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वे किस तरह पैसा कमा रहे हैं, इस पर गौर करने की आवश्यकता है.

खिलाड़ियों को गुमराह करने की कोशिश

राजेश एस कुमार

मलिंगा का तर्क क्रिकेटरों की उस दुविधा को दर्शाता है, जिसमें एक तरफ़ तो आईपीएल की ओर से मिलने वाली भारी-भरकम राशि है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय टीम के प्रति ज़िम्मेदारी. अब यह तो खिलाड़ियों को ही तय करना है, क्योंकि जिस तरह मलिंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, उससे तो यही लगता है कि बलपूर्वक किसी को भी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं कराया जा सकता.

पिछले कुछ सालों में अगर भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर सकारात्मक रूप से उभरी है तो उसमें क्रिकेट का भी काफी योगदान रहा है. लंबे समय बाद देखा गया, जबकि भारतीय विदेशों में नहीं, बल्कि अपने ही देश में क्रिकेट के जरिए पैसा और अंतरराष्ट्रीय ख्याति हासिल कर रहे हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, हम कभी क्रिकेट के सरताज कहे जाने वाले देशों के खिलाड़ियों की नीलामी भी कर रहे हैं. आज हालत यह है कि क्रिकेट अप्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रीय खेल बन चुका है और यह सब हुआ आईपीएल की वजह से. लेकिन अति तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती. आईपीएल के साथ भी यही हुआ. मोदी और कलमाडी का हश्र तो दुनिया देख ही चुकी है. इन दोनों के घोटालों को देखते हुए यह वाजिब भी था, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि पैसा, ग्लैमर और चकाचौंध वाला यह आईपीएल इस जेंटलमैन गेम को ही बर्बाद करने पर तुला हुआ है.

जेंटलमैन इसलिए, क्योंकि एक दौर था, जब खिलाड़ी खेल के मैदान पर उतर कर एक-दूसरे से हाथ मिलाकर अपने-अपने देश का प्रतिनिधित्व करते थे और दर्शकों से भरा स्टेडियम अपने इन नायकों के लिए हवा में उछलता था. हर खिलाड़ी अपने देश की शान माना जाता था और आज भी सचिन जैसे लोग दुनिया भर के हीरो माने जाते हैं. लेकिन अब क्रिस गेल और मलिंगा जैसे खिलाड़ियों को देखिए, वेस्टइंडीज और श्रीलंका के ये धुरंधर खिलाड़ी पिछले कुछ समय से मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस बार की सुर्खियां किसी प्रदर्शन को लेकर नहीं, बल्कि इस बात पर हैं कि वे अपने देश के लिए खेलें या छप्पर फाड़कर नोटों की बरसात करने वाले आईपीएल के लिए. आखिर में इन दोनों खिलाड़ियों ने देश से ज़्यादा नोट को तवज्जो देते हुए आईपीएल को चुना. दोनों के ही अपने बहाने हैं. किसी को अपने देश के क्रिकेट बोर्ड से नाराजगी है तो कोई कोहनी में चोट की वजह से टेस्ट मैच से संन्यास ही ले रहा है.

गौरतलब है कि आईपीएल में खेल रहे श्रीलंकाई खिलाड़ियों को कुछ समय पहले उनके बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे की तैयारियों के लिए जल्द स्वदेश लौटने को कहा था. इसका मतलब यह था कि खिलाड़ी आईपीएल को बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौटें. इसका दूसरा मतलब यह भी था कि आईपीएल को बीच में छोड़ना यानी खिलाड़ियों का करोड़ों का नुकसान. इससे बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी. अंदर से तो ऐसी खबरें भी आईं कि श्रीलंका के खेल मंत्रालय को पर्याप्त मुनाफा नहीं मिला, इसीलिए वह खिलाड़ियों पर वापसी का दबाव बना रहा है. संगकारा कहते हैं कि यदि एफटीपी में नियमित तौर पर आईपीएल को जगह दी जाती है तो इस तरह के टकराव से बचा जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि आईपीएल के लिए खास जगह होनी चाहिए और बीसीसीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त टेस्ट क्रिकेट खेला जाए. आपको बता दें कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को 18 मई तक आईपीएल में खेलने की अनुमति दे दी है, लेकिन संगकारा कुछ दिन पहले इंग्लैंड दौरे पर चले जाएंगे. उन्होंने कहा, हमें 20 मई तक का समय दिया गया है. हमारा 16 और 21 मई को मैच है. मैं 16 मई के मैच के बाद लौट जाऊंगा.

अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये खिलाड़ी अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर स्वदेश रवाना हो सकते हैं तो क्या गेल और मलिंगा ऐसा नहीं कर सकते थे? इन दोनों मामलों में क्रिस गेल की बात पर थोड़ा यकीन किया जा सकता है. उनके मुताबिक, वहां के बोर्ड ने उन्हें चयन संबंधी प्रक्रिया से दरकिनार किया है, जिसकी वजह से उन्हें अपमान सहना पड़ा. लेकिन मलिंगा का मामला पूरी तरह अजीब और अलग है. उन्होंने तो अपने देश वापस जाने से बचने के लिए या यूं कहें कि अपना नुकसान बचाने के लिए टेस्ट क्रिकेट से ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी. यहां पर ताज्जुब वाली बात यह है कि इसके लिए उन्होंने घुटने की चोट को वजह बताया है. 27 वर्ष की उम्र में ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाला यह क्रिकेटर असल में शुरुआत से इस दुविधा में था कि वह पैसा चुने या अपना देश. इसी दुविधा का नतीजा है कि राष्ट्रीय टीम प्रबंधकों को अपने घायल होने की सूचना देकर लसिथ मलिंगा आईपीएल में खेल रहे हैं. मलिंगा के मामले में यह तर्क गले नहीं उतरता कि आईपीएल में तो सिर्फ़ चार ओवर फेंकने होते हैं.

मलिंगा का तर्क क्रिकेटरों की उस दुविधा को दर्शाता है, जिसमें एक तरफ़ तो आईपीएल की ओर से मिलने वाली भारी-भरकम राशि है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय टीम के प्रति ज़िम्मेदारी. अब यह तो खिलाड़ियों को ही तय करना है, क्योंकि जिस तरह मलिंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, उससे तो यही लगता है कि बलपूर्वक किसी को भी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं कराया जा सकता. यह अजीब सा लगता है कि वह घायल हैं, लेकिन फिर भी खेल रहे हैं. मेंडिस कहते हैं कि हमने मलिंगा को पत्र लिखकर घर लौटने को कहा था, लेकिन जवाब में मलिंगा ने यह कहा कि उनके घुटने में दर्द है, जिसकी वजह से वह टेस्ट सीरीज़ के लिए उपलब्ध नहीं हैं. दिलीप मेंडिस ने कड़ा रुख़ अख्तियार करते हुए यह भी कहा था कि अगर खिलाड़ी घायल है तो उसे तुरंत इलाज शुरू कर लेना चाहिए, ताकि वह अगर अपने देश के लिए खेलने में दिलचस्पी रखता है तो उसके लिए स्वस्थ हो सके. तिलकरत्ने दिलशान की कप्तानी में इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली श्रीलंकाई टीम एंजेलो मैथ्यू के घायल होने के कारण पहले ही गेंदबाज़ी के सीमित विकल्पों से जूझ रही है, लेकिन शायद मलिंगा को यह बात समझ में नहीं आई और उन्होंने इन सब झंझटों से पीछा छुड़ाने के लिए संन्यास लेना ही बेहतर समझा. अब उन्हें आईपीएल में खेलने से कोई भी नहीं रोक सकता. क्रिस गेल पर भी यही बात लागू होती है कि अगर उन्हें अपने देश के क्रिकेट बोर्ड से कोई नाराजगी थी तो इसका बहाना लेकर आप आईपीएल नहीं खेल सकते.

ऐसा नहीं है कि पैसे और ग्लैमर की चमक में सिर्फ विदेशी खिलाड़ी ही अंधे हुए हैं, हमारे खिलाड़ी भी कम नहीं हैं. यह तो अच्छा है कि आईपीएल हमारे देश में हो रहा है, नहीं तो किसी और देश में इन खिलाड़ियों की बोली लगती और ये भी घरेलू क्रिकेट को दरकिनार करते हुए पैसा कमाने की सोच बैठते. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभी हाल में धोनी समेत कई भारतीय खिलाड़ी वर्ल्डकप में मिलने वाली पुरस्कार राशि से खुश नहीं थे और उन्होंने बाकायदा विरोध दर्ज कराया. नतीजतन, भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने विश्वकप जीतने वाली भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को दी जानी वाली राशि एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दी. बीसीसीआई ने अपनी कार्यकारी समिति की बैठक में पुरस्कार-प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर दो करोड़ रुपये तो कर दी, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की मानें तो यह राशि अभी भी कम है, क्योंकि खिलाड़ियों की मांग पांच करोड़ रुपये थी.

हम यह नहीं कह रहे हैं कि खिलाड़ी पैसा न कमाएं. पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वे किस तरह पैसा कमा रहे हैं, इस पर गौर करने की आवश्यकता है. इसे किस तरह सही कहा जा सकता है कि आप अपने देश में होने वाले टूर्नामेंट को छोड़कर सिर्फ इसलिए आईपीएल में शामिल हों, क्योंकि वहां आपको अपने देश से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं. इस बात को खिलाड़ी क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें यह पैसा इसलिए मिल रहा है, क्योंकि वे अपने देश की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं. अगर वे अपने देश के स्टार खिलाड़ी नहीं होते तो आईपीएल तक कैसे पहुंचते? यह विडंबना है कि कुछ ही सालों पहले शुरू हुआ आईपीएल संस्करण अपने पैसों के दम पर खिलाड़ियों को बागी बना रहा है. यहां पर एक पक्ष यह भी है कि जब क्रिकेट से जुड़ा प्रबंधन करोड़ों में खेल रहा है और मोदी जैसे सूरमा बड़े-बड़े घोटाले कर रहे हैं तो ऐसे में खिलाड़ी पैसा क्यों न कमाएं. आईपीएल ने न सिर्फ खिलाड़ियों को खेमों में बांटा है, बल्कि उनके सामने लालच की एक ऐसी खाई खड़ी कर दी है, जिससे बचना सबके वश की बात नहीं है.

rajeshy@chauthiduniya.com

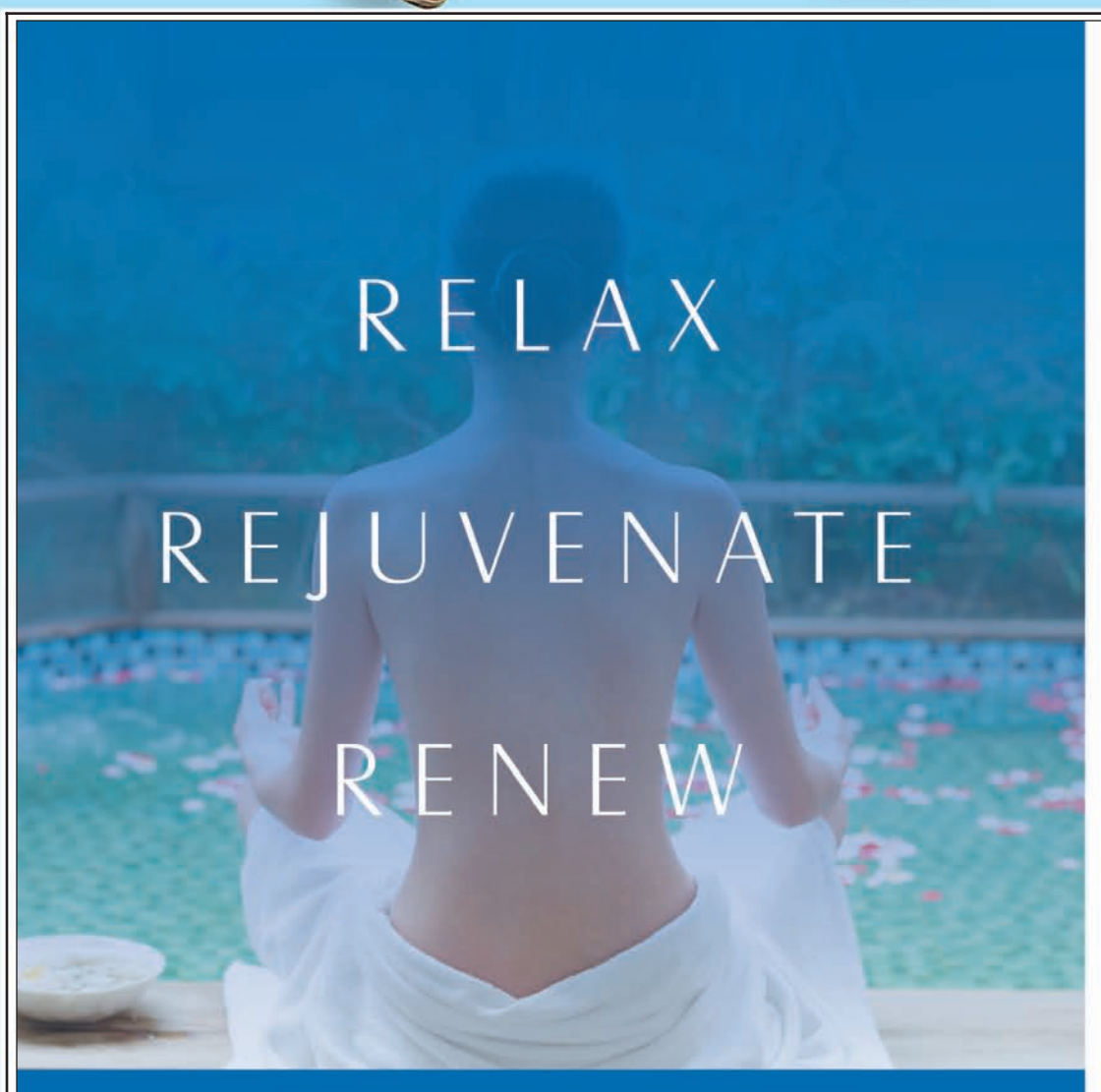

Due to a hectic lifestyle your body deserves a break. And that's precisely why we have come up with a spa right here at Fortune Inn Grazia, Noida. Managed by a renowned wellness facility development and management company, A5 Health Solutions, it offers you a pleasant ambience and ancient relaxation therapies. So, for a peaceful spa experience, visit our hotel.

Managed by:

FORTUNE Inn Grazia BY WELCOMGROUP Noida

Block I, Plot No. 1A, Sector 27, Noida - 201301, Uttar Pradesh
Tel: 91-120-3988444 Fax: 91-120-3380144 E-mail: grazia@fortunehotels.in

CRAYONS

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

शर्लिन ने मोदी की पीए बनने की इच्छा जताते हुए कहा, मोदी आई लव यू. वैसे शर्लिन की इस तारीफ़ के पीछे व्यवसायिक हित भी हो सकते हैं.

ब्यूटी विद ब्रेन

बॉलीवुड की हॉट अदाकारा शर्लिन चोपड़ा जानती हैं कि सुर्ख़ियों में कैसे बने रहा जा सकता है. इसलिए कभी वह टॉपलेस हो जाती हैं तो कभी अपनी बोल्ड बातों से सबको चौका देती हैं. हाल में शर्लिन ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हुए कहा कि मोदी जब बोलते हैं तो अच्छे-अच्छों की बोलती बंद हो जाती है. शर्लिन ने मोदी की पीए बनने की इच्छा जताते हुए कहा, मोदी आई लव यू. वैसे शर्लिन की इस तारीफ़ के पीछे व्यवसायिक हित भी हो सकते हैं. गुजराती महिलाओं द्वारा बनाए गए सामानों की एक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सूरत आईं शर्लिन ने कहा कि वह मोदी को बेहद पसंद करती हैं. उन्होंने नरेंद्र मोदी जैसा प्रभावशाली इंसान नहीं देखा. मोदी की शैली और खरा-खरा बोलने का अंदाज़ उन्हें बेहद पसंद है. अगर उन्हें मौक़ा मिला तो वह उनकी पर्सनल अस्टिटेंट बनना पसंद करेंगी. शर्लिन ने तो यह भी कहा कि मोदी से वह इसलिए प्रभावित हैं, क्योंकि वह हमेशा युवाओं के भविष्य, शिक्षा और विकास की बातें करते हैं. उनके चेहरे पर ग़ज़ब का आत्मविश्वास झलकता है. वैसे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और विकास मॉडल से कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता. अब तो उनके सिलेब्रिटीज़ फैंस में एक नया नाम जुड़ गया है.

रिया सेन का दुःख

बॉलीवुड अभिनेत्री रिया सेन ने क्रिकेटर श्रीसंथ के साथ समय बिताने की अफवाहों को नकार दिया है. रिया ने ट्विटर पर लिखा कि वह श्रीसंथ के साथ समय नहीं बिता रही थीं. वह आईपीएल की कोच्चि टीम के तीन क्रिकेट मैचों में शामिल हुई थीं और बात सिर्फ़ यहीं तक है. यह उनका काम था, बाक़ी सब कल्पनाएं हैं. रिया और श्रीसंथ की पहचान पुरानी है. एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए उन्होंने साथ-साथ विज्ञापन किया था. पहली मुलाक़ात में दोनों दोस्त बन गए. उसके बाद दोनों संपर्क में रहे और अब लगता है कि बात आगे बढ़ गई है. पिछले दिनों स्टेडियम में उपस्थित होकर रिया श्रीसंथ और उनकी टीम का उत्साह बढ़ाती देखी गईं. यह नज़ारा देख बॉलीवुड में चर्चा शुरू हो गई है कि बात अब दोस्ती से आगे बढ़ चुकी है. मैच ख़त्म होने के बाद रिया और श्रीसंथ पार्टी में साथ देखे गए. कोलकाता निवासिनी रिया केकेआर का समर्थन नहीं कर रही हैं. न ही मुंबई इंडियन की समर्थक हैं, जहां वह काम करती हैं. वह तो चाहती हैं कि इस बार आईपीएल का खिताब कोच्चि की टीम जीते. बताने की ज़रूरत नहीं है कि रिया कोच्चि के पक्ष में क्यों हैं. अभिनेत्री मुनमुन सेन की बेटी रिया के इससे पहले अभिनेता अस्मित पटेल से प्रेम संबंध थे. रिया और अस्मित पटेल के कथित एमएमएस वाली बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन रिया इस समय इसलिए दुःखी और सफाई देती फिर रही हैं, क्योंकि अपने गर्म मिजाज़ के लिए मशहूर एस श्रीसंथ अब शादी करने जा रहे हैं. यह लाइन पढ़ते ही आपके दिमाग़ में रिया सेन का नाम आया होगा, लेकिन उनके सपनों की रानी रिया नहीं, बल्कि कोई और है, जिसका खुलासा श्रीसंथ ने नहीं किया है.

जैसे को तैसा

कहते हैं, इतिहास ख़ुद को दोहराता है. लगता है कि सलमान ख़ान और रणबीर कपूर के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि रणबीर की रॉक स्टार सह कलाकार एवं गर्लफ्रेंड ने सल्लू का दामन थाम लिया है. दरअसल सलमान ख़ान के छोटे भाई सोहेल ख़ान एक फिल्म की स्क्रिप्ट पर काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं. अब वह इस स्क्रिप्ट पर शेर ख़ान नाम की फिल्म बनाने जा रहे हैं. इसके लिए जब उन्होंने हीरोइनों को लाइनअप किया तो उनमें से एक रणबीर की गर्लफ्रेंड नरगिस फाकरी भी शामिल थीं. हालांकि सोहेल चाहते थे कि वह इस फिल्म में किसी नए चेहरे को ही लांच करें, लेकिन सलमान के कहने पर उन्होंने नरगिस पर दांव लगाने का फ़ैसला किया. जबकि कैटरीना और सोनाक्षी भी इस फिल्म के दावेदारों की लिस्ट में शामिल थीं. रणबीर और नरगिस इम्तियाज अली की फिल्म रॉक स्टार में साथ नज़र आएंगे. फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस और रणबीर के रोमांस ने ख़ूब चर्चा बटोरी. सुनने में तो यहां तक आया कि नरगिस की वजह से रणबीर कपूर ने कैटरीना कैफ के साथ ब्रेकअप कर डाला. सलमान इस फिल्म में सुपर हीरो की इमेज में नज़र आएंगे. नरगिस फाकरी को उनकेनिर्देशक इम्तियाज अली ने मीडिया से दूर रहने के लिए कहा है. इसके बावजूद लोगों ने चर्चा शुरू कर दी है कि कैटरीना और नरगिस में बहुत समानताएं हैं.

दोनों ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और दोनों इसमें असफल रही थीं. दोनों विदेशी बालाएं हैं और बॉलीवुड में आने के बाद दोनों ही कई दिनों तक लुकाछिपी का खेल खेलती रहीं. दोनों एक सी दिखती हैं और सह अभिनेताओं के साथ इश्क लड़ाने के इल्ज़ाम ने दोनों को परेशान कर रखा है. एक और ख़ास बात इन्हें समान बनाती है कि दोनों की बहनें भी अब बॉलीवुड में एंट्री लेंगी. दरअसल, इन दिनों यह चर्चा जोरों पर है कि दोनों का कोई न कोई कनेक्शन है. ये पहले से एक-दूसरे को जानती होंगी और सगी संबंधी हैं. साथ ही यह कहा जा रहा है कि दोनों के जीन भी मिलते हैं. ग़ौर करें तो दोनों की शक्लें भी एक-दूसरे से मिलती हैं. इस बात को लेकर दोनों नायिकाएं परेशान हैं. उनका कहना है कि लोगों को बातें बनाने के लिए कोई भी मौक़ा चाहिए. हम तो अब तक एक-दूसरे से मिले भी नहीं हैं. दो साल पहले सलमान से उनकी गर्लफ्रेंड ले उड़ने वाले रणबीर की गर्लफ्रेंड भी कहीं अब सलमान के साथ न उड़ जाए यानी जैसे को तैसा.

माधुरी चली परदेस

धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित सबका दिल लूटने के बाद वापस अमेरिका जा रही हैं. चार महीने तक पूरे इंडिया को नचाने के बाद माधुरी ने फ़िलहाल बॉलीवुड को बाय-बाय कह दिया है. सूत्रों की मानें तो माधुरी एक अंतराल के बाद बॉलीवुड में वापसी करेंगी. वह बीते वर्ष नवंबर में छोटे पर्दे के एक शो झलक दिखला जा की जज बनने आई थीं. लगातार चार महीने तक चले इस शो में माधुरी ने प्रतियोगियों के साथ-साथ पूरे बॉलीवुड को नचाया. उम्रदराज हीरो भी माधुरी की अदा के सामने ख़ुद को रोक नहीं पाए. ऋषि कपूर ने माधुरी के साथ इस शो में जमकर ठुमके लगाए. बंगाली बाला रानी मुखर्जी तो माधुरी के हुस्न के सामने नतमस्तक हो गईं. झलक दिखला जा में आईं रानी ने माधुरी की तारीफ़ के पुल बांध दिए. किंग खान शाहरुख़ भी माधुरी के साथ ठुमके लगाते दिखे. माधुरी ने जब झलक दिखला जा में एक गाने पर अपनी कमर हिलाई तो कोरियोग्राफर सरोज ख़ान ने कहा कि माधुरी सबसे बेहतर हैं. जब बॉलीवुड के इतने सितारे माधुरी के हुस्न पर दिल हार रहे थे तो ऐसे में भला ऋतिक रोशन कैसे पीछे रहते? ऋतिक को भी कहना पड़ा कि माधुरी सबसे ख़ूबसूरत हैं. झलक दिखला जा का आयोजन पहले भी तीन बार हो चुका है, लेकिन इस बार माधुरी के जज बनने से शो को काफी लोकप्रियता मिली. माधुरी की वजह से छोटे पर्दे के दो बड़े शो कौन बनेगा करोड़पति और बिग बॉस को काफी चुनौती मिली. रजनीकांत अपनी फिल्म राना के लिए इस अदाकारा को साइन करना कहते थे, यही नहीं, अनिल कपूर ने भी माधुरी से एक फिल्म में सोनम कपूर की मां बनने को कहा, लेकिन उन्हें उक्त दोनों प्रस्ताव पसंद नहीं आए.

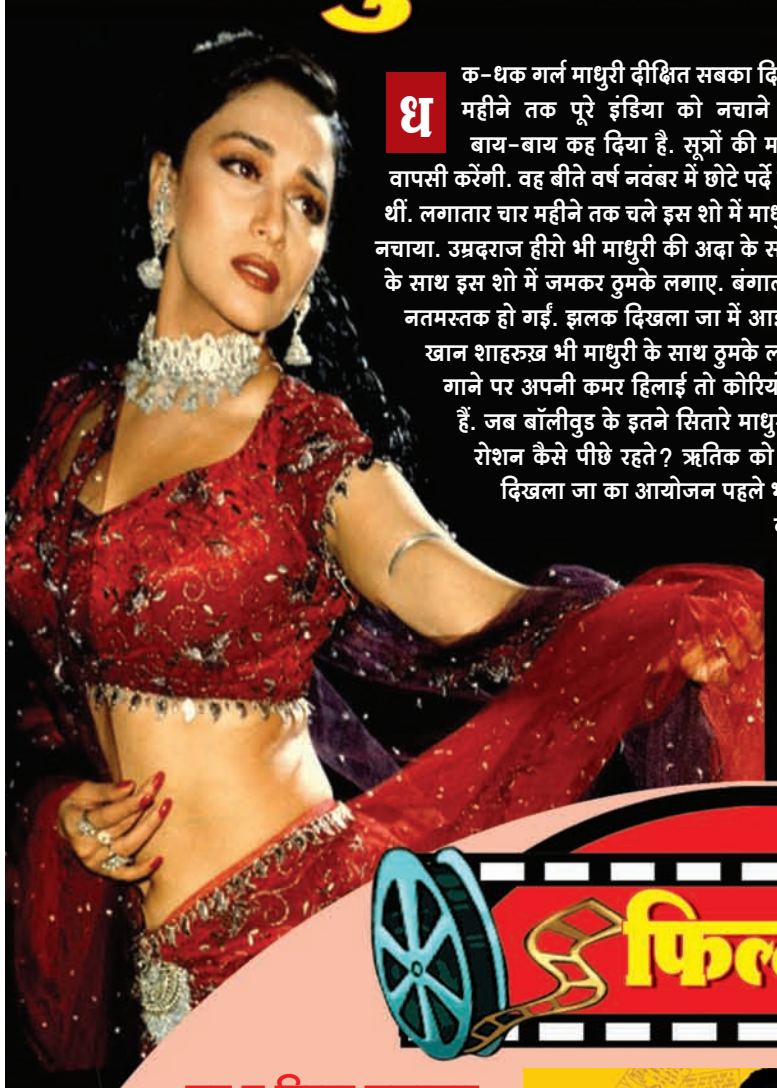

ख़ूबसूरती का संदेश

सेक्सी एवं हॉट नीतू चंद्रा ब्यूटी और फैशन टिप्स देती घूम रही हैं. उन्हें सफेद रंग पसंद है, ख़ासकर गर्मियों के मौसम में. उन्हें लगता है कि व्हाइट टॉप बेहद शालीन लगता है और व्हाइट कलर किसी की शख्सियत को ख़ास तरह का ग्लो देता है. नीतू की सलाह है कि फैशन-परस्त महिलाओं को अपने वॉर्डरोब में ज़्यादा से ज़्यादा सफेद टॉप रखने चाहिए. डेनिम्स को गर्म मौसम के लिए वॉर्डरोब से बाहर कर देना चाहिए. वह कहती हैं कि परफ्यूम्स एवं डियोंडरेंट्स गर्मियों में ज़रूरी हैं. हालांकि तेज फ्रेगरेंस को न ही चुनें तो बेहतर है. फ्लोरल और फ्रूटी फ्रेगरेंस गर्मियों के लिए बढ़िया हैं, क्योंकि ये माइल्ड होते हैं. इस वक़्त ट्रेंडी हेयर बैंड्स और क्लिप्स भी चलन में हैं, जिनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में बालों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता. नीतू कहती हैं कि बालों के सारे एक्सेसरीज इसी मौसम के लिए हैं. जहां तक ज्वेलरी की बात है तो नीतू सिंपल ही रहना चाहती हैं. उनके लिए छोटे से इयररिंग्स और लाइटवेट नेकपीस काफी हैं. त्वचा को टैनिंग से बचाने के लिए सनस्क्रीन को हमेशा साथ रखना चाहिए. वॉटर बेस्ड सनस्क्रीन त्वचा की सुरक्षा करता है. लड़कियों को अपने हैंडबैग में मेकअप की कुछ चीजें जैसे मस्कारा, ब्लश-ऑन या हल्के रंग का लिप ग्लॉस ज़रूर रखनी चाहिए. किसी भी बेसिक शेड में छोटा सा क्लच कई मौक़ों पर सूट करता है. ब्राउन या ग्रीन के शेड में एक स्लिंग बैग भी हो सकता है. शूज आपके फैशन सेंस को ज़ाहिर करते हैं. नीतू को ख़ास तौर पर कोल्हापुरी चप्पलें और फ्लैट्स पसंद हैं. अपने पूरे ड्रेसअप के साथ कोई ऐसा विचित्र एलीमेंट जोड़ लें, जो हटकर हो. अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि नीतू की ख़ूबसूरती का राज क्या है. नीतू की दरियादिली क़ाबिलेतारीफ़ है, क्योंकि जहां माना जाता है कि महिलाएं कभी अपने ब्यूटी सिक्रेट्स दूसरों को नहीं बतातीं, वहीं नीतू ने सबको ख़ूबसूरत दिखने का नुस्ख़ा बता दिया है.

नीतू कहती हैं कि बालों के सारे एक्सेसरीज इसी मौसम के लिए हैं. जहां तक ज्वेलरी की बात है तो नीतू सिंपल ही रहना चाहती हैं. उनके लिए छोटे से इयररिंग्स और लाइटवेट नेकपीस काफी हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

लव यू मिस्टर कलाकार

बॉलीवुड में नए फिल्म निर्देशकों की सूची में एक और शख्स अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार है. राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म लव यू मिस्टर कलाकार का निर्देशन युवा एस मनस्वी ने किया है. फिल्म में मुख्य भूमिकाएं तुषार कपूर, अमृता राव, राम कपूर, प्रेम चोपड़ा एवं किरण कुमार ने निभाई हैं. संगीत संदेश शांडिल्य ने दिया है. यह एक रोमांटिक फिल्म है. फिल्म विवाह की शर्मिली दुल्हन अमृता राव ने एक बार फिर राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म लव यू मिस्टर कलाकार में अपनी अदाकारी दिखाई है. हालांकि बॉलीवुड में अमृता का करियर धीमी गति के समाचारों की तरह आगे बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें इससे कोई शिकायत नहीं है. हो भी क्यों, आख़िर उन्होंने इंडस्ट्री में बिना गॉड फादर के अपनी जगह बनाई. वह कहती हैं, मैं ख़ुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूं कि फराह ख़ान, श्याम बेनेगल, राजकुमार संतोषी एवं सूरज बड़जात्या जैसे निर्देशकों ने मुझे अपनी फिल्मों के लायक़ समझा. गोलमाल के पर्याय बन चुके तुषार को इन दिनों राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म में भी काम करने का मौक़ा मिल गया है. वह लव यू मिस्टर कलाकार में अमृता राव के साथ नज़र आएंगे. दरअसल, लव यू मिस्टर कलाकार साहिल (तुषार कपूर) नामक एक कार्टूनिस्ट की कहानी है. अमृता राव (रितु) ने मैनेजमेंट ट्रेनी का किरदार निभाया है, जिसे साहिल से प्यार हो जाता है. अलग-अलग प्रोफेशन के दो लोग एक कैसे हो जाते हैं, फिल्म में इसे बख़ूबी दिखाया गया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 09 मई–15 मई 2011

www.chauthiduniya.com

नाज़ुक हाथों का लाल सलाम

देश के अति पिछड़े 25 ज़िलों की सूची में शुमार गड़चिरोली ज़िले का विकास विगत 30 वर्षों से नक्सलवाद की वजह से अधर में लटका है. केंद्र व राज्य सरकारों की अनेक योजनाओं के क्रियान्वित होने के बावजूद नक्सलवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बार तो नक्सवाद कर रूप भी बदल रहा है. अब दल की कमान महिलाओं के हाथों में है.

अंजीव पांडेय

नक्सलियों के दंडकारण्य राज्य में नक्सली अराजकता की तीव्रता तो वही है, लेकिन इसी संगठनात्मक संरचना कुछ बदले स्वरूप में है. कमोबेश अधिकतम दलों की कमान महिलाओं के हाथों में हैं. यहां तक कि निजी सुरक्षा के लिए भी महिलाओं को ही नियुक्त किया गया है. कोई अतिश्योक्ति नहीं, अगर कहा जाए कि नर्म कलाइयां एक तरफ़ लाल परचम तो दूसरी तरफ़ बंदूकें थाम नक्सली आतंक को नए अंजाम तक पहुंचाने की कवायद में हैं. वैसे तो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव सत्यनारायन रेड्डी उर्फ़ बोपन्ना उर्फ़ कोसा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गड़चिरोली ज़िले में काम शुरू है. मगर एकमात्र गड़चिरोली डिविजन की बात करें तो इस डिविजन की बागडोर ख़ूंख़ार महिला नक्सली 44 वर्षीय नर्मदा अक्का के हाथों में सौंपी गई है. नर्मदा के मार्गदर्शन में जो दल तैयार किए गए हैं, उसमें चातगांव दलम का कमांडर पद रजीता, कसनतुर रंजिता, गट्टा रामको, राजोली सुनीता, जिमलगट्टा सरोजा, खोब्रामों रंजीता व टीपाग दल का ज़िम्मा कमांडर ज्योति के हाथों में सौंपा गया है. विशेष बात तो यह है कि नर्मदा की निजी सुरक्षा के लिए भी महिलाओं को ही नियुक्त किया गया है. इसमें 24 वर्षीय प्रभावती व रूपा (21) का समावेश है. नर्मदा के नेतृत्व में अब तक अनेक वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है. स्पष्ट है कि या तो नक्सली ख़ेमा पुरुष प्रधान दायरे से बाहर निकलने की मशक्क़त कर रहा है या फिर नई रणनीति के तहत दलों की कमान महिलाओं के हाथ दे दी गई है.

सूत्र बताते हैं कि नक्सलवाद के रेड जोन में गड़चिरोली ज़िले को तीन हिस्सों में बांटा गया है. इनमें दक्षिण गड़चिरोली, उत्तर गड़चिरोली व गोंदिया डिविजन शामिल हैं. सूत्रों के अनुसार हर डिविजन में 20 से अधिक गुरिल्ला दल आज भी सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. एक गुरिल्ला दल में नक्सलियों की संख्या बढ़कर 30 के आसपास पहुंच गई है. एकमात्र गड़चिरोली ज़िले की 12 तहसीलों में नक्सलियों के 17 दल कार्यरत हैं. इसके अलावा ग्राम रक्षा दल व एरिया रक्षा दलों की संख्या आज भी है. ज़िले में 500 से 600 की संख्या में बंदूक़धारी नक्सली हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में एकमात्र गड़चिरोली ज़िला ऐसा है, जहां 78 प्रतिशत जंगल हैं और उसकी सीमा छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है. वारदात के तुरंत बाद नक्सली दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं.

देश के अति पिछड़े 25 ज़िलों की सूची में शुमार गड़चिरोली ज़िले का विकास विगत 30 वर्षों से नक्सलवाद की वजह से अधर में लटका है. केंद्र व राज्य सरकारों की अनेक योजनाओं के क्रियान्वित होने के बावजूद नक्सलवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते फ़िलहाल गड़चिरोली ज़िला नक्सलियों के गढ़ के रूप में सर्वदूर जाना जाता है. ज्ञातव्य हो कि नव जनवादी क्रांति अभियान के नाम से गड़चिरोली ज़िले की सिरोंचा तहसील से सन 1980 में सर्वप्रथम नक्सलियों ने क़दम रखा. सन 1982 में नक्सलियों ने पहला सम्मेलन कमलापुर में किया. शुरुआती दौर में लोगों का दिल जीतने के साथ आदिवासियों पर कथित रूप से हो रहे अन्याय के ख़िलाफ़ नक्सलियों ने आज इन 30 वर्षों में नक्सली लूटमार, धन उगाही के साथ पुलिस जवानों की हत्या करने जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. पुलिस विभाग ने नक्सलियों से निपटने के लिए अपनी मशीनरी को मुस्तैद कर रखा है. महाराष्ट्र के गृहमंत्री आरआर पाटील स्वयं इस ज़िले से हैं, फिर भी नक्सलियों का ख़ौफ़ जारी है.

पिछले चार दशकों में नक्सलियों ने जनांदोलन से ऊपर उठते हुए सशस्त्र क्रांति के नाम पर किसी देश की फ़ौज की तर्ज़ पर अपना ढांचा खड़ा कर लिया है. मतलब साफ़ है कि बाक़ायदा सेना की संरचना तैयार करने के लिए उन्हें धन, मानवबल और हथियारों की आवश्यकता होती है. कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में ज़ब्त हथियारों से यह बात साफ़ हो गई है कि नक्सली न सिर्फ़ विदेशी हथियार इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनके संपर्क सूत्र हमारे देश की आयुध निर्माणियों तक भी फैले हुए हैं. छत्तीसगढ़ के जशपुर में हथियारों से भरा ट्रक पकड़ाया था, उसमें हथियार आर्डिनेंस फैक्ट्री, पुणे के भी थे. इससे अब यह धारणा पुरानी हो चली है कि नक्सली लूटे हुए हथियारों पर ही निर्भर रहते हैं. एक नया तथ्य सामने आया है कि इस वामपंथी उग्रवाद का प्रत्येक समूह अन्य चीज़ों के अलावा हथियार ख़रीदने के लिए लाखों रुपये ख़र्च करता है. केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चलाए गए अभियानों के दौरान हाल ही में उग्रवादियों के ज़ब्त रिकॉर्ड से ख़ुलासा हुआ है कि नक्सली लेवी, फ़िरौती और धमकियों के ज़रिये सालाना करोड़ों रुपये जुटाते हैं. केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि नक्सलियों की अपनी कॉरपोरेट शैली में अकाउंटिंग पद्धति है. इनके दल में आम तौर पर 20 से 40 सदस्य होते हैं और ये दल अपने क्षेत्रीय कमांडर को छमाही आधार पर अपनी आय और ख़र्च का ब्यौरा देते हैं. ये ब्यौरा इससे ऊपरी स्तर पर पहुंचाया जाता है. बताया जाता है कि हथियार ख़रीदने पर किए गए ख़र्च का लेखाजोखा अलग से रखा जाता है. नक्सलियों का वर्चस्व देश के 40 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जिसे रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है. जानकारों के मुताबिक़ इस रेड कॉरिडोर से प्रति वर्ष नक्सलियों को 15000 करोड़ रुपयों की आय होती है. नक्सलियों के पास धन उसकी उप समिति और क्षेत्रीय समिति से आता है. आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक़ नक्सली विदेश निर्मित विशेष रूप से चीन और अमेरिका द्वारा निर्मित हथियारों का ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. बिहार, झारखंड और आंध्रप्रदेश के माओवादी चीन सहित विदेशी छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के नक्सली स्थानीय हथियारों से ही काम चलाते हैं. सूत्रों का कहना है कि रूस निर्मित एके सीरीज़ की बंदूकें माओवादियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं. सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के क़ब्ज़े से एके 47, एके 56, पाकिस्तान निर्मित पीका गन और इज़राइली स्नाइपर गन बरामद किए हैं. सीमा पार हथियारों के बाज़ार हैं. नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत की खुली सीमा है. नक्सली वारदातों की तीव्रता के पीछे एक बड़ा कारण सीआरपीएफ और राज्यों की पुलिस के बीच तालमेल का अभाव माना जाता है. सीआरपीएफ के आला अधिकारी भले ही यह बयान दे रहे हों कि अब राज्यों की पुलिस के साथ बेहतर तालमेल किया जाएगा, लेकिन इस संबंध में पुराना अनुभव कुछ अच्छा नहीं है. केंद्रीय सुरक्षा बल नक्सली इलाक़ों में अपनी डफ़ली अपना राग अलापते नज़र आते हैं. नक्सली सबसे अधिक छत्तीसगढ़ के विशेष पुलिस अधिकारियों से ख़ौफ़ खाते हैं. यही कारण है कि सलवा जुडूम और एसपीओ का नक्सलियों के हमदर्द पुरज़ोर विरोध करते हैं. सीआरपीएफ के जवान तो इन नक्सलियों के लिए सबसे आसान टार्गेट माने जाते हैं. छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में सीआरपीएफ को भारी क्षति इसलिए पहुंची, क्योंकि जवान ज़मीनी स्थिति का आकलन नहीं कर पाए और नक्सलियों के जाल में फंस जाते हैं. एक ओर प्रदेश स्तर से लेकर केंद्रीय सरकार नक्सलियों पर नकेल कसने की बात करती है, लेकिन विभिन्न एनजीओ के माध्यम से विदेशों से मिलने वाले धन के बल पर नक्सली अपने मंसूबों को पालने में सक्षम हो रहे हैं. हालिया घटनाक्रम में इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि नक्सली संगठनों को विदेशों से पैसा मिल रहा है और उसका माध्यम कई ग़ैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ) हैं. ज़ाहिर तौर पर कोई भी संगठन बग़ैर आर्थिक मदद के नहीं चल सकता. सो, नक्सली संगठनों को भी विदेशों से धन मिलना कोई आश्चर्य पैदा नहीं करता. केंद्र और राज्य सरकार की मदद से चलने वाली ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना जैसी योजनाओं का धन भी सीधे-सीधे नक्सलियों के पास पहुंचता है. यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नेशनल पार्क में टाइगर कंजर्वेशन के नाम पर आवंटित करोड़ों की राशि कहां जाती है, किसी को पता नहीं है. सरकार देश के दुर्गम इलाक़ों तक अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन की बात करती हैं, लेकिन जब नक्सलियों के क़ब्ज़े वाले दुर्गम आदिवासी इलाक़ों में जाकर स्थिति का पता लगाया तो मामला वही ढाक के तीन पात ही नज़र आता है.

(साथ में मोहनीश चिपिये)

feedback@chauthiduniya.com

केंद्रीय सुरक्षा बल नक्सली इलाक़ों में अपनी डफ़ली अपना राग अलापते नज़र आते हैं. नक्सली सबसे अधिक छत्तीसगढ़ के विशेष पुलिस अधिकारियों से ख़ौफ़ खाते हैं. यही कारण है कि सलवा जुडूम और एसपीओ का नक्सलियों के हमदर्द पुरज़ोर विरोध करते हैं. सीआरपीएफ के जवान तो इन नक्सलियों के लिए सबसे आसान टार्गेट माने जाते हैं.

पूनम ने भारतीय संस्कृति, समाज की भावनाओं का ज़रा भी ख्याल नहीं रखा. ऐसा लगता है कि उन्हें अपने बदन के कपड़े उतारने के लिए अपना बेडरूम, बाथरूम कम पड़ने लगा है.

उस्मानाबाद और लातूर ज़िलों को औरंगाबाद, जालना और बीड से ज़्यादा लाभ हुआ है, लेकिन वह लाभ कितना मिला, यह तो पारधी समाज के लोग ही जानते हैं.

सभी फोटो-प्रभात पाण्डेय

राजनीति में गड़बड़ाते समीकरण

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा-शिवसेना के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ी नज़र आती है. सबसे अधिक रोचक दृश्य सत्तारूढ़ गठबंधन का है. सरकार चलाने को लेकर राकांपा-कांग्रेस में कहीं कोई तालमेल नज़र नहीं आता है.

महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण तेज़ी से बदल रहे हैं. कौन किसका सहयोगी है और कौन किसका विरोधी, ऊपरी तौर पर तो सब साफ़ है, लेकिन अंदर ही अंदर पक रही खिचड़ी संदिग्ध है. कहने को तो राज्य में कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस आघाड़ी की सरकार है, विपक्ष के रूप में भाजपा-शिवसेना का गठजोड़ भी क़ायम है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा-शिवसेना के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ी नज़र आती है. सबसे अधिक रोचक दृश्य सत्तारूढ़ गठबंधन का है. सरकार चलाने को लेकर राकांपा-कांग्रेस में कहीं कोई तालमेल नज़र नहीं आता है. दोनों दलों के बीच अघोषित द्वंद्व चल रहा है. दोनों के बीच शह-मात का खेल विपक्ष के साथ मिलकर खेला जा रहा है. इस खेल का शुभारंभ किया है केंद्र में कांग्रेस ने तो राज्य में राकांपा ने. आज स्थिति यह है कि अजीत पवार से निपटने के लिए कांग्रेस को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी भाजपा का सहारा लेना पड़ रहा है. कांग्रेस को मात देने के लिए राकांपा को शिवसेना से गलबहियां करनी पड़ रही हैं. इससे महाराष्ट्र का राजनीतिक तिलिस्म और गहराता जा रहा है.

अजीत पवार के उपमुख्यमंत्री बनते समय हुए घटनाक्रम का ज़िक्र भी यहां लाज़िमी है. जिस दिन पृथ्वीराज चव्हाण को मुख्यमंत्री घोषित किया गया, उसके एक दिन पहले दस जनपथ में घटनाक्रम तेज़ी से बदला. कांग्रेस के संकटमोचक प्रणव मुखर्जी और पी. चिदंबरम विधायकों से सलाह-मशविरा करने मुंबई पहुंचे और रात 1.30 बजे कथित रूप से सोनिया गांधी को रिपोर्ट पेश की. कथित रूप से इसलिए क्योंकि मीडिया में सोनिया का नाम प्रचारित कराया गया, जबकि ख़बर है कि उक्त नेताओं ने अपनी रिपोर्ट अहमद पटेल को सौंपी थी. आनन-फानन में सुबह 10 बजे पृथ्वीराज चव्हाण का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित कर दिया गया. उस समय राकांपा में भी हलचल थी और मीडिया को नियोजित कर यह ख़बर उड़ाई गई कि जब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो राकांपा में क्यों नहीं? छगन भुजबल आख़िरी वक़्त तक आश्वस्त थे कि उपमुख्यमंत्री वही बनेंगे, लेकिन यह क्या, एक तरफ़ अशोक चव्हाण मुंबई पहुंचते हैं और दूसरी तरफ़ राकांपा के सभी विधायक एकसूत्रीय कार्यक्रम चला कर अजीत पवार की दावेदारी की मांग कर डालते हैं. छगन भुजबल आख़िरी समय तक बोलते रहे कि उपमुख्यमंत्री वही बनेंगे, मगर बंद कमरे में उन्हें शरद पवार मना लेते हैं. फिर अजीत पवार के नाम का प्रस्ताव वही पेश कर देते हैं. यहां यह बात किसी के गले नहीं उतरी कि शरद पवार इस घटनाक्रम में तटस्थ थे. ज़ाहिर है कि अजीत पवार का उपमुख्यमंत्री बनना शरद पवार की ही रणनीति का हिस्सा था. वह भी इसलिए क्योंकि पृथ्वीराज भी पश्चिम महाराष्ट्र के ही हैं और उनकी छवि साफ़-सुथरी है. पवार का गढ़ भी पश्चिम महाराष्ट्र ही माना जाता है. फिर इसके बाद जिस तरह से अजीत पवार ने अपने तेवर दिखाए वे कांग्रेस के गले के नीचे नहीं उतरे. दूसरे शब्दों में कहा जाए कि कांग्रेस के गले की हड्डी बन गए, जिसे न कांग्रेस उगल सकती है और न ही निग़ल सकती है. विधान मंडल में भी अजीत पवार के तेवरों से कांग्रेस को अपने लिए ख़तरा महसूस होने लगा तो उसने अपने पुराने अंदरूनी मित्र भाजपा का सहारा लिया. आग लगती है तभी धुआं निकलता है. भाजपा के साथ कांग्रेस की साठगांठ बीते विधानसभा सत्र में साफ़ दिखाई दी. यहां तक कि जल प्राधिकरण सुधार अधिनियम को भी पारित होने से रोकने के लिए कांग्रेस के विदर्भ के विधायकों का ही ज़्यादा विरोध दिखा. भाजपा से सिर्फ़ देवेंद्र फड़णवीस ही मुखर होकर विरोध करते दिखे.

इधर, राकांपा भी तू डाल-डाल, मैं पात-पात की तर्ज़ पर शिवसेना के नज़दीक आने लगी. शिवसेना को भी इस समय राज्य में अपना आधार मज़बूत करने की चिंता है. इस तथ्य को समझते हुए अजीत पवार ने हाल ही में संपन्न बजट सत्र में शिवसेना सुप्रीमो बालासाहब ठाकरे को खालापुर में 1755 चौरस मीटर ज़मीन किराया पट्टा पर देने की घोषणा कर सबको हैरानी में डाल दिया है. इसके पहले भी यह ज़मीन ठाकरे परिवार के पास ही थी. 1993 में मीनाताई बालासाहब ठाकरे ने खालापुर की इस ज़मीन के लिए आवेदन दिया था, जिसके आधार पर 1995 में 1755 चौरस मीटर ज़मीन 562 रुपये के भाड़े पर पेड़-पौधे लगाने के उद्देश्य से दी गई थी. इसकी 2008 में लीज अवधि ख़त्म होने के बाद भी ज़मीन पर ठाकरे परिवार का ही क़ब्ज़ा अब भी बना हुआ है. वृक्षारोपण के लिए दी गई इस ज़मीन पर फॉर्म हाउस बनाया गया है. अब अजीत दादा ने किराया बढ़ाकर खालापुर की ज़मीन पुनः बालासाहब ठाकरे के नाम करने की तैयारी दिखाई है. अजीत दादा के इस दांव से भाजपा के कान खड़े हो गए हैं. इस घटनाक्रम से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति के बनते-बिगड़ते समीकरण के मध्य राकांपा की कांग्रेस से दूरी बढ़ रही है और अजीत दादा ना-ना कहने के बाद भी शिवसेना से नज़दीकी बढ़ा रहे हैं. दूसरी ओर शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे भले ही सेना-भाजपा गठबंधन में दरार से इनकार करते हुए कहें कि भाजपा के प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन राकांपा और शिवसेना के बीच बढ़ती नज़दीकियां कुछ और ही कहानी कहती हैं. इन सबके बीच भाजपा मनसे से गठबंधन पर ज़ोर देने लगी है. वैसे भी पिछले दिनों जब बाल ठाकरे ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नहीं खेलने देने की धमकी दी थी तो बीचबचाव शरद पवार ने ही किया था. ज़ाहिर है शरद पवार से ठाकरे परिवार का हमेशा ही घनिष्ठ रिश्ता रहा है.

ग़ौरतलब है कि केंद्र में अनाज, शक्कर व प्याज़ के आसमान छूते दामों के लिए हमेशा शरद पवार को कांग्रेस ज़िम्मेदार ठहराती रही है. कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहा यह जाता रहा है कि आईसीसी का अध्यक्ष बनने के बाद शरद पवार का सारा ध्यान क्रिकेट में रमा हुआ है. अपने कृषि मंत्रालय के कामकाज की उन्हें चिंता ही नहीं है. पवार को कृषि मंत्रालय या क्रिकेट में से किसी एक को चुन लेना चाहिए. उस समय कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की थी कि शरद पवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से चलता कर दिया जाए, पर असफलता ही हाथ लगी. हाल ही जब अन्ना हज़ारे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनशन पर बैठे और सरकार द्वारा गठित 11 मंत्रियों के समूह पर अंगुली उठाई तो कांग्रेस के नेताओं की बांछे खिल गईं. कांग्रेसियों को इस मामले में ज़्यादा देर ख़ुश होने का मौक़ा नहीं मिला, क्योंकि स्थिति को भांपते हुए शरद पवार ने तत्काल मंत्रीसमूह से इस्तीफ़ा दे दिया. कांग्रेस पुनः महाराष्ट्र के इस राजनीतिक चाणक्य को घेरने में नाकाम ही रही. इसी के साथ महाराष्ट्र में राकांपा को और मज़बूत करने की रणनीति पर शरद पवार ने विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है. वे लगातार कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की रणनीति पर पार्टी का संचालन कर रहे हैं. इसके चलते भविष्य में यदि राकांपा-शिवसेना चुनावी युद्ध में उतरें तो आश्चर्य की बात नहीं होगी. वैसे भी राजनीति में कोई किसी का स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है. हां, अब राकांपा को मुख्यमंत्री की गद्दी चाहिए और उसके लिए कांग्रेस पर लगाम कसने की ज़िम्मेदारी भी अजीत पवार पर ही है.

आलोक मिश्रा
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार
महाराष्ट्र के लिए चाहिए
वितरक/एजेन्ट
राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक चौथी दुनिया के महाराष्ट्र संस्कार के लिए महाराष्ट्र के सभी जिलों में वितरक/एजेंट चाहिए
जिला प्रतिनिधि
भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गड़चिरोली, अमरावती, नांदेड़, हिंगोली, परभणी, बीड़, जालना, उस्मानाबाद, नंदुरबार, लातूर, नासिक, धुलिया, कोंकण, कोल्हापुर, सातारा, सांगली, सोलापुर, अहमदनगर, जलगाँव, मुंबई उपनगर
नागपुर कार्यालय : आशीर्वाद पब्लिकेशन प्रा. लि.
२७, पिसे कॉम्प्लेक्स, धंतोली रेलवे पुलिया, ग्रेट नाग रोड, नागपुर - ४४०००३
Ph.-0712- 2707414, 15 Fax:- 91-712-2752025
e-mail: chauthiduniyaa@gmail.com

पूनम युवाओं को गुमराह कर रही है

वास्तव में पूनम पैराग्वे की मॉडल लैरिसा रिक्युलमे की नकल करने की कोशिश की है, जिन्होंने घोषणा की थी कि उनका देश विश्वकप जीता तो वह नग्न दौड़ेगी. यह बात और है कि उनका देश हार गया फिर भी उन्होंने वादा निभाया.

राजेश नामदेव

पूनम पांडेय का निर्वस्त्र होने का बयान हल्के से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बॉलीवुड की मायानगरी की ओर आशाभरी निगाहों से देखने वाली युवा पीढ़ी के लिए इससे नकारात्मक संदेश जाएगा. कहीं यह संदेश बलवती न हो जाए कि बॉलीवुड में पैर जमाने के लिए न्यूड हो जाना सबसे आसान तरीक़ा है. वैसे भी मायानगरी में दुराचरणों की कमी नहीं है. वहां स्टार बनने की चाहत में पहुंचने वाले लाखों युवाओं में कुछेक ही मुक़ाम पाते हैं. ऐसे में पूनम पाडेय का यह बयान न सिर्फ़ नवोदितों को गुमराह करने वाला है, बल्कि प्रथम दृष्टया यह भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन भी है. अनजान-सी मॉडल पूनम पांडेय एकाएक तब सुर्ख़ियों में छा गई. जब समूचा भारत देश विश्व कप क्रिकेट के उन्माद में डूबा था, उसने इस उन्माद को पागलपन की हद पर यह कह कर पहुंचा दिया कि यदि भारतीय टीम विश्व कप जीत गई तो वह सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र हो जाएगी. कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट माना तो कई ने अश्लीलता क़रार दिया. बात जो भी हो, परंतु यह बात तो साफ़ है कि भारतीय क़ानून न तो सार्वजनिक अश्लीलता की अनुमति देता है और न ही ऐसे किसी बयान या कृत्य की जो अश्लीलता को बढ़ावा दे. जब पूनम ने निर्वस्त्र होने की घोषणा की तो कई लोगों ने यह भी कहा कि उसने ऐसा बयान किसी के उकसावे में दिया है, लेकिन अक्षय कुमार के रियलिटी टीवी शो ख़तरों के खिलाड़ी में शामिल होने के बाद मुंबई में हुई प्रेस कांफ्रेंस में उसे इस बात पर किसी प्रकार का मलाल नहीं था, बल्कि वह तो अब भी सही समय आने पर ऐसा करने का विचार रखती है. लोगों ने उसकी पब्लिसिटी का काम करने वाले पर आरोप लगाया, लेकिन इसमें हक़ीक़त कितनी है, यह अब तय नहीं किया जा सकता. कारण जो भी हो, लेकिन पूनम ने भारतीय संस्कृति, समाज की भावनाओं का ज़रा भी ख्याल नहीं रखा. ऐसा लगता है कि उन्हें अपने बदन के कपड़े उतारने के लिए अपना बेडरूम, बाथरूम कम पड़ने लगा है. इसीलिए तो यह ज़रा भी नहीं सोचा कि उनके बदन उघाड़ू कारनामे का समाज में क्या संदेश जाएगा. कुछ लोग कह सकते हैं कि ग्लैमर की दुनिया में यह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है. बात बड़ी है और बड़ी इसलिए भी कि पूनम की उम्र काफ़ी कम है. दरअसल पूनम पांडेय एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मॉडल है. उसकी अब तक की उपलब्धि सिर्फ़ इतनी है कि वह दो-चार विज्ञापनों में काम कर चुकी है और किंगफिशर की बिकिनी गर्ल है. हां यह बात अलग है कि इस पब्लिसिटी के बाद अब वह अक्षय कुमार के रियलिटी शो ख़तरों के खिलाड़ी की शूटिंग के लिए केपटाउन में है. इसके बाद एक कॉमेडी सीरियल का भी ऑफर उसके पास है. दरअसल, आज की युवा पीढ़ी की तरह ही पूनम में भी शार्टकट में शोहरत हासिल करने की ख्वाहिश है. इसके लिए वह फिल्म निर्देशकों-निर्माताओं के चक्कर भी लगा चुकी है. मगर किसी ने उसे घास नहीं डाली. हालांकि बाद में उसने गेंद बीसीसीआई के पाले में डाल दी और बेशर्मी से बाद में यह भी ऐलान कर दिया कि बीसीसीआई परमिशन दे या न दे, आज नहीं तो कल वह अपना वादा निभाएगी. पूनम को अपनी हसरत पूरी करने के लिए किसी विदेशी स्थल का चयन करना होगा या अपने बेडरूम का, क्योंकि विदेशी मॉडल ही बदन उघाड़ू कारनामों के लिए कुख्यात हैं. वास्तव में पूनम पैराग्वे की मॉडल लैरिसा रिक्युलमे की नक़ल करने की कोशिश की है, जिन्होंने घोषणा की थी कि उनका देश विश्वकप जीता तो वह नग्न दौड़ेगी. यह बात और है कि उनका देश हार गया फिर भी उन्होंने वादा निभाया. एक प्रेस कांफ्रेंस में जब पूनम से यह पूछा गया था कि क्या ग़लत कारण से मीडिया में चर्चित होना उसे चिंतित नहीं करता तो उसने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है. निजी रूप से मुझे नहीं लगता कि यह नकारात्मक पब्लिसिटी है. अगर भारतीय टीम या देश के लिए कुछ करना नकारात्मक है तो मैं क्या कह सकती हूं. क़ानूनी विशेषज्ञों की राय में मॉडल पूनम पाडेय का भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने पर निर्वस्त्र होकर जश्न मनाने के लिए बीसीसीआई से अनुमति मांगना लोगों को गुमराह करने से अधिक कुछ नहीं है. क़ानूनविदों की राय है कि कपड़े उतारकर जश्न मनाना भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (सार्वजनिक स्थल पर अश्लील कृत्य करना) के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकता है और कोई किसी दूसरे को अपराध करने की अनुमति नहीं दे सकता, चाहे वह बीसीसीआई हो या कोई और. आईपीसी की धारा-294 के अनुसार, सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाने पर अधिकतम तीन महीने के कारावास या जुर्माना या दोनों की सज़ा दी जा सकती है. भोपाल में इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है. पूनम का इरादा और बयान दोनों लोगों को अश्लीलता के लिए उकसा सकते हैं. पुलिस प्रशासन इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकता है. विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पूनम के बयान भड़काने की श्रेणी में आते हैं और कोई भी व्यक्ति पुलिस में उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करा सकता है और ऐसे में पूनम को ज़मानत करानी पड़ सकती है, क्योंकि यह ज़मानती अपराध है.

पूनम शरीफ़ है नताशा

पूनम के इस बयान के बाद कई लोगों ने उसके चरित्र पर ही संदेह करना शुरू कर दिया, लेकिन पूनम को क़रीब से जानने वाली मॉडल नताशा सिक्का का कहना है कि पूनम एक निहायत ही शरीफ़ और अच्छे घर की है. बक़ौल नताशा, पूनम के इस बयान के पीछे कौन है, यह तो नहीं मालूम लेकिन उसकी उम्र अभी कम है और वह हम लोगों की काफ़ी इज़्ज़त भी करती है. जब नताशा से यह पूछा गया कि क्या वह कभी पब्लिसिटी के लिए ऐसे बयान देगी, तो उसका साफ़ कहना था, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. इस कारण वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे देश की मर्यादा, संस्कृति पर चोट पहुंचे. मैं भी चाहती थी कि इंडिया की टीम विश्व कप में जीते. लगता है कि पूनम को नकारात्मक पब्लिसिटी कुछ ज़्यादा ही मिल गई है.

feedback@chauthiduniya.com

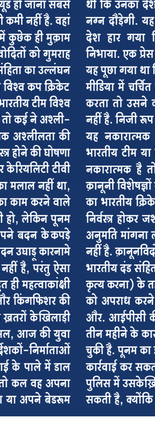

पारधी समाज विकास से बहुत दूर

पारधी गाय का मांस नहीं खाते. उसे पवित्र मानते हैं. कहा जाता है कि पारधी पंछियों की बोली जानते हैं. पारधी शिकार करने जंगल में जाते हैं. जब पारधी जंगली तीतरों को गाली देते हैं तो जंगल के कई तीतर लड़ने के लिए आते हैं. लेकिन वे बीच में लगे पारधी के जाल में फंस जाते हैं. शिकार करना पारधी की रगों में बसा है. पुरातन समाज में पारधियों को ईमानदार जमात में गिना जाता था और वे राजा के विशेष रक्षकों में शामिल होते थे.

मराठवाड़ा में पारधियों के 5435 परिवार बसते हैं

मराठवाड़ा में कुल आबादी के तीन प्रतिशत पारधी हैं. मराठवाड़ा के आदिवासी विकास विभाग औरंगाबाद के तहत जो जानकारियां मिली हैं उसके अनुसार औरंगाबाद ज़िले में पारधियों का निवास 70 गावों में है. इनमें पारधियों के 417 परिवार रहते हैं. उनमें महिला 489, पुरुष 432 और बच्चे 1028, कुल आबादी 1949 हैं. इनमें से 345 भूमिहीन और 363 बेघर हैं. जालना में 14 गांव में पारधी समाज के लोग रहते हैं. वहां उनके 364 परिवार हैं. इनमें महिलाएं 324, पुरुष 288, बच्चे 553, कुल आबादी 1165 है. इनमें 215 भूमिहीन, 27 बेघर हैं. बीड़ ज़िले में 114 गांवों में वे रहते हैं. यहां उनके 960 परिवार हैं. इनमें महिला 1022, पुरुष 879, बच्चे 1967, कुल आबादी 3868 है. इसमें भूमिहीन 762 और बेघर 229 हैं. लातूर ज़िले में 14 गांव में वे लोग रहते हैं. वहां उनके 157 परिवार हैं. उसमें महिलाएं 216, पुरुष 212, बच्चे 308, कुल 736 हैं. इनमें भूमिहीन 83 और बेघर 17 हैं. उस्मानाबाद ज़िले के 164 गांवों में पारधी समाज रहता है. यहां उनके 3637 परिवार हैं. उसमें महिला 3960, पुरुष 3296, बच्चे 7899, कुल आबादी 15155 है. इनमें भूमिहीन 3098 और बेघर 508 है. मराठवाड़ा के इन पांच ज़िलों की कुल स्थिति देखी जाए तो पारधी समाज 376 गांवों में फैला हुआ है. उनके 5435 परिवार हैं. इनमें महिला 6011, पुरुष 5107, बच्चे 11755, कुल आबादी 22878 है. इनमें भूमिहीन 4503 और बेघर 1044 हैं.

संदीप सुखधान

प्राचीन काल से राजा-महाराजाओं की रक्षा का ज़िम्मा संभालने वाला पारधी समाज बीते कई दशकों से उपेक्षा का जीवन जी रहा है. जिन पारधियों ने आज़ादी की लड़ाई में भारतीयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के ख़िलाफ़ लंबी लड़ाई लड़ी, क़ानून की किताब में उन्हें ही अपराधी क़रार दे दिया गया. आज़ादी के बाद क़ानून ने तो उन्हें बख्श दिया, लेकिन छह दशक बाद भी शासन उन्हें मुख्यधारा में लाने में सफ़ल नहीं हुआ है. इतना ही नहीं, अधिकांश पारधी देश के आम मतदाता तक नहीं हो पाए हैं. जानकर आश्चर्य होगा कि पारधी समाज का इतिहास समाज की धारणा से बिल्कुल अलग है. आज समाजिक उपेक्षा और पिछड़ेपन में जी रहे पारधी कभी रजवाड़ों से सीधा संबंध रखते थे. पारधी पारध शब्द से बना है. पारध का अर्थ है शिकार. इस तरह पारधी परंपरागत पेशे से शिकारी हैं. परंपराओं और कार्यशैली की दृष्टि से पारधी अलग-अलग तरह के हैं. जैसे राज पारधी, बाघ पारधी, गाय पारधी, हिरन शिकारी और गांव पारधी. प्राचीन काल में राजा के पास जो शिकार विशेषज्ञ था, वह राज पारधी कहलाया. बाघ को पकड़ कर उसे पालतू बनाना और राजा की इच्छा अनुसार उसे बाघ पर सवार करवाना, यह हिम्मत का काम राज पारधी ही करता था.

गाय पारधी का मुख्य वाहन गाय है. उसकी यह गाय प्रशिक्षित होती है. आज भी हर घर में एक गाय होना ज़रूरी है. पारधी गाय के शरीर के जिस हिस्से को हाथ लगाता था, वह समझ जाती है कि अब क्या करना है. गाय हिरन के शिकार में बहुत काम आती थी. जब गाय चरती थी तो पारधी उसके पास छिपा रहता था. हिरन के पास आते ही पारधी उस पर अचानक हमला कर देता था. इसीलिए पारधी गाय को अपनी मां मानते हैं. पारधी गाय का मांस नहीं खाते. उसे पवित्र मानते हैं. कहा जाता है कि पारधी पंछियों की बोली जानते हैं. पारधी शिकार करने जंगल में जाते हैं. जब पारधी जंगली तीतरों को गाली देते हैं तो जंगल के कई तीतर लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वे बीच में लगे पारधी के जाल में फंस जाते हैं. शिकार करना पारधी की रगों में बसा है. पुरातन समाज में पारधियों को ईमानदार जमात में गिना जाता था और वे राजा के विशेष रक्षकों में शामिल होते थे.

पारधी समाज के लोग आज भी अक्सर गांव के बाहर ही बसर करते हैं. एक पारधी गांव के 25 से 50 खेतों की रखवाली करता है. किसी के खेत में चोरी हुई तो उस खेत के नुक़सान की भरपाई पारधी करता है. वह अपने हथकंडों से चोरी का पता लगाता है. जब चोरी होती है तो वह इस मामले को अपनी जातीय पंचायत में उठाता है. इस पंचायत मे आरोप साबित होते ही नुक़सान से 5 गुना वसूला जाता है. गांव के पारधी को रखवाली के बदले सालाना अनाज मिलता है. इस लिहाज़ से पारधी गांव की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं. इतिहास गवाह है, मराठवाड़ा के पारधियों ने पहले निज़ाम और फिर अंग्रेज़ों के साथ लड़ाइयां लड़ीं थीं. अंग्रेज़ जब पारधियों की छापामार कार्रवाई और बारबार के हमलों से परेशान हो गए तो उन्होंने इस जमात को अपराधी घोषित कर दिया. उन्हें आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत सभी पारधियों को अपराधी की संज्ञा दे दी. 1947 में देश आज़ाद हुआ और भारत सरकार का पुलिस विभाग बना, लेकिन तरीक़ा अंग्रेज़ों के ज़माने का ही चला. जिन पारधियों को पुलिस और सैन्य विभाग में प्राथमिकता से लिया जाना चाहिए था उन्हें अपराधी नाम से मुक्ति नहीं मिल पाई.

1924 में देश में 52 अपराधी बस्तियां बनाई गईं थीं. महाराष्ट्र के सोलापुर में सबसे बड़ी बस्ती बनी. इसमें तार के भीतर क़ैदियों को रखा जाता था. 1949 को बालसाहेब खैर और उनके साथियों ने सोलापुर सेटलमेंट का तार तोड़ डाला. 1952 को डॉ. बाबासाहब अंबेडकर ने पारधियों को अपराधी घोषित करने वाले क़ानून को रद्द किया. वर्ष 2006-07 में आदिवासी विकास विभाग, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प औरंगाबाद ने पारधी समाज के लिए विशेष योजना चलाई. यह विभाग पांच ज़िलों की आदिवासी जनजातियों के लिए है. उसमें औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, बीड़ और लातूर ज़िले आते हैं. इन सब ज़िलों में पारधी समाज के कल्याण के लिए 2006-07 में 8,92,25,000 रुपए का प्रावधान था तथा यह यह निधि 17 योजनाओं में ख़र्च करनी थी. इन योजनाओं में भूमिहीनों के लिए स्वाभिमान योजना, घरकुल योजना, खेती के पूरक के रूप में दस बकरियां और एक बकरा देना, कुंआ बनाकर देना, मोटर पंप और पाइप लाइन योजना, डीजल पंप देना, दूध के लिए दो भैंसें या चार गाय देना, आटे की चक्की स्थापित कर देना, साइकिलें देना, किराना दुकान के लिए पैसा देना, पारधी महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण और मशीन देना, खेती के औज़ार देना, व्यवसाय के लिए 25,000 रुपए तक की सहायता देना, मुर्ग़ी पालन व्यवसाय शुरू करवाना, ज़मीन के पट्टे देना, जनजातीय सम्मेलन करवाना आदि शामिल था. पूरी योजना लागू होने के बाद सरकारी रिपोर्ट में केवल 28 लाख 41 हज़ार रुपए ख़र्च नहीं होना बताया गया है.

पर वास्तविकता कुछ अलग है. औरंगाबाद में पारधी समाज के लोगों के अनुसार आदिवासी विकास विभाग ने यहां सर्वे भी नहीं किया. स्वाभिमान योजना मराठवाड़ा में कहीं दिखाई भी नहीं देती. अहमद नगर ज़िले में यह योजना थोड़ी बहुत चलाई गई. अहमदनगर ज़िले के पांच लोगों को घरकुल मिले, लेकिन वह भी बहुत कमज़ोर. जो बकरियां दी गईं, वे पहले से ही रोग ग्रस्त थीं. ज़िले में केवल दो ही लोगों को कुंआ, मोटर पंप और पाइप मिले हैं. दूध व्यवसाय के लिए गाय या भैंस ज़िले में क़रीब दस लोगों को मिली हैं. आटे की चक्की ज़िले में एक ही मिली है. एक व्यक्ति को साइकिल मिली तथा तीन लोगों को किराना दुकानें प्राप्त हुईं हैं. सिलाई मशीन पूरे ज़िले में किसी को भी नहीं मिली. खेती के औज़ार और धंधे के लिए औरंगाबाद ज़िले में पैसा भी नहीं मिला. लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि उस्मानाबाद और लातूर ज़िलों को औरंगाबाद, जालना और बीड़ से ज़्यादा लाभ हुआ है, लेकिन वह लाभ कितना मिला, यह तो पारधी समाज के लोग ही जानते हैं. योजना के ऐसे क्रियान्वयन से ही यह बात समझ में आ जाती है कि आख़िर पारधी समाज की आज तक उन्नति क्यों नहीं हुई. आज भी शासन और प्रशासन पारधी समाज को चोर से ज़्यादा नहीं आंकते. चुनाव के दौरान सबको अपना ध्यान रखने की प्रार्थना करने वाले उम्मीदवार पारधियों के आगे हाथ नहीं फैलाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे मतदाता हैं ही नहीं. मतदान से वंचित रहना भी उनके लिए आज किसी सामाजिक अभिशाप से कम नहीं है. चुनाव का हक़ पाए बग़ैर पारधियों की हक़ की लड़ाई अधूरी ही रहेगी.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
राष्ट्रीय साप्ताहिक चौथी दुनिया अब महाराष्ट्र से

राष्ट्रीय साप्ताहिक १६ पृष्ठों के साथ महाराष्ट्र के रंगीन ४ पृष्ठ
आज ही अपना अंक सुरक्षित करवाएं
मुंबई- 8097592411, पुणे- 9372922174, नागपुर- 9922412186
बुलढाणा- 9860933217, वाशिम - 9423430554, अकोला- 9822465812,
वर्धा- 9850738513, औरंगाबाद- 9762478014, यवतमाळ - 9767777917
महाराष्ट्र के लिए संपर्क : आशिर्वाद पब्लिकेशन प्रा. लि.
२७, पिसे कॉम्प्लेक्स, धंतोली रेलवे पुलियाँ, ग्रेट नाग रोड, नागपुर- ४४०००३
Ph.-0712- 2707414, 15 Fax:- 91-712-2752025 e-mail: chauthiduniyaa@gmail.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 09 मई-15 मई 2011

मनसे की वजह से शिवसेना और भाजपा के बीच दरार भी पैदा हुई है. यही कारण है कि महाराष्ट्र में भाजपा के वरिष्ठ नेतागण दोनों भाइयों के बीच की दूरी कम करने का प्रयास करते रहते हैं.

सियासी निशाने पर हिंदीभाषी

शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का परिवार और राज ठाकरे आमने-सामने हैं. उद्धव और राज, ये दो भाई आपस मे भिड़ते हैं तो दूसरी तरफ़ मनसे की वजह से शिवसेना को फ़ायदा पहुंचता है. अब जनता इस बात को किस नज़र से देखती है यह आने वाले चुनाव में ही दिखाई देगा. रहा सवाल मुंबई महानगर पालिका चुनाव का, तो शिवसेना और मनसे की भिड़ंत में किसी तीसरे को फ़ायदा पहुंच सकता है. मनसे और शिवसेना के इन अस्पष्ट तेवरों से भाजपा परेशान है.

पिछले दिनों मुंबई में भारी राजनीतिक उलटफेर हुए. राज्य की सारी राजनीतिक घटनाओं का केंद्रबिंदु राजधानी मुंबई रही. वैसे राज्य सरकार का बजट अधिवेशन नए मुद्दों पर राजनीतिक खींचतान पैदा करता ही है, पर अचानक एक ऐसी घटना हुई, जिसने मुंबई की राजनीति को गरमा दिया. ठाणे शहर में एक पानीपुरी (गुपचुप) का ठेला लगाने वाले की जनता ने जमकर पिटाई की. उसके बाद शहर में कई जगह पानीपुरी वालों पर गाज गिरी. इससे उत्तर भारतीयों का विरोध कर रहे राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक और मुद्दा मिल गया. ठाणे में ज़्यादातर पानीपुरी वाले उत्तर भारतीय ही हैं. मनसे के इरादे भांप कर दूसरी पार्टियों के नेताओं के भी कान खड़े हो गए.

मुंबई में बढ़ रही उत्तर भारतीयों की संख्या को लेकर राज ठाकरे शुरू से आक्रामक रहे हैं. ऐसा मामला सामने आए तो राज ठाकरे उसका फ़ायदा उठाए बिना कैसे रह सकते हैं. एक पानीपुरी वाला बर्तन में पेशाब करते पाया गया. वह उसी बर्तन का पानी लोगों को पीने के लिए दे रहा था और उसका पानी पानीपुरी का पानी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था. एक लड़की ने यह सब देखा और मोबाइल फोन पर शूट कर उसे टीवी चैनल पर सारी दुनिया के सामने उजागर कर दिया. ठाकरे के कान में बात पहुंचते ही मनसे हरकत में आ गई. उधर महानगर पालिका की तो मानो नींद ही उड़ गई. अब यह मामला सिर्फ़ पानीपुरी तक ही सीमित नहीं रहा. इसके आगे और भी कई राजनीतिक समीकरण बनने और बिगड़ने लगे. और ये सारे समीकरण आगामी महानगर पालिका चुनाव से जुड़े हुए हैं.

मुंबई महानगर पालिका के चुनाव इस साल के अंत में या अगले साल के शुरू में होने वाले हैं. मुंबई महानगर पालिका का लगभग 2500 करोड़ रुपए का बजट है. इस तिजोरी की चाबी अब तक शिवसेना के हाथ में रही है, लेकिन राज ठाकरे के बाहर आने के बाद शिवसेना की परेशानियां बढ़ गई हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में मनसे के 13 विधायक चुनकर आ गए. ख़ास तौर पर मुंबई में उन्हें भारी सफलता मिली. ज़ाहिर है कि आने वाले चुनाव में मनसे के उम्मीदवार भारी संख्या में जीतकर आ सकते हैं. पिछले साल मुंबई से जुड़े कल्याण-डोंबिवली में महानगर पालिका चुनाव हुए थे. यहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी. इस चुनाव में भी भाजपा को ही नुक़सान सहना पड़ा था. राज ठाकरे की पार्टी मनसे का यह पहला चुनाव था और इसमें ही उनके 27 पार्षद चुनकर आए. भाजपा के साथ ही साथ कांग्रेस पर भी इसका असर पड़ा. कल्याण शहर एक तरह से मुंबई का प्रवेश द्वार है. यहां पर बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय रहते हैं. कल्याण रेल्वे स्टेशन पर मनसे कार्यकर्ताओं ने रेलवे परीक्षा देने आए उम्मीदवारों को मारा था. हालांकि शिवसेना कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका में अपनी सत्ता क़ायम रखने में कामयाब रही, लेकिन उसे सफलता दिलाने में मनसे की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही. मनसे ने महापौर के चुनाव मे हिस्सा नहीं लिया. इससे शिवसेना को सत्ता की चाबी मिल गई. बदले में मनसे को विरोधी पक्ष नेता का पद मिल गया. पिछले साल के कुछ शहरों के नगरपालिका चुनाव को देखें, तो कुछ हद तक इसी तरह की राजनीति देखी गई है. एक तरफ़ शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का परिवार और राज ठाकरे आमने-सामने हैं. उद्धव और राज, ये दो भाई आपस मे भिड़ते हैं तो दूसरी तरफ़ मनसे की वजह से शिवसेना को फ़ायदा पहुंचता है. अब जनता इस बात को किस नज़र से देखती है यह आने वाले चुनाव में ही दिखाई देगा. रहा सवाल मुंबई महानगर पालिका चुनाव का, तो शिवसेना और मनसे की भिड़ंत में किसी तीसरे को फ़ायदा पहुंच सकता है. मनसे और शिवसेना के इन अस्पष्ट तेवरों से भाजपा परेशान है. विधानसभा चुनाव में मनसे की वजह से भाजपा को नुक़सान पहुंचा था. दोनों भाइयों की खींचतान में भाजपा पिस रही है. इसका परिणाम औरंगाबाद और पुणे के चुनावों में देखा गया. मनसे की वजह से शिवसेना और भाजपा के बीच दरार भी पैदा हुई है. यही कारण है कि महाराष्ट्र में भाजपा के वरिष्ठ नेतागण दोनों भाइयों के बीच की दूरी कम करने का प्रयास करते रहते हैं. मुंबई में उत्तर भारतीयों की संख्या काफ़ी है. ज़ाहिर है कि इन वोटों पर कांग्रेस और भाजपा दोनों की नज़र है. भाजपा के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भी उत्तर भारतीय हैं. भाजपा पानीपुरी वाले मामले में चुप्पी साधे हुए है. दूसरी ओर कांग्रेस ने मनसे का विरोध किया, लेकिन मराठी मानुष को रिझाये रखने के लिए मनसे इस मामले का पूरा फ़ायदा उठाएगी और इसी वजह से शिवसेना भी हरकत में आ गई. महानगर पालिका प्रशासन ने पानीपुरी और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले ठेलों पर कार्रवाई शुरू की है. मामला सिर्फ़ पानीपुरी का नहीं है. यह महापालिका चुनाव का सिग्नल है. किस की पुरी में किस का पानी जाता है और उसका असली स्वाद कौन चखेगा, यह तो आनेवाला समय ही बताएगा.

मनोज जोशी
feedback@chauthiduniya.com

फोटो-प्रभात पाण्डेय

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 09 मई–15 मई 2011

www.chauthiduniya.com

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

विसंगतियों की मार से किसान बेहाल

सियाराम यादव

लाखों किसानों के जरिए द्वितीय हरित क्रांति की सफ़लता का सपना संजोए उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय कृषि योजना पर गोपनीयता का पर्दा डाल रखा है. इसके तहत किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के आंकड़े न तो सार्वजनिक किए जाते हैं और न ही यह सूचना उन ज़िला कृषि अधिकारियों को मुहैया कराई जाती है जिनके कंधों पर इसके क्रियान्यवयन की ज़िम्मेदारी है. सरकार और बीमा कंपनी दोनों के पास ऐसा कोई सिस्टम विकसित नहीं हो सका है, जिससे नुक़सान की भरपाई का इंतजार कर रहा किसान यह जान सके कि उसे बीमा कंपनी से कितनी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति दी जा रही है. इस मामले में लखनऊ स्थित एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट भी सूनी-सूनी है. कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी कुंवर सेन गंगवार कहते हैं कि कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली धनराशि का विवरण आपको हमारी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा. संबंधित आंकड़े हमारे कार्यालय आकर देखे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रार्थना पत्र देना होगा. यह भी बताया गया कि क्षतिपूर्ति का विवरण कृषि सांख्यिकी और फ़सल बीमा निदेशालय में प्रेषित किए जाते हैं, लेकिन निदेशक विनोद कुमार सिंह का कहना है कि यह काम बीमा कंपनी का है. हम ज़िलों से क्रॉप कटिंग के आकड़े जुटाकर उसे बीमा कंपनी को प्रेषित करते हैं, इसके पश्चात हमारा काम समाप्त हो जाता है.

जनसूचना अधिकार और संचार के युग में दकियानूसी ढर्रे पर चल रही यह व्यवस्था किसानों के ख़िलाफ़ है. ज़िला कृषि अधिकारी फ़ैज़ाबाद डॉ. योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें काफ़ी मशक्क़त और लिखा-पढ़ी के बाद न्याय पंचायतवार लाभान्वित किसानों की जानकारी दी गई, लेकिन किसानों का व्यक्तिगत विवरण फिर भी नहीं उपलब्ध कराया गया. हालांकि कंपनी ने दावा किया है कि रबी सत्र 2009-10 के लिए उसने किसानों को 35.6 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में जारी किए हैं. यह धनराशि किसानों के ऋण खातों में सीधे भेजी जा रही है. किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का लाभ मिलने की जानकारी उस स्थिति में होगी, जब उसके खाते में धनराशि आ जाएगी. लेकिन यदि किसी कारणवश उसके खाते में धनराशि न पहुंचे उन स्थितियों में क्या होगा. उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ख़रीफ़ 2000 से भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार चलाई जा रही है. इसमें ख़रीफ़ और रबी सत्र के लिए अधिसूचित फ़सलों के प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों व रोगों के कारण फ़सल नष्ट होने की स्थिति में बीमित कृषकों को सहायता प्रदान की जाती है तथा आपदा वर्ष में कृषकों की आय स्थिर रखने का प्रयास किया जाता है. इसमें प्रगतिशील कृषि तरीक़ों एवं प्रोद्योगिकी के प्रयोग हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने की बात भी शामिल है. 2009-10 के लिए बीमा कंपनी ने किसानों से 38.95 करोड़ रुपए वसूले भी इस सत्र में रबी की प्रमुख फ़सल गेहूं में सिकुड़न के चलते उत्पादन प्रभावित हुआ था और किसानों को घाटा उठाना पड़ा था.

समस्त जनपदों में लागू

- अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फ़सल उगाने वाले बटाईदार काश्तकारों सहित सभी कृषक अनिवार्य और स्वैच्छिक आधार पर सम्मिलित
- अनिवार्य आधार पर वित्तीय संस्थाओं (सहकारी/ व्यावसायिक/ ग्रामीण बैंक) से फ़सली ऋण लेने वाले सभी कृषक स्वेच्छा के आधार पर सम्मिलित हो सकते हैं.
- प्याज़ एवं गन्ना को विकास खंड एवं शेष सभी को न्याय पंचायत स्तर पर अधिसूचित किया जाता है.
- प्रीमियम दरें ख़रीफ़ फ़सल हेतु बाजरा एवं तिलहन फ़सलों हेतु बीमित धनराशि का 3.5 प्रतिशत वास्तविक दर जो कम हो एवं अन्य खाद्यान्न फ़सलों हेतु बीमित धनराशि का 2.5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो कम हो.
- रवी फ़सल हेतु बीमित धनराशि का 1.5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो कम हो एवं खाद्यान्न फ़सलों हेतु 2.0 प्रतिशत का वास्तविक दर जो कम हो.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की सबसे बड़ी विसंगति अधिसूचना के स्तर को लेकर है. फ़सलें न्याय पंचायत और विकास खंड स्तर पर अधिसूचित की जाती हैं और प्राकृतिक आपदाओं, कीटों आदि से संभावित नुक़सान का आंकलन भी इसी आधार पर किया जाता है, जबकि किसान बीमा रक़म का व्यक्तिगत स्तर पर भुगतान करते हैं, लेकिन जब मुआवज़े की बात आती है तो न्याय पंचायत के उत्पादन गिरावट को ध्यान में रखा जाता है, एक किसान की फ़सल ओलावृष्टि या कीड़े लगने से चौपट हो जाए तो पूरी न्याय पंचायत में ऐसा ही हो यह ज़रूरी नहीं है. ऐसी दशा में नुक़सान होते हुए भी किसान को क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी. ज़िले की मुकीमपुर ग्राम पंचायत के निवासी राजेंद्र तिवारी कहते हैं कि ख़रीफ़ फ़सल में साल भर पहले उनकी सारी फ़सल चौपट हो गई थी, लेकिन उन्हें मिला कुछ भी नहीं. कहने के लिए तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसानों की भलाई के लिए है, लेकिन योजना की विसंगतियों ने किसानों को इससे दूर कर दिया है. प्रतिवर्ष रवी व ख़रीफ़ में करोड़ों रुपए का बीमा प्रीमियम अदा करने वाले किसानों को फ़सल क्षतिपूर्ति मिलने की बात आती है तो योजना के नियम-क़ायदे आड़े आ जाते हैं. व्यवस्था है कि किसानों को लाभ उसी स्थिति में दिया जा सकता है जब कि फ़सलों की क्षति न्याय पंचायत स्तर पर हो योजना में जिन आधारों पर फ़सल क्षति होने पर क्लेम दिए जाने की व्यवस्था है, ज़रूरी नहीं कि उन प्राकृतिक आपदाओं तथा बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि का प्रभाव न्याय पंचायत में एक समान दिखे. गन्ने के मामले में तो क्षतिपूर्ति उस स्थिति में ही देय होगी जब नुक़सान का निर्धारित स्तर अधिसूचित ब्लॉक में पाया जाए. किसानों का कहना है कि जब बीमा प्रीमियम वे व्यक्तिगत स्तर पर अदा करते हैं तो फिर देय भुगतान के लिए न्याय पंचायत स्तर पर नुक़सान होने की बात क्यों कहीं जाती है? अक्सर यह देखा जाता है कि न्याय पंचायत के एक हिस्सा बुरी तरह बाढ़, सूखा, रोग या ओलावृष्टि से प्रभावित हो जाता है, लेकिन किसानों को मिलता कितना है.क्रॉप कटिंग के आंकड़े भी बीमा योजना में क्षतिपूर्त के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. उन्हीं आंकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति की जाती है. किसानों की मांग है कि इसे व्यक्तिगत स्तर पर लागू किया जाए, फिर चाहे क्षतिपूर्ति की धनराशि कम ही क्यों न दी जाए. फ़सल नुक़सान की दाम में किसान को यदि बीमा कराने के बदले फ़सल में निवेशित राशि ही मिल जाए तो वही बहुत है.

feedback@chauthiduniya.com

> राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की सबसे बड़ी विसंगति अधिसूचना के स्तर को लेकर है. फ़सलें न्याय पंचायत और विकास खंड स्तर पर अधिसूचित की जाती हैं और प्राकृतिक आपदाओं, कीटों आदि से संभावित नुक़सान का आंकलन भी इसी आधार पर किया जाता है, जबकि किसान बीमा रक़म का व्यक्तिगत स्तर पर भुगतान करते हैं, लेकिन जब मुआवज़े की बात आती है तो न्याय पंचायत के उत्पादन गिरावट को ध्यान में रखा जाता है, एक किसान की फ़सल ओलावृष्टि या कीड़े लगने से चौपट हो जाए तो पूरी न्याय पंचायत में ऐसा ही हो यह ज़रूरी नहीं है.

बीमा कंपनी ने अब तक क्या दिया

वर्ष	प्रीमियम की धनराशि करोड़ रुपए में	क्षतिपूर्ति लाख रुपए में
2000	10.52	785.28
2001	9.87	648.05
2002	17.56	2807.92
2003	16.84	3695.91
2004	31.79	12065.79
2005	33.27	7926.66
2006	56.25	14163.34
2007	63.94	21304.69
2008	59.24	5237.58
2009	89.40	153.6602
2010	---	---

जनपद फ़ैज़ाबाद के लाभान्वित किसान (2009-10)

न्याय पंचायत का नाम	लाभार्थी किसान	प्राप्त क्षतिपूर्ति रुपए
रामनगर धौरहरा	98	16632
पिलखांवा	312	298786
तसीमपुर	208	367042
बरवा	284	128718
कोटसराय	296	7119
महमूदमऊ	228	647893
हलीम नगर	489	603994
बंवा	413	128061
मोहम्मदपुर	105	18397
गद्दोपुर	124	8623
कंदईकला	203	401274
मानूडीह	11	3169
रायपट्टी	38	48909
गोकुला	31	1266
तेंधा	64	28088
सिडसिड	177	307311
कुचेरा	214	96533
घुरेहटा	282	55482
बेनीगदोपुर	209	242430
हैदरगंज	368	106647
गुरौली	249	135924
टिकरी	307	61883
केरालालखां	200	46011
बैंतीकला	639	66581
कोंछा	412	275314
पौसारा	162	13669
उनिया	175	11625
बंदनपुर	248	31671
मयाभीखी	236	69571
करमा पढरी	1	3947
भदौली बुर्जुग	101	27017
रसूलाबाद	212	23135
अलावलपुर	90	18484
कुसमहा	170	108034
सिसिंडा	230	3201

एक नज़र

ताजमहल और क़िले में ऑडियो गाइड की सुविधा

आगरा के ताजमहल और क़िले में सैलानियों को अब किराये पर ऑडियो गाइड मिलने शुरू हो गए हैं. पिछले दिनों दिल्ली की एक कंपनी ने ऑडियो गाइड सुविधा का ट्रायल लिया था जो पूरी तरह सफल रहा था. ऑडियो गाइड सेवा के संबंध में पिछले एक साल से कवायद चल रही थी जो अब जाकर पूरी हुई. अब सैलानियों को महंगे गाइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ ही वे भ्रमित करने वाली मनगढंत इतिहास की जानकारी से भी बचेंगे. ताजमहल पर ऑडियो गाइड की स्क्रिप्ट 1 घंटे की और क़िले पर एक घंटे 15 मिनट की है. हिंदी और अंग्रेजी के अलावा गुजराती, तमिल, बांग्ला, स्पेनिश, फ्रेंच, डच, रशियन आदि नौ भाषाओं में ऑडियो गाइड ताज और क़िले पर इतिहास, आर्कीटेक्चर की जानकारी देगा. ऑडियो गाइड के लिए जगह-जगह प्वाइंट्स बनाए गए हैं. इन प्वाइंट्स के नंबर निश्चित किए गए हैं. पर्यटक जैसे ही ईयरफोन लगाकर ऑडियो गाइड को चालू करेंगे, उन्हें प्वाइंट्स पर पहुंचने के लिए कहा जाएगा. पर्यटक जिस प्वाइंट पर पहुंचेगा उसे उसी प्वाइंट की जानकारी गाइड की तरह मिलना शुरू हो जाएगी. इसके लिए देशी पर्यटक को 60 रुपये और विदेशी पर्यटक को 100 रुपये चुकाने होंगे. ताजमहल पर ग्लास हाइस और क़िले के मुख्य द्वार पर ऑडियो गाइड मिल रहे हैं.

शिशु सदन के बच्चे बेघर हो सकते हैं

आगरा के शिशु सदन के बच्चे कभी भी बेघर हो सकते हैं. दरअसल जिस भवन में शिशु सदन चल रहा है, उसे ख़ाली करने के नोटिस मिल चुके हैं. इसके अलावा भी इस भवन में अनेक समस्याएं हैं. इन समस्याओं के चश्मदीद गवाह बने मानवाधिकार आयोग के सदस्य नरेश पारस और क्वालिटी इंस्टीट्यूशन एंड अल्टरनेटिव फॉर चिल्ड्रेन की स्टेट कोऑर्डीनेटर विनीका करोरी. वे हाईकोर्ट के निर्देश पर शिशु सदन की विजिट पर पहुंचे थे. राजकीय शिशु सदन की अधीक्षिका रेनु बाला ने बताया कि एक साल से शिशु सदन के लिए कोई ज़मीन नहीं मिल पा रही है, जबकि भवन को ख़ाली करने का नोटिस मिल चुका है. मानवाधिकार आयोग के सदस्य नरेश पारस ने शिशुओं की सुरक्षा व संरक्षा के लिए शिशु सदन में चौकीदार व अन्य इंतज़ाम न होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की. शिशु सदन की अधीक्षिका ने शिशु सदन में स्टाफ की कमी बताई. उल्लेखनीय है कि इसको लेकर ही हाईकोर्ट में एक रिट दायर है, जिसके तहत ही यह विजिट की गई थी. प्राप्त तथ्यों को अब हाईकोर्ट के समक्ष रखा जाएगा.

टेलीग्राफ सेवा ख़त्म होने के कगार पर

देश में पहली बार टेलीग्राफ (तार) सेवा सन् 1853 से आगरा से कोलकाता के बीच शुरू हुई थी. अंग्रेजी सरकार अपनी सारी सूचनाएं इसी के ज़रिये भेजती और मंगाती थी. आज़ादी के बाद भी लोगों ने इसका ख़ूब लाभ उठाया. यहां तक कि समुद्र में सब-मरीन केबल डालकर विदेशों से भी टेलीग्राफ भेजने और मंगाए जाने लगे. पिछले दो दशकों में इंटरनेट, मोबाइल और 3जी आदि सेवाओं के चलते टेलीग्राफ का चलन बहुत घट गया है. आगरा में 1980 में हर रोज़ टेलीग्रामों की संख्या 15000 से ज़्यादा होती थी. अब केवल 40-50 टेलीग्राम ही होते हैं. अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राम तो साल में एक या दो होते हैं. लगातार घाटे में चलने के कारण शासन ने अब इस संचार सुविधा को बंद करने की तैयारी कर ली है. आगरा बीएसएनएल के जीएम एच. एस. शर्मा के अनुसार टेलीग्राफ सेवा अब ख़त्म होने के कगार पर है. अंतरराष्ट्रीय सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है. जल्द ही तारघर के कर्मचारियों को दूसरे पटलों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा. हर टेलीग्राफ आफिस में अब तीन-चार कर्मचारी ही रखे जाएंगे.

हिंदी संस्थानों के पुरस्कारों पर विवाद

उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सबसे बड़े पुरस्कार भारत-भारती के लिए चुने गए साहित्यकार अशोक वाजपेई के पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने में अनिच्छा ज़ाहिर करने से पैदा हुए विवाद पर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह चुप्पी साध ली है. संस्थान के पुरस्कारों की संख्या 87 से घटाकर मात्र 3 कर दिए जाने के फ़ैसले पर पुनर्विचार के सुझाव पर राज्य सरकार से कोई जवाब न मिलने और पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री या राज्यपाल के शिरकत न करने की कथित सूचना को वाजपेई ने अपना अपमान क़रार दिया है. उन्होंने कहा कि निर्णायक मंडल की सिफ़ारिश के बावजूद अनेक पात्र साहित्यकार पुरस्कार से महरूम रह जाएंगे. इस तरह इस पुरस्कार वितरण समारोह पर तरह-तरह के विवाद खड़े होंगे. लिहाज़ा वह इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते. प्रदेश के भाषा विभाग के प्रमुख सचिव अनिल घोष को पत्र लिखकर उन्होंने सुझाव दिया है कि उनकी पुरस्कार राशि उन्हें डाक से भेज दी जाए और अगर इसमें कोई अड़चन है तो सरकार इस धनराशि को अपने पास रख ले.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आंगनवाड़ी
कार्यकर्ताओं और अफ़सरों में रार

राजेंद्र सारथी

बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण के अधिकार को सुनिश्चित करने में आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता को अंतिम कड़ी के रूप में जाना जाता है, इसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है. ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मां के पेट में बच्चे के गर्भ धारण करने से लेकर शिशु टीकाकरण, शिक्षा एवं विधवा-वृद्ध पेंशन आदि में भी पूरा सहयोग करती हैं. नाममात्र के मानदेय पर काम करने वाली ये कार्यकर्ता अपने भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में आकर कुछ तो खुद भ्रष्ट हो जाती हैं और जो ईमानदारी से जीना चाहती हैं, उन्हें अपने अधिकारियों की विभिन्न प्रताड़नाओं और कोप का सामना करना पड़ता है. उन्हें नौकरी छिनने का भय हर समय सताता रहता है. फ़िरोज़ाबाद जनपद में ऐसे ही दबाव के तहत घुटन में जी रही कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कहानी हम यहां पेश कर रहे हैं.

अप्रैल के प्रथम सप्ताह में फ़िरोज़ाबाद के ज़िला कार्यक्रम अधिकारी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मोहिनी कुलश्रेष्ठ जो आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की ज़िला अध्यक्ष भी हैं, को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि आप द्वारा धारित संघ ने बाल विकास परियोजना शहर प्रथम एवं द्वितीय के अंतर्गत किराए के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के किराया भवनों के भुगतान हेतु समय-समय पर मांग की, जिसे गंभीरता से लिया गया, जबकि शासनादेश के अनुसार भवन किराए पर लेने की प्रक्रिया जैसे आवेदन पत्र, प्रस्तावित भवन का नक्शा, ब्लूप्रिंट, भवन स्वामी का सहमतिपत्र एवं भवन स्वामी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मध्य किरायेदारी अनुबंध एवं शपथपत्र आदि संबंधित दस्तावेज़ परियोजना कार्यालय में जमा कराने के लिए आपको पर्याप्त अवसर दिया गया. बाल विकास परियोजना शहर प्रथम और द्वितीय के अंतर्गत कुल संचालित 431 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 31 मार्च 2011 तक मात्र 370 आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं द्वारा किराया स्वीकृति एवं भुगतान हेतु संबंधित दस्तावेज़ सीडीपीओ को उपलब्ध कराए, जबकि 61 आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं द्वारा विषयगत उपयुक्त दस्तावेज़ सीडीपीओ को उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसमें आपके केंद्र का नाम भी उल्लेखनीय है. सीडीपीओ प्रथम द्वारा अवगत कराया गया है कि आप दोनों कार्यकर्ताओं द्वारा जून 2007 से मार्च 2011 तक किराया संबंधित दस्तावेज़/प्रस्ताव उपलब्ध कराए किराये के भुगतान की मांग की जा रही है. संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि अवशेष 61 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गुमराह कर उपरोक्तानुसार प्रस्ताव न देने तथा संगठित रहकर विरोध करने के लिए आपके ही द्वारा प्रेरित किया गया. विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों की छवि धूमिल करने के लिए मनगढंत शिकायतें भेजी गई तथा अख़बारबाज़ी एवं गलत बयानबाज़ी की गई. जिन उक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किराये भुगतान हेतु प्रस्ताव दिए हैं उनको भी आप द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है. संघ के नाम पर दबाव बनाकर उनसे चंदा वसूली भी की जा रही है. यह भी पाया गया है कि दोनों तैनात केंद्र पर नियमित रूप से विभागीय मानकों के अनुसार केंद्र का सुचालन व पुष्टाहार आदि का वितरण न करके संघ एवं संगठन के नाम पर केंद्र से प्रायः अनुपस्थित रहना व धरना-प्रदर्शन में शामिल होना पाया गया. शहर परियोजना कार्यालय में संघ संगठन के कतिपय पदाधिकारियों व महिलाओं के साथ आकर सीडीपीओ एवं सुपरवाइज़र से किराये के भवन आदि विषय को लेकर विवाद करना और कार्यालय के शासकीय कार्य को प्रभावित करना सीडीपीओ द्वारा अवगत कराया गया. इसके संबंध में पत्र प्राप्ति के दो दिन के अंदर बाल विकास परियोजना के माध्यम से उपलब्ध कराएं. यह आरोप पत्र और कुछ नहीं दो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मोहिनी कुलश्रेष्ठ और आशमा कुलश्रेष्ठ को नौकरी से निकालने की ही कार्यवाही है. मोहिनी कुलश्रेष्ठ आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की ज़िला अध्यक्ष और आशमा कुलश्रेष्ठ महामंत्री हैं. उनके नेतृत्व में अनेक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अधिकारियों के शोषण का शिकार होने से बची हुई हैं साथ ही वे अपने हक की मांग भी करने लगी हैं, यह बात संबंधित अधिकारियों को बेहद अखरती है.

विवाद 2007 से शुरू होता है. आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन, उत्तर प्रदेश की फ़िरोज़ाबाद ज़िला इकाई की अध्यक्ष मोहिनी कुलश्रेष्ठ और महामंत्री आशमा कुलश्रेष्ठ ने जब लिखित रूप से 10 जुलाई 2007 को ज़िला कार्यक्रम अधिकारी से 2005 से 2006 तक शासन द्वारा निर्धारित भवन किराया 100 रुपया प्रतिमाह की दर से और अक्टूबर 2006 से जनवरी 2007 तक का भवन किराया बढ़ी हुई दर 500 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से और फरवरी 2007 से बढ़ी हुई 750 रुपये प्रतिमाह की दर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मांगा जिसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मालिकों को अपने पास से दे चुकी थीं. इसे ज़िला कार्यक्रम अधिकारी ने अपनी तौहीन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जुर्रत माना. यह मांग यूनियन के लेटरहेड पर की गई थी तो उन्होंने कहा कि बजट आने पर ही भुगतान संभव है. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 25 जुलाई 2007 को अपना ज्ञापन ज़िलाधिकारी फ़िरोज़ाबाद को भी दिया. पत्र का प्रभाव हुआ और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जुलाई 2007 तक का भवन का किराया दे दिया गया. इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह विश्वास हो गया कि ज़िलाधिकारी को मामले की जानकारी दे दी जाए तो सुनवाई जल्दी हो जाती है. अतः 8 नवंबर 2008 को उन्होंने पांच बिंदुओं वाला एक ज्ञापन ज़िलाधिकारी को दिया जिसमें उन्होंने लिखा -

1. अगस्त 2007 से आज तक का भवन किराया उन्हें नहीं मिला है.
2. आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार ले जाने के लिए दिया जाने वाला ढुलाई भत्ता 2007 से बंद कर दिया गया, जबकि कोई भी रिक्शाचालक या रेहड़ी वाले पोषाहार को आंगनवाड़ी केंद्र तक पहुंचाने का सामान्य ढुलाई 30-50 रुपये तक लेता है. अब यह भाड़ा दोगुना हो गया है.
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय अगस्त 2008 से बढ़ाया है, जबकि अक्टूबर माह में दिवाली थी, त्योहार से पूर्व मानदेय का भुगतान होना चाहिए था, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को मानदेय नहीं मिला.
4. हॉट कुक्स पोषाहार तैयार करने के लिए किसी भी केंद्र पर सामान (भगोना, बड़ा चमचा, ईंधन आदि) नहीं हैं. जुलाई 2007 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने पास से साधन जुटाकर और पोषाहार को पकाकर वितरण कर रही हैं.
5. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बीमा धनराशि 80 रुपये प्रतिवर्ष काटी जाती है, जबकि जमा की कोई लेखापर्ची या पासबुक किसी कार्यकर्ता को नहीं दी गई. भवन किराया, ढुलाई भत्ता, मानदेय और पोषाहार पकाने का अतिरिक्त मानदेय प्रतिमाह की दर से और बीमे की लेखापर्ची शीघ्रातिशीघ्र दिलाई जाए.

कई सालों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे केंद्र के किराये नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं ने धरने के माध्यम से अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने का कार्यक्रम तय किया. यूनियन के लैटरहैड पर उन्होंने इसकी सूचना सभी प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी. 29 दिसंबर 2010 से उन्होंने अपना अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया. धरने की प्रतिक्रिया हुई तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ओ.के.सिंह ने मौक़े पर आकर सभी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया कि उनके भवन किराये का भुगतान पंद्रह दिन के अंदर दिया जाएगा, लेकिन यह कोरा आश्वासन ही साबित हुआ.

आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के लेटरहेड पर यह ज्ञापन निदेशक बाल विकास, लखनऊ, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी शहर प्रथम फ़िरोज़ाबाद, महिला आयोग, नई दिल्ली, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को रजिस्ट्री द्वारा भेजा गया.

मांगपत्र विभिन्न उच्चाधिकारियों के पास भेजा गया था तो संबंधित अधिकारियों से इसके बारे में जवाब-तलब हुआ. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इस कार्यवाही को ज़िले के संबंधित अधिकारियों ने अपने विरुद्ध दुस्साहस माना. उन्होंने इस संबंध में आंतरिक बैठकें कीं और 7 फरवरी 2009 को ज़िला कार्यक्रम अधिकारी ने संघ के पदाधिकारियों को लिखित जवाब दिया कि भवन स्वामी का सहमतिपत्र, मुख्य सेविका एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के भवन किराये के प्रमाणपत्र का स्वीकृति पत्र, भवन किराया लेने के आवेदन के साथ जमा कराएं.

इसके जवाब में आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष मोहिनी कुलश्रेष्ठ ने पत्र लिखकर ज़िला कार्यक्रम अधिकारी से पूछा कि पूर्व में सन् 2005 से जुलाई 2007 तक का भुगतान बिना किसी अनुबंधपत्र आदि दस्तावेज़ों के ही भवन किराए का भुगतान समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बचत खाते के माध्यम से किया जा चुका है. तब इन प्रपत्रों की मांग क्यों नहीं की गई थी, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन होने के उपरांत बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा केंद्र के संचालन हेतु भवन किराये पर लेने का सहमतिपत्र या कार्यकर्ता एवं भवन स्वामी द्वारा संयुक्त अनुबंधन पत्र जैसा कोई भी पत्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्राप्त नहीं कराया गया था. यह भी पूछा गया कि यदि शासन से इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त हुआ था तो फिर किस परिस्थितिवश अब तक कार्यकर्ताओं को अवगत नहीं कराया गया? कार्यकर्ताओं को अब तक क्यों गुमराह किया गया? 17 माह के उपरांत अब आप भवन स्वामी द्वारा 10 रुपये के स्टांप पेपर पर अनुबंधपत्र प्रेषित करने की बात कर रहे हैं, जबकि कोई भी भवन स्वामी केंद्र संचालन हेतु 10 रुपये के स्टांप पेपर पर अपनी सहमति देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें तो किराया कार्यकर्ताओं द्वारा मिल ही चुका है, लेकिन ज़िला कार्यक्रम अधिकारी ने इस पत्र का संघ के पदाधिकारियों को कोई जवाब नहीं दिया. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 15 सितंबर 2009 को तहसील दिवस पर अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में अगस्त 2007 से अगस्त 2009 तक आंगनवाड़ी केंद्रों का भवन किराया न मिलने की शिकायत के साथ इसे शीघ्रातिशीघ्र दिलाने की मांग की. 1 अक्टूबर 2009 को ज़िला कार्यक्रम अधिकारी ने उपज़िलाधिकारी सदर को प्रति उत्तर में वही पुरानी बातें दोहराईं कि इस संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भवन किराये स्वीकृति हेतु भवन स्वामी/स्वामिनी का सहमति पत्र एवं नक्शा नज़री, मानचित्र ब्लूप्रिंट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किराया स्वीकृति हेतु आवेदनपत्र स्वीकृत कराने के लिए संबंधित कार्यकर्ताओं से कागज़ात आदि की प्रतियां मांगी गई थीं. 185 कार्यकर्ताओं में से 169 कार्यकर्ताओं को उपलब्धपत्र प्राप्त हुए, लेकिन बाक़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा वांछित अभिलेखों का नहीं दिए जाने से लगता है कि ये केंद्र किराये पर लेकर नहीं चलाए जा रहे हैं. इस पर कार्यकर्ताओं ने धरने के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचाने का कार्यक्रम तय किया. यूनियन के लैटरहैड पर उन्होंने इसकी सूचना सभी प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी. 29 दिसंबर 2010 से उन्होंने अपना अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया. धरने की प्रतिक्रिया हुई तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ओ.के.सिंह ने मौक़े पर आकर सभी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया कि उनके भवन किराये का भुगतान पंद्रह दिन के अंदर करा दिया जाएगा. इस आश्वासन के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना धरना समाप्त कर दिया, जब वर्ष 2010 का आश्वासन की भेंट चढ़ गया तब कार्यकर्ताओं ने 25 मार्च को प्रेस वार्ता करके अपनी व्यथा अख़बारों के माध्यम से पहुंचाने का निर्णय लिया. प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि तीन साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भवन किराया नहीं दिया गया है. किराया भुगतान न करने की नीयत से ज़िला कार्यक्रम अधिकारी भवन स्वामी एवं कार्यकर्ता से संयुक्त अनुबंधपत्र, भवन/केंद्र का ब्लूप्रिंट, नक्शा, भवन स्वामी का सहमतिपत्र आदि कार्यकर्ताओं से मांगे जा रहे हैं, जबकि ये केंद्र संचालित हो रहे हैं, कभी भी ऐसी औपचारिकताएं पूरी करने की मांग नहीं हुई. अफ़सोस की बात यह है कि कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दबाव में आकर उक्त औपचारिकताएं पूरी करके दे भी दी हैं. इसके बाद भी उन कार्यकर्ताओं को मात्र वर्ष 2010-11 का ही भवन किराया दिया गया है. अगस्त 2007 से फरवरी 2010 तक का भवन किराया उन्हें देने का कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया गया है, बल्कि बीच के अवशेष किराये की बात करने पर ज़िला कार्यक्रम अधिकारी व बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा कार्य से हटाने की धमकियां दी जा रही हैं. यह भी कहा जा रहा है कि यदि भवन किराये के संबंध में ज़्यादा ज़िद करोगी तो पूर्व की नेता कार्यकर्ता जैसा व्यवहार किया जाएगा.

प्रेस वार्ता में कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि हम अपनी यूनियन द्वारा ज़िला कार्यक्रम अधिकारी, ज़िलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा स्थानीय विधायक व सांसद को तीन साल के बक़ाया भवन किराये के संबंध में अवगत करा चुके हैं, पर कोई संतोषजनक कार्यवाही न होने पर सभी कार्यकर्ताओं में असंतोष व्याप्त है. यदि शीघ्र ही अवशेष भवन किराये का भुगतान नहीं किया गया तो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए विवश होंगी. स्पष्ट है कि यहां जो भी अनियमितता अथवा तानाशाही की जा रही है वह ज़िला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ही की जा रही है. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो इस मामले में एकदम बेबाक और पाक-साफ़ दिखाई देती हैं.

feedback@chauthiduniya.com

चुनावी समर जीतने की तैयारी

मायावती ने फ़िरोज़ाबाद के पांचों विधान सभा क्षेत्रों से मिशन 2012 को सफल बनाने वाले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. फ़िरोज़ाबाद से पहली बार सपा विधायक और दूसरी बार बसपा विधायक रहे नसीरूद्दीन सिद्दीक़ी, शिकोहाबाद से डॉ. मुकेश वर्मा, टूंडला से विधायक राकेश बाबू एडवोकेट, जसराना से पिछले चुनाव में टिकट से वंचित रह जाने वाले राम गोपाल लोधी, सिरसागंज पहले सपा और अब बसपा सरकार में मंत्री जयवीर सिंह के पुत्र अतुल प्रताप सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, स्वयं मंत्री जयवीर सिंह को करहल विधान सभा क्षेत्र से लड़ने को कह दिया गया है.

बसपा की टिकट वितरण कार्यवाही के पश्चात् भाजपा सरकार में मंत्री रहे गत लोकसभा चुनाव लड़े रघुवर दयाल वर्मा ने पूरे राजनीतिक जीवन में 36 का आंकड़ा रहे मुलायम सिंह यादव से हाथ मिला लिया. सिरसागंज नगर पालिका अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने चुनाव बसपा विधायक व मंत्री बने जयवीर सिंह से नज़दीकी के चलते जीता था. वह विधान सभा प्रत्याशी बनना चाहते थे मनोकामना पूर्ण न होते देख वह भी सपा में आ गए. टिकट वितरण के बाद अपने प्रिय नेताओं के साथ क़स्बा व ग्रामीण स्तरीय नेता भी चले गए हैं, उनके द्वारा उक्त चुनाव विशेष रूप से तो प्रभावित नहीं किया जाएगा, लेकिन मोहल्ले व गांवों में प्रभाव डाला जा सकता है. बसपा द्वारा घोषित पांचों विधान सभा क्षेत्रों में बदलाव की ज़्यादा संभावना नहीं है फिर भी आगरा से विधायक व सरकार में मंत्री नारायण सिंह सुमन टूंडला विधान सभा क्षेत्र आश लगाए हैं. बदलते परिसीमन में सामान्य सीट हो जाने के कारण वह अपनी राजनीतिक ज़मीन फ़िरोज़ाबाद ज़िले में पाने हेतु लालायित हैं. योजना के तहत उन्होंने ज़िला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में दस्तक दी थी. इस समय तो टूंडला के विधायक राकेश बाबू एडवोकेट ने हाईकमान में अपनी पैठ एवं ग़ैर जनपद वासी का कार्ड खेलकर उन्हें वापस कर दिया था. चर्चा है कि टूंडला विधानसभा की सीट नारायण सिंह सुमन के लिए छोड़ दी जाएगी. विधायक राकेश बाबू बेटे को लालबत्ती दिलाने में सफल होने के पश्चात् अपनी सीट आसानी से छोड़ेंगे यह लगता नहीं है. यहां 50 हज़ार ब्राह्मण, 45 हज़ार ठाकुर, 45 हज़ार यादव, 35 हज़ार जाटव, 15 हज़ार चक समाज के मतदाता हैं. बसपा सरकार में सरकारी योजनाओं में एक ही समाज की भागीदारी की चर्चा एवं अनुसूचित समाज उत्पीड़न संबंधी रिपोर्ट के चलते ठाकुर, ब्राह्मण समाज के विरोध का सामना राकेश बाबू को करना पड़ सकता है. फ़िरोज़ाबाद से घोषित प्रत्याशी नसीरूद्दीन सिद्दीक़ी स्वास्थ्य के कारण सक्रिय नहीं रह पाते हैं. क्षेत्रीय स्तर के कार्य पूर्ण कराने हेतु प्रतिनिधि के रूप में उनके पुत्र ज़िम्मेदारी निभाते हैं. स्वच्छ और ईमानदार छवि की चर्चा आम जनता के मध्य जितनी नसीर साहब की होती है, उतनी ही नकारात्मक चर्चा उनके पुत्रगणों की होती है, जिसके कारण बसपा को नुक़सान उठाना पड़ सकता है. इस प्रकार की चर्चाओं से बसपा सुप्रीमो व काडर के माध्यम से वाक़िफ़ होती रहती है. उक्त विधान सभा क्षेत्र में अलग-अलग पहचान के 90 हज़ार मुस्लिम, इसी प्रकार 70 हज़ार वैश्य, 55 हज़ार ब्राह्मण, 20 हज़ार जाटव, 12 हज़ार यादव मतदाताओं की प्रमुखता है. शिकोहाबाद क्षेत्र से अनजान डॉ. मुकेश वर्मा के बारे में कहा जाता है कि चार बार विधायक व मंत्री रहे रघुवर दयाल वर्मा के भवन स्वामी के वह सुपुत्र हैं. बसपा सुप्रीमो ने पार्टी में एक वर्ष तक सक्रिय रहे वर्मा के घर के नीचे से ही प्रत्याशी खड़ा कर लिया. यादव 70 हज़ार, ब्राह्मण 40 हज़ार, लोधी व निषाद 42 हज़ार मतदाताओं वाले शिकोहाबाद क्षेत्र से बसपा को प्रभावशाली प्रत्याशी की खोज करनी होगी तभी बात बनेगी. सिरसागंज क्षेत्र के बदलते परिसीमन एवं सिंचाई विभाग के कर्मचारी की हत्या कराने के आरोप से घिरे मंत्री जयवीर सिंह जादौन के पुत्र अतुल प्रताप सिंह के स्थान पर मंत्री जयवीर सिंह को या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए. इस आशय की मांग अंदरख़ाने पनपने लगी है. मृदुभाषी एवं शालीन मंत्री जयवीर सिंह परिवार की शक्ति दो स्थान सिरसागंज व करहल में बंट गई तो दोनों ही स्थानों पर सफलता मिलेगी, इसमें संदेह है. केवल इसी आधार पर टिकट में परिवर्तन की बात चल निकली है. 80 हज़ार यादव, 45 हज़ार ब्राह्मण, 40 हज़ार क्षत्रिय, 20 हज़ार जाटव मतदाताओं की प्रमुखता वाले क्षेत्र में ब्राह्मण, बघेल व लोधी मतदाता जिताऊ व हराऊ की भूमिका निभा सकने में समर्थ हैं.

छोटे दल और निर्दलीय

जनपद में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, राष्ट्रीय समानता दल, अति पिछड़े वर्ग में जनाधार रखती है, वहीं पीस पार्टी का मुस्लिम समाज में दख़ल है, स्वामी रामदेव एवं के.एन.गोविंदाचार्य की अगुवाई में प्रारंभ होने वाले राष्ट्रवादी मोर्चे से भी कुछ लोग जुड़ सकते हैं. जसराना एवं सिरसागंज क्षेत्र में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकती है. ऐसा ही राष्ट्रीय समानता दल भी कर सकता है. पीस पार्टी फ़िरोज़ाबाद में प्रत्याशी उतार सकती है तो राष्ट्रवादी मोर्चा भी प्रत्याशी उतारने का प्रयास करेगा. सिरसागंज व शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्रों से सपा का टिकट प्राप्त करने हेतु एक महिला व पुरुष प्रत्याशी जिन्होंने बाबा रामदेव के प्रवास में प्रमुख भूमिका निभाई थी, अपना दांव आज़मा सकते हैं. भाजपा से टिकट की आस लगाए स्वच्छ छवि के प्रत्याशी असफल रहने पर चुनाव मैदान में राष्ट्रवादी मोर्चा तले उतर सकते हैं. पिछले चुनाव में राम प्रकाश यादव (जसराना) व पूर्व मंत्री अशोक यादव (शिकोहाबाद) निर्दलीय तौर पर विजयी होकर आए थे. लाख टके का एक सवाल यह है कि पूर्व चेयरमैन मनीष असीजा क्या करेंगे? फ़िरोज़ाबाद में हो रही चर्चाओं पर ध्यान दें तो वह कांग्रेस, भाजपा, सपा, राष्ट्रवादी मोर्चा अथवा निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा यह सवाल है कि इनकी योजना क्या होगी, की जानकारी किसको होगी. तो जवाब यह है कि निकटतम सहयोगी चाहे वह घनिष्ठतम मित्र हों अथवा अर्धांगिनी किसी को भी उनकी योजना की जानकारी नहीं होगी.

अरविंद मोहन
feedback@chauthiduniya.com

रिश्तेदारी गले की हड्डी बनी

शिवम तिवारी

मुलायम सिंह यादव फ़िरोज़ाबाद संसदीय उपचुनाव में अपनी पुत्रवधू डिंपल यादव के पराजित होने के सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि उनके मिशन 2012 के मार्ग में अब उनके रिश्तेदार ही भाले ठोंकने में जुटे दिखाई दे रहे हैं. अन्य राजनीतिक दलों में फैले रोग के अनुरूप ही सपा में भी यह रोग फैल गया है. रिश्तेदार मुलायम सिंह यादव ज़िंदाबाद का नारा तो लगाते हैं, लेकिन काम वो गॉड फादर्स के इशारे पर ही करते हैं. पार्टी में बग़ावती स्वरों को पनपने का अवसर सपा द्वारा जारी विधानसभा प्रत्याशियों की सूची में फ़िरोजाबाद ज़िले के सिरसागंज से पूर्व विधायक हरीओम यादव जो रिश्ते में सपा सुप्रीमो के समधी हैं और मैनपुरी सदर से राजीव यादव जो शिकोहाबाद के गांव नकटपुर निवासी हैं की घोषणा से प्रारंभ हो गया है. सपा के पुराने व दिग्गज नेतागण, कमरियावाद फैलाने का आरोप मुलायमसिंह यादव पर लगा रहे हैं. मैनपुरी में के.सी. यादव और फ़िरोज़ाबाद ज़िले में पूर्व विधायक व सपा सुप्रीमो की समधिन उर्मिला यादव बग़ावत पर उतर आई हैं. उर्मिला यादव सपा सुप्रीमो की भतीजी को ही सिरसागंज से चुनाव लड़वाने हेतु कटिबद्ध लग रही हैं. बाहरी के नाम पर मैनपुरी से टिकट प्राप्त राजीव यादव के विरुद्ध प्रोफेसर के.सी. यादव ने ताल ठोंक दी है. फ़िरोज़ाबाद जनपद में बग़ावत करने पर निष्कासित हो चुके पूर्व विधायक हरिओम यादव ने सीमा पार करके कटु शब्दों का प्रयोग किया था. आरोप था कि उन्होंने संसदीयउपचुनाव एवं ज़िला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य किया था, जिसके परिणामतः पार्टी प्रत्याशियों को पराजित होना पड़ा. ख़ेमे में चर्चा है कि सुप्रीमो के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि हरिओम यादव को सपा में वापस भी लेना पड़ा और टिकट की घोषणा भी पहले करनी पड़ी. फ़िरोज़ाबाद जनपद में सपा का टिकट चाहने वाले समर्पित व मौक़ा परस्तों के मध्य विभाजक रेखा खिंच गई है, भाजपा सरकार में मंत्री रहे और लोक सभा चुनाव लड़े रघुवर दयाल वर्मा भाजपा, बसपा के रास्ते सपा में दाख़िल होकर शिकोहाबाद सीट से दावेदारी पक्की मान रहे हैं. ऐसा हुआ तो साफ़-सुथरी छवि वाले समाजवादी पार्टी नेता लाखन सिंह यादव को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है. वैसे यहां से समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव और अभी हाल में सक्रिय हुए डॉ. दिलीप यादव भी मुख्य दावेदार हैं. सपा में बग़ावत के तेवरों से भाजपा ख़ेमे के यादव दावेदारों के चेहरों पर रौनक़ आ गई है. फ़िरोज़ाबाद सदर क्षेत्र में पूर्व जिलाध्यक्ष व विधायक अज़ीम भाई के नाम पर प्रभावी बग़ावत नहीं है. जसराना विधानसभा से प्रबल विरोध के चलते तीन बार के विधायक रहे रामवीर सिंह यादव से पराजित होना पड़ा था, इस बार उन्हें ज़िला पंचायत अध्यक्ष रही बहन का पुत्र राजीव यादव इंजीनियर जो कि सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई भी हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं. वहीं झपारा जसराना निवासी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (अपील) रहे सुरेंद्र सिंह यादव एडवोकेट भी दावेदारी कर रहे हैं, तीन कार्यकाल से उनके पुत्र एवं पत्नी के नाम ग्राम प्रधानी बरक़रार चली आ रही है, वहीं टूंडला विधानसभा से पूर्व विधायक मोहन देव शंखवार व रमेश चंद्र चंचल ही प्रमुख दावेदार हैं. सपा के कुनबे में आए इस बिखराव पर ध्यान देने पर याद आता है कि सपा सरकार के समय जसराना विधायक रामवीर सिंह व शिकोहाबाद विधायक हरीओम यादव के परिजन और नज़दीकी लोग ज़मीन पर क़ब्ज़ा कराने के अभियान में लगे थे. आपसी हित टकरा जाने पर वजूद दिखाने के नाम पर उनमें गोली भी चलती थी, सपा विधायकों के कृत्य पर एक सार्वजनिक सभा में सपा सुप्रीमो ने नाराज़गी भी जताई थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ. बढ़ते हौंसलों का ही फल था कि संसदीय उपचुनाव में डिंपल यादव पराजित हुई. ज़िला पंचायत अध्यक्ष चुनावों हेतु सपा राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन के परिवारीजनों के मतदाता बनने की राह में कांटे बिछाए गए.

पूर्व विधायक रमेश चंद्र चंचल को ज़िला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हेतु प्रत्याशी बनाया गया तो पूर्व विधायक हरीओम यादव ने अपने समर्थक सदस्यों को सपा से दूर रखा, जिन्होंने बसपा विधायक पुत्र को ज़िला पंचायत अध्यक्ष बनाने में सहयोग दिया. पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सुमन ने तुरुप की चाल के रूप में रघुवर दयाल वर्मा का सपा में प्रवेश करा दिया, जिससे सुमन ने अपनी विरोधी लॉबी को मुश्किल में डाल दिया है. सच्चाई यह है कि सपा सुप्रीमो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव, नेता विरोधी दल शिवपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव से तार जोड़कर रखने वाले सपा नेता मनमानी करते रहते हैं और असहाय मुलायम सिंह यादव सब कुछ देखते रह जाते हैं.

अंदर की बात

सैफ़ई में होली मिलन के अवसर पर सपा कार्यालय में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था. एक कमरे में सपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव बैठे हुए लोगों को अपनी बात कहने का समय दे रहे थे. सिरसागंज से विधानसभा प्रत्याशी के कुछ प्रबल समर्थक भी वहां गए हुए थे. उनका समय आया तो वे भी प्रदेश अध्यक्ष से मिले और उन्हें अपनी व्यथा बताई. सिरसागंज की सीट फाइनल करके आपने हमें तो धता ही बता दी. अखिलेश यादव ने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं! हमने अभी नाम ही तो घोषित किया है बी-फॉर्म नहीं पकड़ा दिया. चुनाव के समय तक तो बहुत कुछ फेरबदल हो सकता है. आप घबराते क्यों हैं. इसका नाम राजनीति है. सब तरह के दांव चलने पड़ते हैं. आपको जल्दी ही सपा मुखिया मुलायम सिंह जी से मिलवाने की कोशिश करता हूं. यह सुनकर संभावित प्रत्याशी के समर्थक उम्मीद की डोर थामे बाहर आकर बैठ गए. इसके थोड़ी देर बाद ही सिरसागंज के घोषित प्रत्याशी हरिओम यादव के छोटे पुत्र छोटू यादव अपने साथियों प्रदीप सिंह (पूर्व विधानसभा अध्यक्ष), शौर्यमणि देव, पिंटू मेंबर व अन्य के साथ वहां पहुंच गए. उनके हाथ में मिठाई के डिब्बे थे. प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष पहुंचकर वे मिठाई का डिब्बा रखकर बोले, मुंह मीठा कीजिए. अखिलेश यादव बोले, पहले यह तो बताओ कि यह मिठाई किस ख़ुशी में खिला रहे हो? छोटू यादव बोला, आपने पिताजी की टिकट सिरसागंज से घोषित कर दी है इसलिए. इस पर अखिलेश यादव बोले, सीट घोषित ही तो की है अभी क्लीयर तो नहीं की. आप लोगों ने क्षेत्र में अपने इतने शत्रु बना लिए हैं कि टिकट घोषित होते ही विरोध सुनते-सुनते हम तो तंग आ गए हैं. अब तो इस टिकट पर पुनर्विचार की ज़रूरत आ पड़ी है. इस पर छोटू यादव सफ़ाई देने लगा.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

होम्योपैथी ग़रीबों की पैथी

भारत में होम्योपैथी का इतिहास 201 साल पुराना है. एलोपैथी के बाद यह सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति है. सन् 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीतसिंह की इलाज के लिए फ्रांस के होम्योपैथिक डॉ. होनिंगबर्गर भारत आए थे. उनके इलाज से महाराजा को काफ़ी लाभ हुआ था. सन् 1881 में डॉ.पी.सी.मज़ूमदार एवं डॉ.डी.सी.राय ने कोलकाता में पहले होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की थी. आज इसके द्वारा लाइलाज घोषित रोगों में होम्योपैथी को अंतिम किरण की तरह देखा जा रहा है. यह विचार होम्योपैथी के जनक डॉ. सेमुअल हैनिमैन की 256वीं जयंती के अवसर पर आगरा के होटल रॉयल रेजीडेंसी में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के सदस्य डॉ. अनुरुद्ध वर्मा ने व्यक्त किए. समारोह की अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजय चौहान ने की. कार्यक्रम का आयोजन आगरा होम्योपैथिक कैमिस्ट एसोसिएशन ने किया था. इस अवसर पर होम्योपैथी के वरिष्ठ चिकित्सक रहे स्वर्गीय डॉ.जे.सी.शर्मा द्वारा लिखित काव्यकृति होम्योपैथिक रामायण के बारे में विस्तृत रूप से डॉ.महेंद्र वर्मा ने बताया. इसे गागर में सागर की संज्ञा दी गई. संस्थापक डॉ. योगेश चंद शर्मा ने सन् 1977 में भारत सरकार द्वारा जारी डॉ. सेमुअल हैनिमैन का एक दुर्लभ डाक टिकट प्रदर्शित किया तथा 1828 में डॉ. हैनिमैन की अंतिम महान कृति कॉनिक डिजीज के बारे में भी बताया. अजय चौहान ने संस्था के सदस्यों दिनेश चंद गुप्ता तथा डॉ. अंकित अग्रवाल को विशिष्ट सेवाओं के लिए स्मृति चिन्ह प्रदान किया. समारोह में लाड्स होम्यो लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड के देवेंद्र मरवानी, संस्था के अध्यक्ष के.के. गर्ग, डॉ.कैलाश चंद सारस्वत, डॉ.विजय यादव, डॉ. तरुण गुप्ता, डॉ. अजीत शर्मा, डॉ. पवन पारिक, डॉ. अरविंद जैन, डॉ. डी. एन. सारस्वत और डॉ. ओ. पी. वर्मा भी उपस्थित थे.

भूकंप त्रासदी में बचाव का प्रशिक्षण

आगरा महानगर में पिछले दिनों भूकंप से बचाव का प्रशिक्षण किया गया. इसकी थीम थी सुबह 9.30 बजे शहर में अचानक भूकंप आना. चार इलाक़ों का प्रभावित होना. कहीं आग लगना तो कहीं बिल्डिंग धंसना. भूकंप का संकेत मिलते ही राहत टीमों का दौड़ पड़ना. आग बुझाने के बाद घायलों को निकालकर एंबुलेंस से नज़दीकी अस्पतालों में पहुंचाना. तीन लोगों की जान जाना. प्रशिक्षण के लिए चार स्थान नियत किए गए थे, राजामंडी, शाहगंज, लोहामंडी चौराहा और कमलानगर, लेकिन शाहगंज में अति उत्साह में सिविल डिफेंस वाले अपनी भूमिका ही भूल गए. राजामंडी में एंबुलेंस बिना डॉक्टर के ही पहुंच गई, इसलिए घायल उतारने पड़े. पुलिस के जवान चारों स्थानों पर हाथ पर हाथ धरे ही दिखाई दिए. राहत शिविर में पर्याप्त इंतज़ाम नहीं थे, यहां तक कि स्ट्रेचर तक नहीं मिली. कई स्थानों पर अधिकारियों में समन्वय का अभाव दिखा यानी प्रशिक्षण कामयाब नहीं रही. बाद में समीक्षा करते हुए डीएम अजय चौहान, एनडीएमए सदस्य एके सिन्हा ने कहा कि यह पहला प्रशिक्षण ख़ामियों को जानने के लिए ही किया गया था. आगे इन ख़ामियों को ध्यान में रखकर ही योजना बनाई जाएगी.

संविदा चिकित्सकों का कार्यकाल बढ़ेगा

आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की कमी है. इस कमी को पूरा करने के लिए पिछले साल 25 डॉक्टरों को संविदा के आधार पर एक साल के लिए नौकरी पर रखा गया था. इनमें से कुछ का कार्यकाल दो महीने पहले समाप्त हो गया था. इन डॉक्टरों ने अपनी संविदा बढ़ाने के लिए दोबारा से आवेदन कर दिया और अपनी ड्यूटी को अंजाम देते रहे, लेकिन उन्हें दो माह बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिला तो उन्होंने कॉलेज प्रशासन को याद कराया. तब कॉलेज प्रशासन जागा और दोबारा कॉलेज की ओर से 25 संविदा चिकित्सकों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाने की संस्तुति प्रदेश सरकार को भेजी. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय अग्रवाल के अनुसार जल्दी ही चिकित्सकों की मंज़ूरी आ जाएगी जिससे वो कॉलेज में काम कर सकेंगे.

प्राधिकरण क़ैदियों की अपील करेगा

उत्तर प्रदेश शासन की पहल पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक कार्ययोजना शुरू की है. क़ैदियों की जेल-अपील अब जेल अधिकारी के स्थान पर जेल में प्राधिकरण द्वारा नामित अधिवक्ता किया करेंगे. इसमें ग्राइंड के साथ ही महत्वपूर्ण क़ानूनी बिंदुओं का समावेश होगा. निर्धन बंदियों को इसका लाभ मिलने की पूरी संभावना है. इस संबंध में सभी ज़िला कारागारों को कारागार मुख्यालय से परिपत्र जारी किया गया है. विधिक सेवा प्राधिकरण ने जेलवार दो अधिवक्ता नामित किए हैं. ये अधिवक्ता जेल में जाकर नियमित रूप से जेल प्रशासन के सहयोग से ग़रीब कैदियों का विवरण एकत्रित करके इनकी अपील तैयार करेंगे, जिसे जेल प्रशासन अपीलीय न्यायालय भेजेगा. जेल के लिए नामित अधिवक्ताओं का भी रिकार्ड जेल प्रशासन तैयार करेगा. ये अधिवक्ता अपील के अलावा अन्य क़ानूनी सलाह भी देंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com